छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **चतुर्थ सत्र**

सोमवार, दिनांक 25 नवम्बर, 2019

(अग्रहायण 04, शक सम्वत् 1941)

[अंक 01]

विधान सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष	डॉ. चरणदास महंत
प्रमुख सचिव	श्री चन्द्रशेखर गंगराड़े

सभापति तालिका

1. श्री सत्यनारायण शर्मा
2. श्री धनेंद्र साहू
3. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
4. श्री मनोज सिंह मण्डावी
5. श्री शिवरतन शर्मा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय राज्यपाल

सुश्री अनुसुईया उइके

मंत्रिमण्डल के सदस्यों की सूची

01.	श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री	सामान्य प्रशासन, वित्त, ऊर्जा, खनिज साधन, जन सम्पर्क, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित ना हो.
02.	श्री टी.एस. सिंहदेव, मंत्री	पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, 20 सूत्रीय कार्यान्वयन, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.)
03.	श्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री	लोक निर्माण, गृह, जेल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन
04.	श्री रविन्द्र चौबे, मंत्री	संसदीय कार्य, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन विकास, मछली पालन, जल संसाधन एवं आयाकट
05.	डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, मंत्री	स्कूल शिक्षा, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, सहकारिता
06.	श्री मोहम्मद अकबर, मंत्री	परिवहन, आवास एवं पर्यावरण, वन, विधि एवं विधायी कार्य
07.	श्री कवासी लखमा, मंत्री	वाणिज्यिक कर (आबकारी), वाणिज्य एवं उद्योग
08.	डॉ.शिवकुमार डहरिया, मंत्री	नगरीय प्रशासन एवं विकास, श्रम
09.	श्री अमरजीत भगत, मंत्री	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, संस्कृति
10.	श्रीमती अनिला भेंडिया, मंत्री	महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण
11.	श्री जयसिंह अग्रवाल, मंत्री	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास,वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक)
12.	श्री गुरू रूद्र कुमार, मंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग
13.	श्री उमेश पटेल, मंत्री	उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सदस्यों की वर्णात्मक सूची
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा क्रमांक सहित)

अ

01.	अजय चन्द्राकर	57-कुरूद
02.	अमरजीत भगत	11-सीतापुर (अ.ज.जा.)
03.	अरूण वोरा	64-दुर्ग शहर
04.	अजीत जोगी	24-मरवाही (अ.ज.जा.)
05.	अनिता योगेंद्र शर्मा, श्रीमती	47-धरसींवा
06.	अनिला भेंडिया, श्रीमती	60-डौंडी लोहारा (अ.ज.जा.)
07.	अंबिका सिंहदेव, श्रीमती	03-बैकुंठपुर
08.	अमितेश शुक्ल	54-राजिम
09.	अनूप नाग	79-अंतागढ़ (अ.ज.जा.)
10.	आशीष कुमार छाबड़ा	69-बेमेतरा

इ

01.	इंद्रशाह मण्डावी	78-मोहला-मानपुर (अ.ज.जा.)
02.	इंदू बंजारे, श्रीमती	38-पामगढ़ (अ.जा.)

उ

01.	उत्तरी गनपत जांगड़े, श्रीमती	17-सारंगढ़ (अ.जा.)
02.	उमेश पटेल	18-खरसिया

क

01.	कवासी लखमा	90-कोन्टा (अ.ज.जा.)
02.	कृष्णमूर्ति बांधी	32-मस्तूरी (अ.जा.)
03.	किस्मत लाल नंद	39-सरायपाली (अ.जा.)
04.	कुलदीप जुनेजा	50-रायपुर नगर उत्तर
05.	कुंवर सिंह निषाद	61-गुण्डरदेही
06.	केशव प्रसाद चन्द्रा	37-जैजेपुर

ख

01	खेलसाय सिंह	04-प्रेमनगर

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ग

01.	गुरू रूद्र कुमार	67-अहिवारा (अ.जा.)
02.	गुरूदयाल सिंह बंजारे	70-नवागढ़ (अ.जा.)
03.	गुलाब कमरो	01-भरतपुर-सोनहत (अ.ज.जा.)

च

01.	चक्रधर सिंह सिदार	15-लैलूंगा (अ.ज.जा.)
02.	चरणदास महंत	35-सक्ती
03.	चंदन कश्यप	84-नारायणपुर (अ.ज.जा.)
04.	चंद्रदेव प्रसाद राय	43-बिलाईगढ़ (अ.जा.)
05.	चिन्तामणी महाराज	08-सामरी (अ.ज.जा.)

छ

01.	छन्नी चंदू साहू, श्रीमती	77-खुज्जी

ज

01.	जयसिंह अग्रवाल	21-कोरबा

ट

01.	टी.एस.सिंहदेव	10-अम्बिकापुर

ड

01.	डमरूधर पुजारी	55-बिन्द्रानवागढ़ (अ.ज.जा.)

त

01.	ताम्रध्वज साहू	63-दुर्ग ग्रामीण

द

01.	दलेश्वर साहू	76-डोंगरगांव
02.	द्वारिकाधीश यादव	41-खल्लारी
03.	देवती कर्मा	88-दंतेवाड़ा (अ.ज.जा.)
04.	देवेंद्र यादव	65-भिलाई नगर
05.	देवेंद्र बहादुर सिंह	40-बसना
06.	देवव्रत सिंह	73-खैरागढ़

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ध

01.	धरमलाल कौशिक	29-बिल्हा
02.	धनेन्द्र साहू	53-अभनपुर
03.	धर्मजीत सिंह	26-लोरमी

न

01.	ननकीराम कंवर	20-रामपुर (अ.ज.जा.)
02.	नारायण चंदेल	34-जांजगीर-चांपा

प

01.	प्रकाश शक्राजीत नायक	16-रायगढ़
02.	प्रमोद कुमार शर्मा	45-बलौदाबाजार
03.	पारसनाथ राजवाड़े	05- भटगांव
04.	प्रीतम राम, डा.	09-लुण्ड्रा (अ.ज.जा.)
05.	पुन्नूलाल मोहले	27-मुंगेली (अ.जा.)
06.	पुरूषोत्तम कंवर	22-कटघोरा
07.	प्रेमसाय सिंह टेकाम, डॉ.	06-प्रतापपुर (अ.ज.जा.)

ब

01.	बृजमोहन अग्रवाल	51-रायपुर नगर(दक्षिण)
02.	बृहस्पत सिंह	07-रामानुजगंज (अ.ज.जा.)

भ

01.	भुनेश्वर शोभाराम बघेल	74-डोंगरगढ़ (अ.जा.)
02.	भूपेश बघेल	62-पाटन

म

01.	ममता चंद्राकर, श्रीमती	71-पण्डरिया
02.	मनोज सिंह मण्डावी	80-भानुप्रतापपुर (अ.ज.जा.)
03.	मोहन मरकाम	83-कोण्डागांव (अ.ज.जा.)
04.	मोहित राम	23-पाली-तानाखार(अ.ज.जा.)
05.	मोहम्मद अकबर	72-कवर्धा

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

य

01.	यू.डी.मिंज	13-कुनकुरी (अ.ज.जा.)

र

01.	रजनीश कुमार सिंह	31-बेलतरा
02.	रंजना डीपेंद्र साहू, श्रीमती	58-धमतरी
03.	राजमन वेंजाम	87-चित्रकोट (अ.ज.जा.)
04.	रमन सिंह, डॉ.	75-राजनांदगांव
05.	रामकुमार यादव	36-चंद्रपुर
06.	रामपुकार सिंह ठाकुर	14-पत्थलगांव (अ.ज.जा.)
07.	रविन्द्र चौबे	68-साजा
08.	रश्मि आशिष सिंह, श्रीमती	28-तखतपुर
09.	रेखचंद जैन	86-जगदलपुर
10.	रेणु अजीत जोगी, डॉ. (श्रीमती)	25-कोटा

ल

01.	लक्ष्मी ध्रुव, डॉ.	56-सिहावा (अ.ज.जा.)
02.	लखेश्वर बघेल	85-बस्तर (अ.ज.जा.)
03.	लालजीत सिंह राठिया	19-धरमजयगढ़ (अ.ज.जा.)

व

01.	विक्रम मण्डावी	89-बीजापुर (अ.ज.जा.)
02.	विनय जायसवाल, डॉ.	02-मनेन्द्रगढ़
03.	विनय कुमार भगत	12-जशपुर (अ.ज.जा.)
04.	विद्यारतन भसीन	66-वैशाली नगर
05.	विकास उपाध्याय	49-रायपुर नगर पश्चिम
06.	विनोद सेवन लाल चंद्राकर	42-महासमुन्द

श

01.	शकुन्तला साहू, सुश्री	44-कसडोल
02.	शिवरतन शर्मा	46-भाटापारा

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

03.	शिवकुमार डहरिया, डॉ.	52-आरंग (अ.जा.)
04.	शिशुपाल सोरी	81-कांकेर (अ.ज.जा.)
05.	शैलेश पाण्डे	30-बिलासपुर

स

01.	सत्यनारायण शर्मा	48-रायपुर ग्रामीण
02.	संतराम नेताम	82-केशकाल (अ.ज.जा.)
03.	संगीता सिन्हा, श्रीमती	59-संजारी बालोद
04.	सौरभ सिंह	33-अकलतरा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनांक 25 नवम्बर, 2019

(अग्रहायण 4, शक् संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई.

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

<u>"राष्ट्रगीत" एवं "राज्यगीत"</u>

अध्यक्ष महोदय :- गुरूवार, दिनांक 21 नवम्बर, 2019 को हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार प्रत्येक सत्र की प्रथम दिवस की कार्यवाही राष्ट्र गीत "वंदे मातरम्" के साथ साथ राज्य गीत "अरपा पइरी के धार" से प्रारंभ होगी । अब राष्ट्र गीत "वंदे मातरम" के साथ-साथ राज्य गीत "अपरा पैरी के धार" होगा। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि राष्ट्र गीत एवं राज्य गीत के लिए कृपा अपने स्थान पंर खड़े हो जाएं ।

श्री अजीत जोगी (मरवाही) :- राज्यगीत, मेरी पार्टी का भी गीत है, दो साल पहले से ।

(राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्" के पश्चात् राज्यगीत "अरपा पइरी के धार" बजाया गया)

श्री अमितेश शुक्ल (राजिम) :- माननीय अध्यक्ष जी मैं दो मिनट लेना चाहूंगा। मेरा इसमें सुझाव है 'वंदे मातरम्" पूरा नहीं बजा, या तो इसे पूरा बजाया जाए या फिर अरपा पैरी के धार को थोड़ा छोटा कर दिया जाए, सिम्बॉलिक बजाया जाए ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- वह शून्यकाल का विषय है, प्रश्नकाल का विषय नहीं है ।

श्री अमितेश शुक्ल :- मैं सुझाव दे रहा हूं भाई ।

श्री शिवरतन शर्मा :- प्रश्नकाल का विषय आपकी अपेक्षा है ।

समय :
11:07 बजे

<u>निधन का उल्लेख</u>

(1) श्रीमती सुषमा स्वराज, भारत की पूर्व विदेश मंत्री

(2) श्री बाबूलाल गौर, मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री

(3) श्री अरूण जेटली, भारत के पूर्व वित्तमंत्री

(4) श्री मालूराम सिंघानिया, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य

अप्रमाणित/पुनरीक्षण के लिये नहीं

(5) डॉ. बंशीलाल महतो, लोक सभा के पूर्व सदस्य
(6) श्री कैलाश जोशी, मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री

अध्यक्ष महोदय :- मुझे सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि भारत की पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज का निधन दिनांक 06 अगस्त, 2019 को, मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर का निधन 21 अगस्त 2019 को, भारत के पूर्व वित्तमंत्री श्री अरूण जेटली जी का निधन 24 अगस्त 2019 को, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री मालूराम सिंघानिया का निधन दिनांक 4 सितम्बर 2019 को, लोक सभा के पूर्व सदस्य डॉ. बंशीलाल महतो का निधन 23 नवम्बर, 2019 को तथा मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी जी का निधन 24 नवम्बर 2019 को हो गया है ।

श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी सन् 1952 को अम्बाला कैंट हरियाणा में हुआ था । आपने बी.ए., एल-एल.बी. तक की शिक्षा प्राप्त की थी । आप सन् 1977 तथा 1987 में हरियाणा विधान सभा के लिए विधायक निर्वाचित हुईं तथा आपने हरियाणा शासन में अनेक विभागों के मंत्री पद को संभाला । आप 3 बार राज्य सभा की सदस्य रही हैं । अनेक प्रमुख समितियों की सभापति रहीं । आप 4 बार लोक सभा की सदस्य निर्वाचित हुईं तथा आपने सूचना एवं प्रसारण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, संसदीय कार्य, विदेश सहित अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रीय मंत्रालयों का दायित्व संभाला । सन् 1998 में आप दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं । आप प्रखर एवं कुशल वक्ता तथा दल से ऊपर उठकर रिश्तों को सहेजने वाली नेत्री मानी जाती रहीं । आपकी अर्थव्यवस्था, रक्षा और सूचना के क्षेत्र में विशेष अभिरूचि थी । आपके निधन से देश ने एक अनुभवी राजनीतिज्ञ, एक प्रशासक तथा कुशल वक्ता को खो दिया है ।

श्री बाबूलाल गौर जी का जन्म 2 जून सन् 1929 को उत्तरप्रदेश के ग्राम नागौर, जिला प्रतापगढ़ में हुआ था । आपने बी.ए., एल-एल.बी. तक की शिक्षा प्राप्त की । आप छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े रहे । आप भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक थे । आप आप अनेक श्रमिक आंदोलनों से जुड़े तथा ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स में अपनी पकड़ बनाई । आप आपातकाल के दौरान जेल भी गए। आप प्रथम बार सन् 1974 में मध्यप्रदेश की पांचवी सभा के लिए विधायक निर्वाचित हुए, तत्पश्चात् आप भोपाल के गोविंदपुरा विधान सभा क्षेत्र से लगातार 10 बार विधायक निर्वाचित होते रहे । आपने मध्यप्रदेश की विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई । आप मध्यप्रदेश शासन के अनेक महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे । आप 2004 में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने । आपकी सामाजिक कार्यों में अभिरूचि रही । आपके निधन से एक अनुभवी राजनीतिज्ञ तथा एक समाजसेवी को हमने खो दिया है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अरूण जेटली जी का जन्म 28 दिसम्बर, सन् 1952 को नई दिल्ली में हुआ था । आपने बी.कॉम., एल-एल.बी., तक की शिक्षा प्राप्त की । आप छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे । आपका मुख्य व्यवसाय वकालत था । आप मीसा के तहत् जेल भी गए । आप 4 बार राज्य सभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा आपने राज्य सभा के नेता प्रतिपक्ष का दायित्व भी संभाला । आपने वित्त, रक्षा, वाणिज्य एवं उद्योग जैसे अनेक महत्वपूर्ण केन्द्रीय मंत्रालयों में मंत्री पद का दायित्व भी संभाला । आप कानूनी मामलों के विशेषज्ञ माने जाते रहे हैं । आपने कानूनी तथा सामाजिक मामलों के लेख एवं किताबें लिखी हैं । साहित्य एवं खेल के क्षेत्र में आपकी विशेष अभिरूचि थी । आपके निधन से देश ने एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, एक कानूनविद् तथा एक लेखक को खो दिया है ।

श्री मालूराम सिंघानिया, सन् 1930 में सिंघाना जिला झुंझनू, राजस्थान में जन्मे थे । आपकी हाईस्कूल तक की शिक्षा दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुई, आप प्रारंभ से ही राजनीति में सक्रिय रहे । आप भारतीय जनसंघ तथा भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे । आप भारतीय जनता पार्टी की टिकिट पर 1967 में दुर्ग जिले के विरेन्द्र नगर विधान सभा क्षेत्र से अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के लिए विधायक निर्वाचित हुए । आपने अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग उठाई थी । आप अपने क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सतत् प्रयत्नशील रहे । आपकी संस्कृति, अध्ययन, धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में विशेष रूचि रही। आपके निधन से प्रदेश ने एक समाजसेवी तथा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ को खो दिया है।

डॉ. बंशीलाल महतो का जन्म 30 जून सन् 1940 को सलीहाभटा, जिला-कोरबा में हुआ था। आपने बी.ए.एम.एस. आयुर्वेदाचार्य की शिक्षा प्राप्त की थी। आप कृषक परिवार से संबंधित थे। आपका मुख्य व्यवसाय चिकित्सा था। आप सन् 2014 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर सोलहवीं लोकसभा के लिए संसदीय क्षेत्र कोरबा से सांसद निर्वाचित हुए। आप लोकसभा की कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति, परामर्शदात्री समिति, रसायन और उर्वरक समिति के सदस्य रहे। कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आपकी विशेष अभिरूचि रही। आप अपने क्षेत्र के विकास के लिये हमेशा प्रयत्नशील रहे। आपके निधन से देश ने एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा एक समाजसेवी को खो दिया है।

श्री कैलाश जोशी जी का जन्म 14 जुलाई सन् 1929 को हाटपीपल्या, तहसील-बागली, जिला-देवास में हुआ था। आपका मुख्य व्यवसाय कृषि था। आप सन् 1955 में हाटपीपल्या नगर-पालिका के अध्यक्ष बने। आप सन् 1962 से निरंतर बागली विधान सभा मध्यप्रदेश विधान सभा के लिये विधायक निर्वाचित हुए। आप आपातकाल के दौरान मीसा के तहत बंदी बनाये गये। आप मध्यप्रदेश विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। आपने मध्यप्रदेश शासन के अनेक महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री का दायित्व भी

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

संभाला। आप सन् 1977 में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आप सन् 2004 तथा 2009 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर भोपाल संसदीय क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए। भारतीय विधाओं के अध्ययन, अध्यात्म तथा सामाजिक कार्यों में आपकी विशेष अभिरूचि थी। आपके निधन से हमने एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, ओजस्वी वक्ता तथा समाजसेवी को खो दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्री :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सत्र के बीच में हमने बड़े राजनेताओं को खोया है। वे देश और प्रदेश की राजनीति में बड़े प्रभावशाली रहे हैं। स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने अपनी पहचान एक दृढ़ महिला के रूप में बनायी। वे अपनी भाषायी एवं कानूनी विद्वता के लिये प्रसिद्ध रही हैं। उनकी हिन्दी अंग्रेजी के साथ-साथ संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, हरियाणवी और कन्नड़ भाषाओं में अच्छी पकड़ थी। वे प्रखर वक्ता और कुशल प्रशासक भी थीं। श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह भारत की विदेश मंत्री भी बनीं। किसी राजनीतिक दल के महिला प्रवक्ता के रूप में भी उनको गौरव हासिल है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने विभिन्न विभागों का दायित्व भी संभाला, जिसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्री, दूरसंचार मंत्री एवं विदेश मंत्री के रूप में कार्य करते हुए देश को अनेक उपलब्धियां दिलायीं। वे 15वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनीं। उन्होंने अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन भी किया। वे सन् 1977 में अंबाला छावनी में पहली बार विधायक बनीं। उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में अनेक भूमिकाओं में देश के लिए अपना योगदान दिया। उनका जन्म 14 फरवरी, 1952 को हुआ और 6 अगस्त, 2019 को निधन हो गया। सुषमा स्वराज जी के निधन से भारतीय राजनीति की बड़ी क्षति हुई है। मैं सदन के माध्यम से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी के साथ हम लोग मध्यप्रदेश विधान सभा में सदस्य के रूप में बैठने का और उन्हें सुनने का हमें अवसर मिला। हम उन्हें एक आंदोलनकारी नेता के रूप में जानते हैं। वे श्रमिकों के पक्ष में हमेशा लड़ते रहे। वे 23 अगस्त, 2004 से 29 नवंबर, 2005 तक मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में रहे। उन्होंने विभिन्न विभागों में भी काम किया। गृह, विधि एवं विधायी, नगरीय प्रशासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, श्रम, भोपाल गैस राहत, पुनर्वास, उद्योग, वाणिज्यिक कर, रोजगार, सार्वजनिक उपक्रम ऐसे अनेक विभागों का दायित्व संभाला । वे पहली बार भोपाल दक्षिण से विधान सभा के सदस्य के रूप में रहे। गोविन्दपुरा से लगातार 7 बार विधायक रहे। अध्यक्ष महोदय, बाबूलाल गौर एक सहज, सरल और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। वे बहुत ही नीचे से उठकर ऊपर आये थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अरूण जेटली जी विद्वतापूर्ण भागीदारी तथा हस्तक्षेपों से भारतीय संसद की चर्चा प्रक्रिया को समृद्ध किया है। संसदीय चर्चाओं में उनका अमूल्य योगदान रहा है। जेटली जी, एक कुशल रणनीतिकार और कानूनविद थे। उनके जाने से निश्चित रूप से देश को एक अपूरणीय क्षति हुई है। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री मालूराम सिंघानिया जी हमारे छत्तीसगढ़ के ही रहे हैं और मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में बहुत ही सहज, सरल और मिलनसार व्यक्तित्व थे। साथ ही गौ सेवा के क्षेत्र में बड़ा काम किया है। मैं उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री बंशीलाल महतो जी जो कोरबा से सांसद के रूप में रहे। वे हमेशा किसानों और आदिवासियों के लिए काम करते रहे। पिछले दिनों उनसे दो बार भेंट भी हुई थीं। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि वे हम लोगों को असमय छोड़कर चले जायेंगे। उनके जाने से अपूरणीय क्षति हुई है। मैं उनसे पूछा करता था कि डाक्टर साहब, अब आप क्या करेंगे ? तब वे कहते थे कि अब मैं अपनी डिस्पेंसरी में ही बैठूंगा और जनसेवा ही मेरा मुख्य ध्येय है और उसे निरंतर करते रहूंगा। लेकिन अचानक उनके निधन की सूचना आई, जो हम सबके लिए एक दु:खद समाचार था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय कैलाश जोशी जी के साथ भी हम लोगों को मध्यप्रदेश की विधान सभा में बैठने का अवसर मिला था। हम लोगों ने उनके अनेक उद्बोधन विधान सभा में और नये विधायकों के उद्बोधन कार्यक्रम में सुनने का अवसर मिला है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने मध्यप्रदेश के नौवें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। साथ ही विभिन्न विभागों में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे व्यक्तित्व के जाने से निश्चित रूप से समाज को एक अपूरणीय क्षति होती है। उनका जन्म 14 जुलाई, 1929 को देवास जिले के हाटपिपलिया में हुआ था। उनके राजनीतिक जीवन की शुरूआत हाटपिपलिया के नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में हुई। वे बागली विधानसभा से 7 बार विधायक रहे। सन् 1972 से 1977 तक मध्यप्रदेश विधानसभा के विपक्ष के नेता के रूप में उनका योगदान रहा है। सन् 2004 से 2014 तक भोपाल से सांसद भी रहे। उनका लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी महान विभूतियों को स्मरण करते हुए देश और प्रदेश की राजनीति में उनका योगदान रहा है, उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता है। मैं सभी को विन्रम श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके परिवारों को दु:ख सहने की क्षमता मिले, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सुषमा स्वराज जी का छत्तीसगढ़ से बहुत निकट का नाता रहा है। उनका राजनीतिक, सामाजिक और उनके जीवन के विभिन्न आयाम रहे हैं। आज हम सब लोग उनको स्मरण कर रहे हैं। सुषमा स्वराज जी एक प्रखर वक्ता थे। मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में जब भी उनका भाषण हुआ तो सुषमा स्वराज जी क्या बोल

रही हैं, उनको सुनने के लिए सब बेतात रहते थे। वे सबसे कम उम्र में हरियाणा सरकार में मंत्री के रूप में दायित्व संभाला। जे0पी0 आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उस समय उन परिस्थितियों में सुषमा जी, जे0पी0 से प्रभावित होकर सामाजिक और राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ सूचना एवं प्रसारण और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी सम्हाला । उनके कार्यकाल में बहुत सारे राज्यों में एम्स की स्थापना हुई तथा हमारे छत्तीसगढ़ में एम्स दिखाई दे रहा है, वह सुषमा जी की ही देन है । उनकी सोच, समाज के प्रति उनकी दूरदर्शिता इतनी अधिक थी कि आने वाले समय में इसकी क्या उपयोगिता है, जिसका समाज को लाभ मिले । जब वे सूचना एवं प्रसारण मंत्री थीं तो ये जो सिने जगत को उद्योग का दर्जा दिये जाने का काम सुषमा स्वराज जी के कार्यकाल में हुआ और उसको सिने जगत को उद्योग का दर्जा मिला । उन्होंने दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनकी जो स्वीकार्यता है, वह सभी दलों में रही है । जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब सुषमा जी का भाषण हुआ, उसके बाद में मनमोहन सिंह जी को बोलना था तो मनमोहन सिंह जी इस बात को स्वीकार करते थे कि सुषमा जी, आपके भाषण की जो कला है, शायद में वहां तक न पहुंच पाऊं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ और जब विभिन्न नदियों में भस्म को प्रवाहित करना था तो मैं दिल्ली गया था । वह कलश सुषमा जी के हाथों से मुझे प्रदान किया गया । जब मैं श्रद्धांजलि सभा में दिल्ली में उपस्थित था तो सभी दल के लोग वहां पर उपस्थित थे और सभी लोगों ने दलगत राजनीति से हटकर उनकी क्या भूमिका रही है, उसके संबंध में अपना अनुभव बता रहे थे । कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा जी ने कहा कि मेरी मां की तबीयत खराब थी । मैंने सुषमा जी को फोन लगाया और कहा कि एम्स में बैड की व्यवस्था हो जाएगी क्या? सुषमा जी बोलीं कि आनंद भाई, आप चिन्ता मत करिए, मैं प्रयास करती हूं । जब आनंद जी 5 बजे एम्स अस्पताल में पहुंचे तो सुषमा जी आनंद जी की मां के हाथ को अपने हाथ में रखकर बैठी हुई थीं, उनके हाथों को सहला रही थी । आनंद जी बोले कि मैं भाव विभोर हो गया, मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा कि मेरी मां हैं, मैं बाद में पहुंचा, सुषमा जी पहले पहुंच गईं और जब मैंने कहा कि सुषमा जी, मैंने तो बेड के लिए कहा था, आपको आने की क्या आवश्यकता थी ? तो सुषमा जी ने कहा कि क्या यह केवल आपकी मां है, मेरी मां नहीं है, यह अधिकार मुझसे क्यों छीन रहे हो ? वहां पर अलग-अलग दलों के लोगों ने जो भाव विभोर श्रद्धांजलि दी, उनका नाता दलगत राजनीति से हटकर था । विदेश मंत्री के रूप में उनकी भूमिका ऐसी रही कि हम उसकी जितनी सराहना करें, वह कम है कि कहां पाकिस्तान, कहां ईराक में भारत के जो लोग बंधक बनाए हुए थे, उनको भारत में वापस लाना, परिवार के साथ में उनको मिलाना, उस गूंगी लड़की को लेकर दिल्ली वापस आना, उनके परिवार के साथ मिलाना और ऐसी कई घटनाएं जहां विदेशों में मृत्यु हो गई तो सकुशल भारत पहुंचाने

में उनकी क्या भूमिका हो सकती है, उनकी क्या मदद हो सकती है ? मुझे लगता है कि विदेश मंत्री के रूप में जो सुषमा जी की भूमिका रही है, वह निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जोड़ने, उनके साथ में मैत्री संबंध स्थापित करने और उसके साथ में जो भारत के लोग बंधक बनाए हुए हैं, उनको वापस लाना विदेश मंत्री के रूप में हम कह सकते हैं कि उनकी स्वीकारोक्ति और उनकी उपलब्धियां हम सबके सामने में है । आज हम लोग सुषमा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, हमारी स्मृति में जो वर्णित घटनाएं हैं, उनको लाने के लिए हम लोग यहां नमन कर रहे हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री के रूप में, साथ ही विभिन्न दायित्वों का निर्वहन और उनके साथ में हम सब लोगों को उनके साथ पार्टी में काम करने का अवसर भी मिला । आज हमारे लिए वे प्रेरणास्त्रोत हैं । हम लोगों ने उनको पार्टी के प्रवक्ता के रूप में देखा है । लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हमने देखा है और जब शासन में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है तो कहां तक जाकर लोगों की मदद कर सकते हैं, वास्तव में सुषमा जी में ये सारी बातें कूट-कूटकर भरी हुई थीं । मुझे लगता है कि जहां तक महिलाओं की जो राजनीति में जागरूकता और एक सशक्त नेतृत्व, महिला सशक्तीकरण की बात आती है, सुषमा स्वराज जी से प्रारंभ हुई है । यहां पर हम उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं । बाबूलाल गौर जी मध्यप्रदेश में मंत्रियों के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुये मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आसीन हुये । बाबूलाल गौर जी की जो पृष्ठभूमि है, भारतीय मजदूर संघ की रही है । भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक दंतोपन ठेंगड़ी जी, उनके साथ में यदि कोई काम किये हैं तो बाबूलाल गौर जी उसमें से एक रहे हैं । जिस प्रकार से अपने संगठन में दायित्वों का निर्वहन करते हुये वहां पर मंत्री के रूप में, मध्यप्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है, वह सराहनीय है । बाबूलाल गौर जी गोवा मुक्ति आंदोलन है, उस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और स्वतंत्रता सेनानी का भी उनको सम्मान मिला । बाबूलाल गौर जी ने मध्यप्रदेश में बुलडोजर मंत्री के रूप में पहचान बनाई । जो सौंदर्यीकरण करना है, सड़कों का चौड़ीकरण करना है, उसके लिए जो तोड़ने की बात है तो आने वाली स्थिति क्या होगी, उस समय बहुत से लोग संशय में थे । बाबूलाल गौर जी ने कहा कि अगर आप अच्छे काम करेंगे, नीयत आपकी अच्छी है, तो लोग आपके साथ चलेंगे । उसके बाद 59,000 से लेकर 64,000 तक लीड के साथ में बाबूलाल गौर जी जीते हैं, हम उन्हें राजनीति में अपराजेय योद्धा कह सकते हैं, बाबूलाल गौर जी को हम अजातशत्रु कह सकते हैं, बाबूलाल गौर जी आज हमारे बीच में नहीं है, आपके माध्मय से विधानसभा में हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं ।

अरूण जेटली जी के बारे में हम सब जानते हैं । एक प्रखर वक्ता के रूप में न केवल लोक सभा में, न केवल राज्य सभा में, बल्कि ऐसे कई अवसर आये हैं, उनको जब निराकरण करनी है तो राष्ट्रीय

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मंचों पर जो दायित्व दिया गया है, अरूण जेटली जी ने उसका निर्वहन किया है, उसको प्रतिपादित किया है । अरूण जेटली जी लॉ किये हैं । उनकी वकालत का सब लोहा मानते हैं । उनके वकालत के बारे में न केवल सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि देश के ऐसे अनेक उच्च न्यायालय है, जिनमें अरूण जेटली जी को जाने का अवसर मिला है और उनको सुनने का अवसर भी प्राप्त हुआ है । अरूण जेटली जी, सूचना प्रसारण मंत्री, उसके साथ ही कानून मंत्री, उनके साथ में राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में, प्रवक्ता के रूप में विभिन्न दायित्वों का सरकार और संगठन में निर्वहन किया है । आज जब उन्हें छत्तीसगढ़ के विधान सभा में श्रद्धांजलि दे रहे हैं, निश्चित रूप से इस बात को मैं रखना चाहूंगा कि उनसे जो जुड़ी हुई बातें हैं, जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, 1 नवम्बर को जब शपथ की बात आई, उस समय लालकृष्ण आडवानी जी और अरूण जेटली जी साथ में आये थे । रात को शपथ हुआ, जोगी जी हमारे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिये, शपथ लेने के बाद में दूसरे दिन सुबह, मैं उस समय विधायक था, अरूण जेटली जी के साथ में बिलासपुर हम लोग गये और नार्मल स्कूल जो बिलासपुर में है, वह हाई कोर्ट के रूप में पहली बार उसको मान्यता मिली । अरूण जेटली जी, वहां पर उपस्थित थे । हमारे हाई कोर्ट के जज के रूप में, प्रथम हाई कोर्ट के जज, वहां पर कार्यभार संभाले । छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में दिल्ली में पार्लियामेंट में जो उनकी भूमिका, और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के प्रत्यक्ष साक्षी रहे हैं, जिनके सामने शपथ हुआ और हाई कोर्ट की स्थापना हुई । ऐसे अरूण जी जेटली रहे हैं । छत्तीसगढ़ के प्रति उनका जो लगाव, उसके बाद अनेक बार छत्तीसगढ़ में उनका आगमन हुआ, जब हमारे राज्योत्सव के कार्यक्रम हुये, उस राज्योत्सव के कार्यक्रम में अरूण जेटली जी का यहां पर आगमन हुआ था । छोटे राज्य की जो कल्पना है, छोटे राज्य बनाने के बाद में लोगों के मत में विभिन्नता रही है, मतैक्य रहे हैं । जेटली जी ने प्रतिपादित किया कि छोटे राज्य बनाने के बाद लोगों के मत में विभिन्नता रही है, मतैक्य रहे हैं। श्री जेटली जी ने प्रतिपादित किया है कि छोटे राज्य की कल्पना को जो स्वीकार किया गया तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को उसका लाभ मिला है जो आज छत्तीसगढ़ का परिदृश्य दिखाई दे रहा है। उनके जीवन का जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। उनके कार्यों को हमने संगठन में और प्रतिपक्ष में नजदीक से देखा है और उसके साथ ही साथ सरकार में उनकी भूमिका को भी हम सबने देखा है। जब छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद राजधानी का निर्माण हो रहा था उस समय यह बात आई कि रायपुर में राजधानी और न्यायधानी बननी चाहिए तो छत्तीसगढ़ के लोगों में मतभिन्नता हुई कि इसे अलग-अलग जगहों में होना चाहिए। उस समय वकीलों और हम सब लोगों से मिल करके यह मार्ग प्रशस्त हुआ कि इस पर विस्तार से विचार करें और किसी के साथ अन्याय न हो। उस समय उसमें बहुत सारी चीजों को जोड़कर रखे थे जो कि संभव नहीं हो पाया अन्यथा हम लोग चाहते थे कि अन्य जो जिले हैं उनको भी प्रमुखता से स्थान मिले। किन्तु आज मैं यह कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

की स्थापना, विकास, हाईकोर्ट इस सबमें अरूण जेटली जी की भूमिका रही है। आज इस अवसर पर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको स्मरण करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, श्री मालूराम सिंघानिया जी के बारे में हम सबको मालूम है कि वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना का संचार था और जिस प्रकार से उनकी कार्यपद्धति रही है, बाद में वह विधायक बने और विधायक बनने के बाद अपने कर्तव्यों का जो उन्होंने निर्वहन किया, पूरे क्षेत्र, समाज के लिए तथा वह एक अंतर्राज्यीय व्यक्तित्व थे जिन्होंने अनेक प्रदेशों में जाकर काम किया है और अपनी छाप छोड़ी है। श्री मालूराम सिंघानिया जी अटल जी के बहुत करीबी माने जाते थे और अटल जी के सहयोगी के रूप में उनकी भूमिका रही है। आज इस अवसर पर हम उनको भी श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं।

डॉ. बंशीलाल महतो जी के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह इतनी जल्दी हम सबको छोड़कर चले जायेंगे। कुछ दिन पहले ही हम सब लोग बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। हम सब लोगों ने बंशीलाल महतो जी का संघर्ष देखा है, सांसद के रूप में काम करते हुए देखा है और बंशीलाल जी को हम एक कुशल चिकित्सक कह सकते हैं। उन्होंने आयुर्वेदाचार्य के रूप में जो डिग्री हासिल की, उनके क्लिनिक में आप जब भी जाते, लाईन में लोगों की भीड़ लगे हुए देखते। वह आजीवन एक सफल चिकित्सक रहे हैं। अभी सांसद बनने के बाद और सांसद से पृथक होने के बाद भी वह अपने व्यवसाय से कभी पृथक नहीं हुए। उनका कहना था कि जो हुनर है और जो भगवान ने दिया है उसका हमेशा जनता के बीच उपयोग हो। मुझे लगता है कि उन्होंने कभी किसी से फीस नहीं मांगी और लोगों ने जो दिया उसे उन्होंने स्वीकार किया। उनकी सरलता और सहजता को हम सब लोगों ने देखा है और मुझे लगता है कि अध्यक्ष जी और करीब से उनको देखे हैं। राजनीति में चुनाव होते हैं, उतार-चढ़ाव आते हैं लेकिन मैंने कटुता का भाव कभी उनके मन में नहीं देखा। हार गये तो भी स्वीकार किये, जीते तो भी स्वीकार किये और सहजता जो एक अच्छे जनप्रतिनिधि में होनी चाहिए वह सारे गुण उनमें मौजूद थे। ऐसे डॉ. बंशीलाल महतो जी को मैं इस अवसर पर श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूं।

श्री कैलाश जोशी जी को आप और हम सब लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है। जिस प्रकार से बागली से वह लगातार विधायक के रूप में काम किए, उद्योग मंत्री रहे और उसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री के रूप में, लोकसभा सदस्य के रूप में और जितना मेरा जीवन है उससे ज्यादा उनका राजनीतिक जीवन रहा है। एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में बहुत लंबे समय तक कैलाश जोशी जी को काम करते हुए हम सब लोगों ने देखा है। आज यदि राजनीति में संत की किसी को संज्ञा दी जाए तो मुझे लगता है कि कैलाश जोशी जी आज के राजनीति के संत हैं कि उनका न काहू से बैर था, जीवन में किसी के साथ उनकी कभी कटुता दिखाई नहीं दी। उनकी सादगी, सरलता और राजनीतिक क्षेत्र में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रहकर इतने लंबे वर्षों तक उनके जीवन में किसी प्रकार का एक दाग न लगे, यह कैलाश जोशी जी एक उदाहरण हैं कि इतनी लंबी राजनीति में काम करते हुए निर्लिप्त भाव से अपने आप को अलग करके राजनीतिक दल से उपर उठ करके, दलगत राजनीति से बाहर हो करके जो काम करना, उनका जो स्वभाव और न केवल अपने दल के लिए बल्कि बाहर के लिए भी उतना ही चहेता कैलाश जोशी जी रहे हैं। आज हम इस पीढ़ी के लिए खास करके कि लंबे राजनीति में जिनको काम करना है। निश्चित रूप से कैशाल जोशी जी का जो राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, यह हम सब के लिए उनका एक प्रेरणादायी जीवन रहा है और आज ऐसे अवसर पर हमारे बीच में नहीं हैं, मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- श्री अजीत जोगी जी।

श्री अजीत जोगी (मरवाही) :- अध्यक्ष जी, धन्यवाद। यह दुखद संयोग है कि हमारे इस सत्र का श्रीगणेश छै महान विभूतियों को श्रद्धांजलि देने से हो रहा है। सुषमा स्वराज जी के बारे में विपक्ष के नेता ने बहुत सी बातें कही है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं उनके साथ लंबे समय तक राज्यसभा और लोकसभा में रहा हूं। उनके भाषण देने की शैली, मैं सोचता हूं हमारी पीढ़ी में अटल जी के बाद यदि कोई इतनी अच्छी वक्ता थी तो वह सुषमा स्वराज जी ही थी। मैं विस्तार से उनके अपने संबंधों को दोहराना नहीं चाहता। किन्तु केवल एक बात कहूंगा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो छत्तीसगढ़ में एम्स की स्थापना के लिए उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि अजीत अगर जमीन दोगे तो मैं एम्स तुम्हारे यहां खोलूंगी। मैंने कहा जमीन क्या, मैं आपको पूरा अस्पताल दे रहा हूं तो उन्हें बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। मैंने बताया कि टी.बी. अस्पताल की पूरी जमीन उपलब्ध है। हम सबको इस बात का गौरव है कि दिल्ली के बाद जितने एम्स स्थापित हुए, उनमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ का एम्स उनके कारण हमारा टी.बी. भी अस्पताल स्थापित हुआ और इस नये स्वरूप में है। मैं सोचता हूं, यह एम्स एक स्मारक के रूप में सुषमा जी को सदैव याद करने वाला भवन बना रहेगा। प्रवक्ता के रूप में, मैं कांग्रेस का और वह भाजपा की, हम लोग एक दूसरे के सामने बहस करते थे पर उसके पहले और उसके बाद भाई और बहन जैसा हमारा रिश्ता रहता था। कभी बहस के बाद, डिबेट के बाद मैं उनके घर चाय पीने जाता था और कभी वह मेरे घर चाय पीने आती थी। ये उनकी सहजता का और सबसे बड़ी विशेषता उनकी यह थी कि वे हर किसी से पारिवारिक संबंध बना लेती थी। जैसा अभी उल्लेख किया गया।

अध्यक्ष महोदय, श्री बाबूलाल गौर जी, मैं भोपाल में पढ़ा हूं, इसलिए एक मजदूर नेता से उठकर उनको मुख्यमंत्री तक बढ़ते हुए मैंने देखा है। सात-सात बार में अपनी ही रिकार्ड को तोड़ते हुए अपनी विधानसभा से उन्हें निर्वाचित होते देखा। वे अजेय थे, एक छोटी सी बात उनकी सहृदयता के बारे में बताता हूं। जब वे मुख्यमंत्री थे तो किसी ने मेरी आवाज बनाकर उन्हें फोन किया और कहा कि मुझे,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

यानी अजीत जोगी को 50 लाख रूपये की तत्काल भोपाल में आवश्यकता है। वे ठग हमारे कवर्धा जिले का था और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं, उसको 50 लाख रूपये दे दिया। एक दिन सेंट्रल हाल में मुलाकात हुई तो कहा भाई साहब आपका काम कर दिया था, तो मैंने कहा क्या काम ? तो उन्होंने बताया 50 लाख रूपये आपने फोन किया था तो मैंने दे दिया। लंबी कहानी नहीं बताना चाहता, कैसे आगे कुछ हुआ। पर यह एक उदाहरण है कि यदि उनका कोई मित्र संकट में था तो उन्होंने सत्यापन करने की भी आवश्यकता नहीं समझी और 50 लाख रूपये दे दिये। सच में वह एक अजेय विधायक थे और अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भोपाल को नया स्वरूप देने में बहुत बड़ा योगदान दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री अरूण जेटली जी के साथ भी मुझे दिल्ली में एक लम्बा समय व्यतीत करने का अवसर मिला। वह अंग्रेजी और हिन्दी में बहुत ही अच्छा बोलते थे। वे एक अच्छे वकील होने के नाते, वैज्ञानिक तरीके से तर्क देकर अपनी बातें रखते थे और सामने वाले को निरूत्तर कर देते थे। राजनीति, वकालत के अतिरिक्त खेल के क्षेत्र में विशेषकर क्रिकेट में उनको बहुत अधिक रूचि थी और यह एक अच्छी बात है। दिल्ली का जो क्रिकेट का फिरोजशाह कोटला मैदान था, जहां वे खुद अनेक बार गये थे आज उनके नाम से उसका नामकरण हो गया। इसी संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि श्रीमती सुषमा स्वराज जी, श्री अरूण जेटली जी और गोवा के मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री पणीकर जी भा.ज.पा. की प्रथम पंक्ति के 3 नेता एक के बाद एक चले गये और ये भा.ज.पा. की शक्ति का परिचायक है कि इतनी जल्दी-जल्दी 3 नेताओं के जाने के बाद भी, आज भी वह पार्टी मजबूत बनी हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री मालूराम सिंघानिया जी ने विशेषकर गौ सेवा के क्षेत्र में जो काम किया, उसके लिए जानना और स्मरण करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कैलाश जोशी जी से मेरा बहुत लम्बा संबंध इसलिए रहा कि जब 6 साल से ज्यादा मैं इंदौर का कलेक्टर था। वे देवास बागली से थे, वे अक्सर इंदौर में ही रहा करते थे और कभी किसी निजी कार्य के लिए नहीं, पर जब भी आये तो उन्होंने सार्वजनिक हित के कार्य के लिए बात की। बागली में एक बहुत बड़ा आदिवासी क्षेत्र है और वे उन आदिवासियों में इतने लोकप्रिय थे कि कभी उनको उन आदिवासियों के वोट के कारण कोई हरा नहीं पाया। संभवत: वे 7 बार बागली से चुनाव जीते थे। मैंने खुद प्रयास किया। उस समय मैं कांग्रेस में था, बागली से जो हमारा उम्मीद्वार था, उसने बड़ा हट किया कि आप आदिवासी क्षेत्र में आईये, आपका असर पड़ेगा। मैंने उनके खिलाफ 2-3 अच्छी मिटिंग्स लीं। पर परिणाम यह आया कि उन्हीं को बागली के आदिवासियों के सारे वोट मिले और उसका मुख्य कारण यह था कि उन्होंने आदिवासियों को अपना परिवार बना लिया था। एक-एक आदिवासी

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

परिवार को बाई नेम जानते थे, उनकी आवश्यकताओं को जानते थे और उन्होंने आदिवासियों के लिए विशेषकर जो काम किया, उसके लिए उनको स्मरण किया जाता रहेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नाम छूट गया। डॉ. बंशीलाल महतो जी छत्तीसगढिया विचारधारा से ओतप्रोत थे और हमारी, आपकी, मुख्यमंत्री जी की और हम सबकी वही भावना होने के कारण वे हम सब के नजदीक थे। वे बड़ी मीठी छत्तीसगढ़ी बोलते थे। उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि वे जीवन में एक बार सांसद बने। जीवन के अंतिम पड़ाव में वे सांसद भी बने और उन्होंने कोरबा, मेरे मरवारी क्षेत्र के लिए, जब मैंने उनको जैसा काम कहा, वह करने में बड़ा सहयोग किया। इन्हीं शब्दों के साथ ऐसे छत्तीसगढिया महान विभूति तथा इन 6 विभूतियों को मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो सत्र के अंतराल में हमने राष्ट्रीय स्तर के 6 वरिष्ठ नेताओं को खोया है। श्रीमती सुषमा स्वराज जी, अरूण जेटली जी जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। इस दौरान हमने दो मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी, कैलाश जोशी जी को खोया है। छत्तीसगढ़ के हमारे पूर्व सांसद डॉ. बंशीलाल महतो जी और मालूराम सिंघानिया जी जिनकी विधायक के नाते भूमिका थी, उनको इस बीच खोया है। निश्चित रूप से मैं आपकी और सदन की भावनाओं से अपने आपको संबद्ध करता हूं। सुषमा स्वराज जी किसी राजनीतिक दल की पहली महिला राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में उन्होंने पहचान बनाई, हरियाणा में जनता पार्टी की सबसे कम उम्र की प्रभारी रहीं, हरियाणा सरकार में सबसे कम उम्र की केबिनेट मंत्री रहीं, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री का रिकार्ड और भारतीय जनता पार्टी की पहली केबिनेट मंत्री बनीं। अकेली महिला सांसद जिन्हें Outstanding Parliamentarian Award मिला और मोदी सरकार में पूर्णकालिक महिला मंत्री के रूप में, 2009 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। निश्चित रूप से उनका जाना पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बाबूलाल गौर जी के साथ लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला। उनकी संगठन और सरकार में दोनो भूमिका देखा। लगातार 9 बार विधानसभा में विधायक की भूमिका, मुख्यमंत्री की भूमिका और उसके साथ नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री के रूप में उन्होंने जो छाप छोड़ी, निश्चित रूप से हम सब उन्हें याद करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अरूण जेटली जी की भारतीय संसद में राज्यसभा में विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में उनकी भूमिका रही। उन्होंने अपना जीवन विद्यार्थी परिषद से शुरू किया और विद्यार्थी परिषद के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष चुने गये और उसके साथ आपातकाल में उनको 19 महीने जेल में रहना पड़ा। उनका छत्तीसगढ़ से विशेष

लगाव था, छत्तीसगढ़ के निर्माण में उनकी भूमिका रही। जय प्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़कर उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निश्चित रूप से वरिष्ठ नेता के रूप में आज हम उन्हें श्रद्धापूर्वक याद करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मालूराम सिंघानिया जी, थानखम्हरिया से थे, वह हमारे पड़ोसी रहे हैं। जनसंघ से लेकर राजराज्य परिषद में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए और देश का कोई बड़ा आंदोलन जो गौहत्या, गौ के संरक्षण के लिए हो, मालूराम सिंघानिया जी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। वह अपना आखिरी समय बनारस में पूजापाठ में निकाले। स्वामी कल्पात्री जी के निकटतम शिष्यों में एक मालूराम सिंघानिया जी की भूमिका रही है। हमारे अनन्य मित्र जिनकी भूमिका छत्तीसगढ़ के विधानसभा में और लोकसभा में भूमिका रही, उन्हें हम सांसद के रूप में याद करते हैं। माननीय बाबूलाल गौर जी और कैलाश जोशी को याद करते समय छत्तीसगढ़ की वह स्मृति और मुख्यमंत्री के नाते उनकी स्मृति के साथ-साथ, कैलाश जोशी जी का जो जीवन रहा, निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जो पूरा जीवन ईमानदारी, निष्ठा के साथ काम करते रहे और राजनीतिक जीवन में लगातार एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व करना, पार्षद की भूमिका से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करना, निश्चित रूप से हम सबके लिए कैलाश जोशी जी एक आदर्श के रूप में रहे और छत्तीसगढ़ से लगातार उनका संपर्क बना रहा। उनको हम याद करते हैं। मैं सभी नेताओं के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूं और ईश्वर उनके परिवार को इस कष्ट को सहने की शक्ति दे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम जिन 6 मूर्धन्य नेताओं को श्रद्धांजलि दे रहे हैं । शायद, किसी एक सत्र में इतने राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तरीय नेताओं को श्रद्धांजलि देना पड़ रहा है, यह हम सबके लिए बहुत दुख का विषय है । सुषमा स्वराज जी एक ऐसी नेत्री रहीं, जिनको पूरा देश सुनना चाहता था । जब वे बोलती थीं तो उनको सुनने के लिए पूरा देश व्यग्र होता था । ऐसी नेता जिन्होंने छत्तीसगढ़ को एम्स दिया । छत्तीसगढ़ के दूरदर्शन केन्द्र को, आकाशवाणी केन्द्र को अपग्रेड किया । हमने कभी यह नहीं सोचा था कि वे इतनी जल्दी हमारे बीच से चली जाएंगी । हम लोगों को उनका मार्गदर्शन मिला है । हम उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं ।

बाबूलाल जी गौर एक ऐसे अजातशत्रु थे, हम लोगों को मध्यप्रदेश की विधान सभा में तीन बार उनके साथ बैठने का अवसर मिला, आप भी रहे । नये सदस्यों को उनके जीवन को देखना चाहिए कि वे आखिर इतनी बार चुनाव क्यों जीतते रहे, इतने अधिक वोटों से कैसे जीतते रहे । इस उम्र में भी वे लगातार सक्रिय रहे । ऐसे बाबूलाल गौर जी को हम कभी भूल नहीं सकते ।

अरूण जेटली जी, देश के ऐसे ख्यातिनाम एडवोकेट, बुद्धिजीवी, बड़े से बड़े विषय में जब वे सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते थे तो लोग उन्हें सुनते थे कि अरूण जेटली जी क्या बोलेंगे और आज भी लोग उन्हें याद करते हैं । ऐसे अरूण जेटली को हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं ।

मालूराम सिंघानिया जी, हम सब लोगों के पहले वे एमएलए बने । वे छत्तीसगढ़ की बातों को सदैव उठाते रहे । उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया । हम उनके प्रति भी श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं ।

बंशीलाल महतो जी, अगर छत्तीसगढिया का कोई प्रतीक हो सकता है तो वे बंशीलाल महतो जी हो सकते हैं । एकदम अल्हड़ स्वभाव के थे, आप उनसे कभी भी बात करें तो वे छत्तीसगढिया में ही बात करेंगे । वे हमारे बीच से चले गए । उन्होंने कहा था कि मैं अगली बार चुनाव नहीं लड़ूंगा और उन्होंने टिकिट का दावा भी नहीं किया । ऐसे बंशीलाल जी महतो हमारे बीच नहीं रहे । हम उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं ।

कैलाश जोशी जी के साथ भी हम लोगों को काम करने का अवसर मिला । हम यह कह सकते हैं कि विधायी प्रक्रियाओं, नियम कायदे और कानून का वे जितना पालन करते थे । हमको तो विधायक के रूप में उंगली पकड़कर उन्होंने सिखाया है । अगर विधान सभा में हम खड़े होकर ज्यादा बोलते थे तो वे कहते थे कि अभी तुम नये हो, अभी सीखने की जरूरत है, बार-बार खड़े मत हुआ करो । पटवा जी, जोशी जी ऐसी एक पीढ़ी थी, आज हमारे नये विधायकों को ऐसे लोग देखने को नहीं मिलते हैं । जैसा हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा राजनीति के संत । आज वे हमारे बीच नहीं रहे । हम सबके लिए नई पीढ़ी के लोगों के लिए, हमारी पीढ़ी के लोगों को लिए, जिनसे हम सीख सकते थे और जिनसे सीखें तो हम सबको भी राजनीति में एक आदर्श प्राप्त होगा । ऐसे 6 नेताओं के निधन पर आज हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं । प्रभु, उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें अपने चरणों में स्थान दे । यही प्रभु से काम ना करते हैं ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजेपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, देश और प्रदेश के 6 राजनेताओं को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं । निश्चित रूप से यह पूरे देश के लिए दुख की बात है कि जिन्होंने राजनीति के माध्यम से, समाज सेवा के क्षेत्र में, लोगों के हित में काम किया । आज ऐसे दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं, केन्द्रीय मंत्री रहीं श्रीमती सुषमा स्वराज जी, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी, केन्द्रीय मंत्री श्री अरूण जेटली जी, पूर्व विधायक श्री मालूराम सिंघानिया जी, कोरबा के पूर्व सांसद डॉ. बंशीलाल महतो जी, मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी जी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए मैं अपने दल और पूरे सदन की तरफ से श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं, धन्यवाद् ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं । दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सदन दो मिनट का मौन धारणा करेगा ।

(सदन द्वारा खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया गया ।)

अध्यक्ष महोदय :- दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित ।

(12:02 से 12:13 बजे तक सभा की कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

12:13 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश के किसान परेशान हैं। प्रदेश में 75 प्रतिशत से ज्यादा धान की कटाई हो चुकी है। किसानों को पैसे की आवश्यकता है। इस सरकार ने धान खरीदी के समय में एक महीने की वृद्धि की है और किसान अगर खुले बाजार में धान बेचने जा रहा है तो सरकार धान की जब्ती कर रही है। पूरे प्रदेश के किसानों में त्राही-त्राही मची हुई है। किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कर्ज लेने के लिये भटक रहा है। साहूकारों के पास चक्कर लगा रहा है, क्योंकि किसान धान भी नहीं बेच पा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं उसे लूंगा, आप बैठ जाइए।

श्री शिवरतन शर्मा :- हमने इसमें स्थगन दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने देख लिया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह पूरे देश के 50 लाख किसानों का मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं ले रहा हूं। अभी कार्यमंत्रणा समिति पहले है।

श्री शिवरतन शर्मा :- सदन की कार्यवाही रोककर हमारे स्थगन पर चर्चा कराये, यह मैं आपसे निवेदन करता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। सरकार एक तरफ तो बोलती है कि 25 रूपये क्विंटल में धान खरीदेंगे और वहां अभी तक आदेश नहीं पहुंचा है। पूरे प्रदेश में अन्य प्रदेशों से धान का बम्फर यहां पर प्रवेश हो चुका है। प्रशासन उसे रोकने में...।

अध्यक्ष महोदय :- मैं उसमें विचार कर रहा हूं। विधायनी कार्य के बाद उसे लूंगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। सरकार धान खरीदी में हाफ रही है। आप हाफ रहे हैं। आप अभी तक क्यों नहीं खरीदे हैं? आपने कहा है तो उसे 2500 रूपये में खरीद लीजिए। दिल्ली की लड़ाई लड़िए,हम वहां आपका साथ देंगे, पर 2500 रूपये में धान खरीदिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- आज पूरे प्रदेश में धान खरीदी की जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं और (व्यवधान) खेती किसानी के मौसम में उन्हें जो क्षति हो रही है, उसके कारण हमने स्थगन दिया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- पूरे बिचौलिए प्रदेश में सक्रिय हैं और किसानों के धान की औने पौने दाम में खरीदी हो रही है। यह बहुत गलत है। इसमें स्थगन दिये हैं, आप इसे स्वीकार करिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम चाहते हैं कि सारे काम रोककर उसमें तत्काल चर्चा कराई जाए। आज प्रदेश का जो सबसे प्राथमिक क्षेत्र है, जिसमें लाखों लोग हैं, सब परेशान है। किसान बिचौलियों के कब्जे में हैं। औने-पौन दाम में मण्डियों में जा रहा है। .....(व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आप एक आदेश निकलवाईये कि आज धान 2500 रूपये में खरीदेंगे। आदेश जारी करिये और दिल्ली की लड़ाई लड़ते रहिये। हम आपको दिल्ली से लड़ने के लिए मना नहीं कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- किसानों पर राजनीति करने वाली सरकार छल कर रही है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मगर यह किसान बर्बाद हो रहा है। बिचौलिये लूट रहे हैं। सरकार हांफ रही है, सरकार थक गई है। .....(व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- जो लूटपाट हो रहा है, ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मैं लूंगा। विधायिनी कार्य हो जाए, फिर मैं ले रहा हूँ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सब कामों को स्थगित करके चर्चा कराये।

समय :
12:16 बजे

<u>कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन</u>

अध्यक्ष महोदय :- कार्यमंत्रणा समिति की बैठक गुरूवार दिनांक 21 नवम्बर, 2019 में लिए गए निर्णय अनुसार समिति ने वित्तीस तथा अन्य कार्यों के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिश की है :-

1. वित्तीय वर्ष 2019-20 के द्वितीय अनुपूरक की अनुदान मांगों पर चर्चा, मतदान, एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण के लिए निर्धारित समय - 3 घण्टे।
2. मंगलवार, दिनांक 26 नवम्बर, 2019 को सभा की बैठक में प्रश्नकाल के पश्चात "संविधान दिवस" के अवसर पर संविधान से संबंधित विषय पर चर्चा होगी। उसके उपरांत वित्तीय वर्ष

असंशोधित/संशोधन के लिए नहीं

2019-20 के द्‌वितीय अनुपूरक की अनुदान मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी।

3. नवम्बर-दिसम्बर, 20149 सत्र से प्रत्येक सत्र के प्रथम दिवस की कार्यवाही राष्ट्रगीत "वंदेमातरम्" के साथ-साथ राज्यगीत "अरपा पइरी के धार..." से आरंभ होगी।

अध्यक्ष महोदय :- अब इसके सम्बन्ध में श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को स्वीकृती देता है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि -सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन की गई सिफारिश को स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(भारतीय जनता पार्टी एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे.) के सदस्यों द्‌वारा नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- मैं आप लोगों का ही प्रस्ताव ले रहा हूँ।

समय :
12:19 बजे

<u>स्थगन प्रस्ताव</u>

<u>प्रदेश में किसानों का धान समर्थन मूल्य पर खरीदी न होने एवं उन्हें परेशान किए जाने सम्बन्धी</u>

अध्यक्ष महोदय :- मेरे पास समर्थन मूल्य पर धान खरीदी न होने तथा किसानों को परेशान किए जाने के सम्बन्ध में सदस्यों की ओर से 16 स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :-

प्रथम सूचना	-	श्री केशव चन्द्रा, सदस्य
दूसरी सूचना	-	श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य
तीसरी सूचना	-	डॉ0 रमन सिंह, सदस्य
चौथी सूचना	-	श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
पांचवी सूचना	-	श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
छठवीं सूचना	-	श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य
सातवीं सूचना	-	श्री नारायण चंदेल, सदस्य
आठवीं सूचना	-	श्री सौरभ सिंह, सदस्य
नवमी सूचना	-	श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दसवीं सूचना	-	श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य
ग्यारहवीं सूचना	-	श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य
बारहवीं सूचना	-	डॉ0 कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य
तेरहवीं सूचना	-	श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य
चौदहवीं सूचना	-	श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य
पन्द्रहवीं सूचना	-	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य
सोलहवीं सूचना	-	श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी, सदस्य।

चूंकि श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य की सूचना अधिक तथ्यात्मक है। अत: उसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ।

धान कटाई 60 प्रतिशत से ज्यादा हो चुकी है। प्रदेश में धान की पैदावार बहुत अच्छी है। उसके बाद भी किसानों की आर्थिक हालत खस्ता/बदहाल है। किसान अपनी फसल को 1200-1500 रूपये प्रति क्विंटल के बीच बेचने को बाध्य हुआ है। किसानों के नाम पर बहुमत पाने वाली सरकार किसानों को बर्बाद करने में लगी हुई है। समर्थन मूल्य में धान खरीदी 01 नवम्बर से शुरू होनी थी, उसे बढ़ाकर 01 दिसम्बर से खरीदी का निर्णय लिया गया जिसके चलते किसान अपनी आवश्यकता की पूर्ति सस्ते में धान बेचकर कर रहा है । वहीं जो किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने हेतु धान रख रहा है । उनका 200 रूपये प्रति क्विंटल से अधिक खर्च बढ़ गया है (खलिहान तैयार करना व सूखत के कारण) किसान धान बेचने जा रहे हैं और पूरे प्रदेश में किसानों का धान जब्त किया जा रहा है । करोड़ों रूपये के धान की जब्ती बनायी जा चुकी है । प्रदेश की 50 प्रतिशत मंडियों में खरीददार नहीं आते, जिसके चलते किसानों को बाहर धान बेचने को बाध्य होना पड़ रहा है और शासन धान की जब्ती बनाकर उन्हें प्रताड़ित कर रही है।

केन्द्र की सरकार ने किसानों को 6000 रूपये प्रति एकड़ किसान सम्मान निधि प्रदान करने का निर्णय लिया, किन्तु समय सीमा में प्रदेश सरकार द्वारा औपचारिकता पूर्ण न किये जाने के कारण प्रदेश के आधे से ज्यादा किसान इसके लाभ से वंचित हैं, किसानों को मध्यकालीन, दीर्घकालीन तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋण वसूली का दबाव झेलना पड़ रहा है । प्रदेश के दो किसानों को जेल में भी भेज दिया गया तथा सरकार वन टाईम सेटलमेंट में सहयोग करने की बात कर रही है ।

प्रदेश में किसानों का बैल मर जाने के कारण आत्महत्या करने का प्रकरण भी सामने आया है । प्रदेश सरकार के किसान विरोधी निर्णय के कारण किसान त्रस्त हैं, भयभीत हैं जिसके चलते पूरे प्रदेश में किसानों में सरकार के विरूद्ध रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अतएव इस महतवपूर्ण विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं ।

इस संबंध में शासन का क्या कहना है ।

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य शासन के द्वारा निर्णय लिया गया है...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था पर आनी चाहिए या तत्काल चर्चा शुरू होनी चाहिए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- मंत्री जी को बोलने तो दो । मंत्री जी की बात तो सुन लो । सुनने की हिम्मत तो रखिए ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन की ओर से निर्णय लिया गया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में किसानों से धान खरीदी का कार्य दिनांक 1 दिसम्बर, 2019 से 15 फरवरी, 2020 तक किया जायेगा । धान खरीदी करने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही पूरी की जा चुकी है । इस प्रकार खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में धान खरीदी का कार्य ढाई माह तक चलेगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब सहकारिता मंत्री क्यों दे रहे हैं ? इसका जवाब खाद्यमंत्री या कृषि मंत्री की ओर से आना चाहिए । हमने अपने स्थगन में किसानों की बदहाली के संबंध में चर्चा की है कि किसानों की बदहाली है । किसानों की बदहाली के बारे में या तो मुख्यमंत्री जी जवाब दें या फिर कृषि मंत्री जी जवाब दें । क्योंकि हमने सहकारिता मंत्री से नहीं पूछा है, हमने किसानों की बदहाली के बारे में पूछा है। किसानों की बदहाली है और मुख्यमंत्री जी की नीतियों के कारण है । उनको जवाब देना चाहिए । आज सहकारिता की हालत खराब है, खाद्य विभाग की हालत खराब है, कृषि विभाग की हालत खराब है । सरकार की गलत नीतियों के कारण किसानों की बदहाली है और हमने पूरे स्थगन प्रस्ताव में बदहाली की चर्चा की है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मंत्रिमण्डल की संयुक्त जवाबदारी है, जवाब देने की संयुक्त जवाबदारी है । (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- उल्लेखनीय है कि गत खरीफ विपणन वर्ष 2018-2019 में धान खरीदी का कार्य 1 नवम्बर, 2018 से 31 जनवरी, 2019 तक किया गया था । खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में माह नवंबर 2019 के प्रथम सप्ताह में आकस्मिक वर्षा एवं तुफान आने के कारण खेत के गीले होने से कटाई में आने वाली कठिनाइयों, धान में नमी की मात्रा ज्यादा होने एवं खरीदी केन्द्रों के गीले होने के कारण धान खरीदी का कार्य दिनांक 1 दिसम्बर, 2019 से प्रारंभ किया जाना निर्धारित किया गया है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- किसानों की बदहाली के संबंध में हमने स्थगन दिया है । आपकी व्यवस्था आनी चाहिए क्योंकि हमने किसानों कह बदहाली के संबंध में हमने स्थगन दिया है (व्यवधान) इस ओर मुख्यमंत्री जी या कृषि मंत्री की ओर से बयान आना चाहिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये सहकारिता का विषय नहीं है और किसानों की बदहाली से संबंधित हमने दिया है और इसका उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आना चाहिए ।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, ये समग्र विषय है और मुख्यमंत्री जी या कृषि मंत्री जी की ओर से जवाब आना चाहिए । छत्तीसगढ़ के किसानों की आर्थिक स्थिति के संबंध में है (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो सुन लीजिए । (व्यवधान)

डा. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के द्वारा अधिकतम 17 प्रतिशत तक नमी का ही धान खरीदी किये जाने के निर्देश हैं, पहले धान खरीदी किये जाने पर आकस्मिक वर्षा के कारण धान में नमी की मात्रा ज्यादा होने से किसानों को खरीदी केन्द्रों में धान जाने के कारण धान में नमी की मात्रा ज्यादा होने से किसानों को खरीदी केन्द्रों में धान लाने पर रिजेक्ट किये जाने पर असुविधा की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी । अत: किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही धान खरीदी का कार्य 1 दिसम्बर, 2019 से प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी यहां उपस्थित हैं । यह सरकार की संयुक्त जवाबदारी है और मंत्री जी से उत्तर आ रहा है, आप सुन लीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- किसानों की बदहाली के संबंध में हमने स्थगन दिया है । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, संयुक्त जवाबदारी की बात समझ रहे हैं, लेकिन यह संवेदनशील मुद्दा है । इस मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ बोलेंगे तो वजन ज्यादा रहेगा ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में किसान पंजीयन का कार्य दिनांक 16 अगस्त, 2019 से 07 नवंबर, 2019 तक किया गया । कुल 19.70 लाख किसानों द्वारा धान खरीदी हेतु पंजीयन कराया गया है ।

खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में भारत सरकार द्वारा उचित औसत गुणवत्ता के खरीफ फसल धान के लिए समर्थन मूल्य कॉमन (मोटा) धान हेतु 1815 रूपये प्रति क्विंटल एवं धान ग्रेड ए (पतला) हेतु 1835 रूपये प्रति क्विंटल की दर निर्धारित की गई है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- धर्मजीत भैया, बोलेंगे न । मंत्री जी जो बोल रहे हैं, जवाब सुन तो लीजिए, जवाब सुन लो, उसके बाद फिर बोलना ।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम तो आग्रह कर रहे हैं कि यह गलत मुद्दा है, छत्तीसगढ़ के किसानों से संबंधित मामला है । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- जवाब तो सुन लीजिए । सुनने की आदत डालो।

श्री धर्मजीत सिंह :- किसानों की समस्या है, उसी से संबंधित है । मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, उनका विभाग नहीं है । यह बड़ा मुश्किल है कि उनका कोई लेना-देना नहीं है, उनका विभाग नहीं है । जिनको बयान देना चाहिए, वे चुप बैठे हैं । यहां खाद्यमंत्री गायब हैं । पता नहीं कहां चुनाव प्रचार में चले गए। पूरा प्रदेश परेशान है धान के नाम से । वे चुनाव प्रचार कर रहे हैं । अध्यक्ष जी, आप तो बोल दीजिए ना, माननीय मुख्यमंत्री बोलें, मुख्यमंत्री जी मीटिंग बुलाये थे, उसमें हम लोग थे । मुख्यमंत्री जी बोले, पूरी सरकार बोल रही है । (व्यवधान)

डॉ.प्रेमसाय सिंह :- यह कहना सही नहीं है कि किसानों की आर्थिक हालत खस्ता/बदहाल है । किसान अपनी फसल को 1200-1500 रूपये प्रति क्विंटल में बेचने को बाध्य हुआ है । यह कहना भी सही नहीं है कि किसानों को बाहर धान बेचने को बाध्य होना पड़ रहा हैऔर शासन धान की जब्ती बनाकर प्रताड़ित कर रही है । (व्यवधान)

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष जी, यह मुद्दा किसानों से संबंधित है ...(व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- यह छोटे सरकार है, बड़े सरकार इधर है । हम चाहते हैं, बड़े सरकार बोले । (व्यवधान)

श्री अजीत जोगी :- इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिये । व्यवधान

डॉ.शिव डहरिया :- सूजी से काम चल जथे तो साबर के का जरूरत हे । थोड़ा सुन ले । (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह :- वस्तुस्थिति यह है कि राज्य शासन के निर्देश पर सीमावर्ती राज्यों से अवैध धान की आवक रोकने हेतु कलेक्टर द्वारा राजस्व, खाद्य, सहकारिता, फॉरेस्ट, मंडी एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों की विशेष चेकिंग दल का गठन किया गया है । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- पाकिस्तान के एक रेल मंत्री बोला ना, एक पाव का बम है, आधा किलो का बम है । हम बड़े बम से सुनना चाहते हैं । आधा पाव, एक पाव से नहीं सुनना चाहते हैं । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन का विषय है, वह किसानों की बदहाली हालत को लेकर है । इसमें कृषि विभाग का भी है । खाद्य विभाग का भी है । मुख्यमंत्री जी का विषय है । इसमें मुख्यमंत्री जी की ओर से जवाब आये, समुचित जवाब आये, मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं । उनके विभाग का मामला है नहीं । असहाय दिख रहे हैं । लाचार दिख रहे हैं । मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिये । (व्यवधान)

डॉ.प्रेमसाय सिंह :- इस संबंध में कीेक्टर्स पुलिस अधीक्षक एवं डिस्ट्रीक्ट फॉरेस्ट आफिसर को वीडिया कॉफ्रेंस के माध्यम से भी निर्देशित किया गया है । माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कलेक्टर

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

कीराज्य स्तर पर बैठक लेकर सीमावर्ती राज्यों से अवैध धान की आवक रोकने हेतु कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घोर आपत्तिजनक है । माननीय मंत्री जी को असहाय, लाचार कहना घोर आपत्तिजनक है । छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री को लाचार कहा जा रहा है । (व्यवधान)

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- आपसे भी वरिष्ठ मंत्री है, इनका जवाब सुन लीजिए । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- आपसे वरिष्ठ जरूर है । जानते नहीं हो तो मत बात किया करो । (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह :- उक्त निर्देशों के पालन में पूरे प्रदेश में सीमावर्ती राज्यों से सटे प्रदेक के जिलों में चेक पोस्ट स्थापित किया गया है एवं अवैध धान की आवक रोकने हेतु समुचित कार्यवाही विशेष चेकिंग दल के द्वारा की जा रही है । दिनांक 23.11.2019 तक प्रदेश में 1358 प्रकरण निर्मित किये गये हैं, जिसके अंतर्गत कुल 1667.18 क्विंटल धान की जब्ती बनाई गई है । किसानों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है । (व्यवधान)

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- वरिष्ठ मंत्री हैं । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । सुन लें । माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न सुन लें, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता है । आप अपने मंत्री जी को बैठायें और व्यवस्था का प्रश्न सुनें । हमारा व्यवस्था का प्रश्न है । हमारा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें । ....(व्यवधान) हमारा व्यवस्था का प्रश्न है । हमारा व्यवस्था का प्रश्न है, उसको सुन लें । हमारा पाईन्ट आफ आर्डर सुन ले । माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पाईन्ट आफ आर्डर सुन लें। आप पाईन्ट ऑफ आर्डर सुन लें । पाईन्ट ऑफ आर्डर से दूसरा विषय कोई दूसरा थोड़ी होता है । (व्यवधान)

डॉ.प्रेमसाय सिंह :- यह कहना सही नहीं है कि समय सीमा में प्रदेश सरकार द्वारा औपचारिकता पूर्ण न किये जाने के कारण प्रदेश के आधे से ज्यादा किसान, किसान सम्मान निधि के लाभ से वंचित है । यह कहना भी सही नहीं है कि प्रदेश में किसानों का बैल मर जाने के कारण आत्महत्या करने का कोई प्रकरण सामने आया है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, एक मिनट रूक जाईये । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पाईन्ट ऑफ आर्डर स्वीकार कर लिया है । (व्यवधान)

डॉ.प्रेमसाय सिंह :-प्रदेश के इतिहास में पहली बार हमारी सरकार द्वारा बड़ी ऋण माफी की गई है । इस ऋण माफी मं प्रदेश के 17.99 लाख से अधिक किसानों के 8608 करोड़ के अल्पकालीन ऋण

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माफ किये गये हैं । इस कृषि ऋण माफी योजना की विशेषता यह भी है कि इसमें छोटे-बड़े किसानों में कोई भेद नहीं रखा गया । सभी क कृषि ऋण माफ किया गया है । ऋण माफी की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है । जिससे किसानों के बड़ी राशि के कृषि ऋण भी माफ किये गये हैं । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- यह बहुत गलत बात है, यह आपत्तिजनक है । आसंदी के व्यवस्था के बाद भी मंत्री जी नहीं सुन रहे हैं, इस सदन में हम क्या अपनी बात रखेंगे । जब आपकी बात नहीं सुनी जा रही है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय:- व्यवस्था का प्रश्न क्या है, बताइये । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- मंत्री इतने उद्दंड हो जाये तो हम अपनी बात क्या रखेंगे । आपके बोलने के बाद भी मंत्री जी नहीं सुन रहे हैं । (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह :- किसानों के 30-35 वर्ष पुराने कालातीत ऋण भी माफ किये गये हैं । इस ऐतिहासिक कृषि ऋण माफी से उत्साहित कृषक पुन: खेती की ओर आकर्षित हुये हैं । केवल सहकारी बैंकों के माध्यम से इस वर्ष खरीफ के लिए 11.49 लाख किसानों को 3953 करोड़ के फसल ऋण प्रदाय किये गये हैं जो पिछले खरीफ की तुलना में 686 करोड़ रूपये अधिक है । ऋण लेने वाले किसानों कीसंख्या में भी दो लाख की वृद्धि हुई है । (व्यवधान)

श्री धर्मजीतसिंह :- संसदीय कार्य मंत्री जी, सुनियोजित तरीके से माननीय मंत्री जी को आगे किये हो । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय अग्रवाल जी । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- इस पर संसदीय कार्य मंत्री जी बोलें । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- संसदीय कार्य मंत्री जी आपने कहा ना, इसलिए । आपने जिक्र किया, माननीय चंद्राकर जी ने जिक्र किया ना ।

श्री मिश्रा

मिश्रा\25-11-2019\b15\12.30-12.35

श्री रविन्द्र चौबे :- आपके जिक्र किया, माननीय अजय चन्द्राकर जी ने जिक्र किया ना।

श्री शिवरतन शर्मा :- पाईंट ऑफ आर्डर बृजमोहन जी ने उठाया है और बोलने की इजाजत अध्यक्ष जी ने इनको दी है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरा दूसरा पाईंट ऑफ आर्डर भी खड़ा हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, सभी मंत्री

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जी आपके कहने के बाद कि पाईंट ऑफ आर्डर मैं सुनूंगा, उनको बैठाने की कोशिश कर रहे हैं और वह बैठे-बैठे मुस्करा रहे हैं, इससे बड़ा सदन का अपमान दूसरा नहीं हो सकता। (शेम-शेम की आवाज) और आपको इसके ऊपर भी व्यवस्था देनी चाहिए कि आप खड़े होकर जब कोई निर्देश दे रहे हैं उसको भी यह लोग नहीं मान रहे हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है वह स्थगन प्रस्ताव सिर्फ सहकारिता से जुड़ा हुआ नहीं है। हमारा स्थगन प्रस्ताव वित्त से जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ है, खाद्य से जुड़ा हुआ है और हमारा स्थगन प्रस्ताव कई विभागों के संयुक्त प्रयास से जुड़ा हुआ है और हमने किसानों की बदहाली के संबंध में इस स्थगन प्रस्ताव में चर्चा की है और इसलिए इस स्थगन प्रस्ताव का जवाब, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी गाहे-बगाहे केबिनेट की मीटिंग लेकर, बाहर में प्रेस कांफ्रेंस लेकर इस बात को कहते हैं कि धान को जप्त किया जायेगा, धान खरीदा नहीं जायेगा, एक दिसंबर से धान खरीदा जायेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बृजमोहन अग्रवाल जी, आप व्यवस्था के प्रश्न को उठा रहे हैं तो उठाईये, जब मैं ग्राह्य या अग्राह्य कर लूं तब इसके बाद भाषण देने का अवसर आयेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है क्योंकि यह एक नीतिगत विषय है जिस पर सरकार को निर्णय लेना था और सरकार के अनिर्णय के कारण किसानों की बदहाली हुई है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए, यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और आपको यह निर्देश देना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दें।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाईंट ऑफ आर्डर है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब एक पाईंट ऑफ आर्डर में दूसरा पाईंट ऑफ आर्डर? पहले मेरी बात सुन लें।

श्री अजय चंद्राकर :- आपका भी पाईंट ऑफ आर्डर?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने नहीं कहा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने आपको जवाब देने की अनुमति दी है क्या?

श्री अजय चंद्राकर :- आपको किस विषय पर सुनें?

अध्यक्ष महोदय :- आपको कुछ कहना है?

श्री रविन्द्र चौबे :- हॉ , मैं बोल रहा हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय फिर वही बात है कि संसदीय कार्यमंत्री जी लगातार आपकी व्यवस्थाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। सभा की गरिमा को गिराने की कोशिश यदि संसदीय कार्यमंत्री जी द्वारा होती है यह बहुत ही अप्रिय स्थिति सभा के लिए है। वह किस प्रक्रिया में,

किसकी अनुमति से, किस कारण से खड़े हैं? अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था आई नहीं है कि आपने क्या व्यवस्था दी है। यदि वह इस व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहे हैं तो बात अलग है, वह बोलते। व्यवस्था के प्रश्न पर आपकी कोई व्यवस्था आई नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- आप किसके अंतर्गत बोल रहे हैं? (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- चौबे जी, क्या आप बोल रहे हैं?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किस विषय पर बोलेंगे?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष जी ने अनुमति दी है, उस पर बोल रहे हैं।

श्री देवेंद्र यादव :- आप बार-बार खड़े हो जाते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा - अध्यक्ष जी, मेरा पाईंट ऑफ आर्डर है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, आसंदी का पूरा सम्मान आपको भी करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए। आप आपत्ति कर रहे हैं कि मैं उनकी बात नहीं मान रहा हूं, तो ऐसी बात नहीं है, पहली बात तो यह है। दूसरी बात हम स्थगन पर आपकी बात ले रहे थे, माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे थे, उत्तर अभी आधा पढ़ा हुआ था, आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। या तो उत्तर देने के पूर्व आप व्यवस्था का प्रश्न उठाते तो शायद आसंदी से कुछ निर्देश होता तो इधर उसका पालन होता लेकिन माननीय मंत्री जी आधे से ज्यादा उत्तर पढ़ लिये। अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात यह कि यदि इस सदन के बहुत विद्वान सदस्य माननीय बृजमोहन जी ने कहा कि इसमें वित्त का भी मामला जुड़ा हुआ है, इसमें कृषि का भी मामला जुड़ा हुआ है, आपने 6000 रूपये की सीमा केंद्र सरकार की योजना के बारे में रेवेन्यू से जानकारी नहीं गई उसका भी मामला इसमें उठाया। आपने इसमें लिखा हुआ है कि 1 दिसंबर से खरीदी का निर्णय लिया गया जो कि 1 नवंबर में होना था, आपने को-ऑपरेटिव से धान खरीदी का भी मामला उठाया। आप ही के स्थगन में 6 विभागों के अलग-अलग मामले को 6 पैरा में हमेशा धान खरीदी का आपने उठाया है। जब आप भी इधर रहे हैं, जब भी मुद्दा आया तो को-आपरेटिव डिपार्टमेंट से ही उत्तर आया है। अध्यक्ष जी, छयो मंत्री जी का उत्तर देने को कहेंगे, हम छयो विभाग से उत्तर देना चाहेंगे। सरकार आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिये तैयार है। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष जी, लेकिन जब व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया, वैसे भी स्थगन का मुद्दा एक होना था। आप 6 विभागों को जोड़कर कैसे स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं और अगर आप लाये तब भी हम उसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं, कृपा करके सुन तो लें ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था के प्रश्न पर माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है।

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष जी, ये (व्यवधान) बने रहना चाहते हैं। ये सिर्फ समाचारों में बने रहना चाहते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैं पहले अपने बात कह लूं, माननीय मंत्री जी ने तो अध्यक्ष जी की व्यवस्था के उपर ही प्रश्नचिन्ह कर दिया है, आपने तो उसको भी......।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बैठिये अग्रवाल जी, आप बैठ जाईये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, क्या यहां पर मंत्रियों के कोई नेता नहीं?

6 मंत्री अलग-अलग हैं। कोई नेता हैं कि नहीं हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, हमारे नेता हैं, हमारे सदन के नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं। (मेजों की थपथपाहट) (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अभी मंत्री जी ने अभी कुछ बातें कही।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठ जाईये। आज पहला दिन है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने कुछ बातें कही मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं, आज पहला दिन है। एक मिनट सुनिये। आप लोग, मेरी बात तो सुन लें। आप बैठिये, बहुत हो गया। आप सुनिये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने जो बातें उठाई, वह बिल्कुल युक्तिसंगत रही है। आप अनुमति दें, मैं उस विषय में भी अपनी बात कहूंगा। अभी स्थगन पर चर्चा शुरू नहीं हुई है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चंद्राकर जी, आप पहले बात सुन लीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, पहले स्थगन तो सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, उनकी बातें असंगत थी।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, मेरा प्वाईंट ऑफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय :- पहले मैं व्यवस्था दे रहा हूं, आप सुन तो लीजिए।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी जवाब तो आयेगा, मैं आग्रह यह करना चाहता हूं। माननीय शिवरतन जी हमारे सीनियर सदस्य हैं। उनका प्वाईंट ऑफ आर्डर है तो उसको सुन लीजिए। उसके बाद आगे जो आसंदी का निर्देश होगा वह मानेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- प्वाईंट ऑफ आर्डर किस वजह से ? (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- शिवरतन जी को अवसर मिलना चाहिए। (व्यवधान)

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वीकार करें, अस्वीकार करें वह अलग बात है। प्वाईंट ऑफ आर्डर का.... (व्यवधान) हमारा अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये-चलिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन आसंदी के निर्देश पर संचालित होता है।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, आप प्वाईंट ऑफ आर्डर पर ही बोलिए। भाषण नहीं चलेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्वाईंट ऑफ आर्डर पर ही बोल रहा हूं। हां, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, प्वाईंट ऑफ आर्डर पर ही बोल रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन आसंदी के निर्देश पर संचालित होता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, भाषण नहीं देंगे तो क्या देंगे ? आप भाषण नहीं चलेगा बोलते हो। प्वाईंट ऑफ आर्डर पर भी भाषण नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, राशन देने का बीमा तो बघेल जी ने लिया है। भाई, भाषण ही तो देना है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, माननीय बृजमोहन जी ने प्वाईंट ऑफ आर्डर उठाया और आपने माननीय मंत्री को तीन बार बैठने के लिए कहा।

अध्यक्ष महोदय :- उस बात को छोड़िए न।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, महत्वपूर्ण बात है।

अध्यक्ष महोदय :- यह मेरी व्यवस्था है, आप बैठिए। आप बैठिये-बैठिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी लगातार भाषण देते रहे। यह सरासर आसंदी की अवहेलना है। आसंदी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- आपको कितनी बार बोल दिया है आप समझ नहीं रहे हो।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिये, मेरी बात सुनिये। आप सुनिये न। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- आप बगल में खाली अध्यक्ष जी को भड़काने के लिए...।(व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आप आसंदी की अवहेलना कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बैठ जाओ भैया प्लीज, मंत्री जी। आप लोगों ने गंभीरतापूर्वक मेरी बातों को नहीं सुना। मैंने आपके इस सदन (व्यवधान) एक मिनट, एक मिनट, आपको सुना रहा हूं। आप मेरी बातों को सुनिये। आप मेरी बात सुन लीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष जी, यह बिना दवाई खाये आये हैं, इसलिए बार-बार खड़े होकर ऐसा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- स्थगन प्रस्ताव को मैंने पढ़ते समय कहा था कि प्रथम सूचना केशव चंद्रा की मिली है। परंपरा और नियमों की बात करूं तो मैं केशव चंद्रा के स्थगन प्रस्ताव को पढ़ सकता था। मगर मैंने ज्यादा तथ्यात्मक समझ कर, आप सुन लीजिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष के दिये गये प्रस्ताव को शामिल किया है। इस बारे में आपको कुछ नहीं कहना है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, कहना है।

अध्यक्ष महोदय :- इस बारे में आपको कुछ नहीं कहना है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, यह परंपरा है। यह हमको कहना है यह परंपरा है कि स्थगन प्रस्ताव पर कई मिलते हैं तो उसमें जो विषय सुसंगत होता है, जिसमें सब विषय का समावेश होता है। (व्यवधान) यह परंपरा रही है।

अध्यक्ष महोदय :- अब आप ही लोग कहें तो उसमें 6-6 विषय शामिल हैं। उससे को-आपरेशन नहीं होगा तो को-आपरेटिव मंत्री नहीं उठायेगा तो कौन उठायेगा ?

आप चलिये, मंत्री जी अपना भाषण पूरा करिये। (मेजों की थपथपाहट)

श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरा जवाब पढ़ रहा था।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था नहीं आई है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, जब 6 विभाग हैं तो मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- आपके बाद जब ग्राह्य हो जायेगा तो देंगे न वे भी जवाब देंगे। आप क्यों परेशान हैं ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब पूरा पढ़ रहा था।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था नहीं आयी है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी व्यवस्था, जब 6 विभागों का मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया। आपके बाद, जब ग्राह्य हो जाएगा, तब वह भी जवाब देंगे। आप क्यों परेशान हैं?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको जवाब देना चाहिए। (व्यवधान)

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- वे जवाब देंगे। जब जरूरत पड़ेगी तो वह भी जवाब देंगे।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश सरकार किसानों के प्रति असंवेदनशील है। जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब फिर से पढ़वा दीजिए। कोई उनका जवाब नहीं सुन पाया।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिनांक 20.11.2019 की स्थिति में प्रदेश में कुल 18,84,610 किसान परिवारों से स्वघोषणा पत्र प्राप्त हुआ है और राज्य सरकार द्वारा इन सभी किसान परिवारों का पंजीयन PM-KISAN पोर्टल में कर दिया गया है। इस प्रकार दिनांक 20.11.2019 के पूर्व प्राप्त किसी भी स्वघोषणा पत्र के विरूद्ध किसी किसान परिवार का पंजीयन शेष नहीं है।

राजस्व विभाग द्वारा किसान परिवारों के पंजीयन कराने हेतु लगातार प्रयास कर रही है, इसी प्रयास के परिणाम स्वरूप 18,84,610 किसान परिवारों का पंजीयन अब तक कराया जा चुका है। जिसमें से 14,80,323 किसान परिवारों को योजना के अंतर्गत किसान सम्मान निधि प्राप्त होना प्रारंभ हो गया है, शेष लगभग 4 लाख किसान परिवारों के खाते से सम्बन्धित सहकारी बैंक को भारत सरकार द्वारा अक्रियाशील मानते हुए रोका गया है। जबकि ये सभी बैंक क्रियाशील है। इसकी सूचना भारत सरकार को देकर इसके निराकरण का प्रयास किया जा रहा है।

गतवर्ष खरीफ 2018 में धान का रकबा 38.17 लाख हेक्टेयर में अनुमानित उत्पादन 104.46 लाख में.टन था। मार्कफेड द्वारा 80.38 लाख मे.टन एवं बीज निगम के द्वारा कृषकों से 6.00 लाख क्विंटल धान बीज उपार्जित की गई थी। इस प्रकार प्रदेश में कुल 80.98 लाख में. टन धान क्रय किया गया। जिसकी कुल राशि रूपये 6021.58 करोड़ कृषकों को प्रोत्साहन के रूप में मार्कफेड एवं बीज निगम के द्वारा भुगतान किया गया।

इस वर्ष खरीफ 2019 में धान का रकबा लगभग 39 लाख हेक्टेयर है, जिससे 125 लाख मे. टन धान उत्पादन होना अनुमानित है। इस वर्ष धान खरीदी का लक्ष्य 85 लाख मे. टन रखा गया है तथा बीज निगम के द्वारा कृषकों से लगभग 6 लाख क्विंटल धान बीज उपार्जन करने का कार्यक्रम है। इस प्रकार कुल 85.60 लाख मे.टन धान क्रय किया जाना है जिसका भुगतान योग्य प्रोत्साहन राशि रू. 5778.00 करोड़ मार्कफेड एवं बीज निगम के द्वारा किया जावेगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु राशि रू. 5943 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है।

असंशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

राज्य शासन के द्वारा केंद्र शासन को पत्र लिख कर खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में किसानों के हित में समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 2500 रूपये की दर पर खरीदी करने का निवेदन किया गया है एवं यदि किसी परिस्थिति के कारण भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस अनुरूप वृद्धि किया जाना संभव नहीं हो तो राज्य सरकार को इस मूल्य पर धान उपार्जित करने की सहमति विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना के अंतर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही राज्य के किसानों के व्यापक आर्थिक हित को देखते हुए एम.ओ.यू. की कंडिका 1 की शर्त से शिथिलता प्रदान करते हुए राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता के अतिरिक्त उपार्जित होने वाले सरप्लस चावल लगभग 32 लाख टन भारतीय खाद्य निगम में केन्द्रीय पूल में लिये जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। खाद्य विभाग भारत सरकार से उपरोक्त प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- आप भी कुछ कहेंगे ?

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण स्थगन है। प्रतिपक्ष के सारे साथी चर्चा भी करना चाहते हैं। आज की कार्यसूची क्रमांक 7 शासकीय कार्य के तत्काल पश्चात् इसको चर्चा के लिए लिया जाए और समय निर्धारित किया जाए और हम सरकार की ओर से चर्चा ग्राह्य करने की आपसे अनुमति चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको ग्राह्य करते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण विषय है। इस महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव पर हम चर्चा रोककर और अभी आप तुरंत चर्चा करवाएं, जब आप इसको स्वीकार कर रहे हैं। जब सरकार स्वीकार करने को तैयार है तो तुरंत चर्चा होनी चाहिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया। मैंने कहा कि कार्यसूची के सांतवे क्रमांक के तत्काल पश्चात् चर्चा शुरू करायी जाए। सरकार तैयार है।

अध्यक्ष महोदय :- स्थगन प्रस्ताव को चर्चा हेतु ग्राह्य किया जाता है। मैं आज की कार्यसूची में सम्मिलित कार्य के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करता हूँ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर तुरंत चर्चा करवाईये। इतना महतवपूर्ण विषय है।

श्री धरमलाल कौशिश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं लगता कि इससे और कोई महत्वपूर्ण विषय है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी कोई विषय की चर्चा का महत्व नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे कार्य को रोककर, इस पर चर्चा करवाईये। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर तुरंत चर्चा करवायें। इस पर तुरंत चर्चा प्रारंभ करवाईये।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करवायें।

अध्यक्ष महोदय :- कितने मिनट लगने हैं?

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विपक्ष चर्चा करने से भाग रही है। इसलिए बहाना बनाना चाह रहे हैं। जब सरकार तैयार हो गई है। विपक्ष चर्चा करने से क्या भाग रही है?

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभीचे।

समय :
12:45 बजे

<u>जुलाई, 2019 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखा जाना।</u>

अध्यक्ष महोदय:- जुलाई, 2019 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव, विधानसभा, सदन के पटल पर रखेंगे।

प्रमुख सचिव, विधानसभा (श्री चन्द्र शेखर गंगराड़े) :- मैं, अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार जुलाई, 2019 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखता हूं।

<u>नियम 267-"क" के अधीन जुलाई, 2019 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना।</u>

अध्यक्ष महोदय :- नियम 267-"क" के अधीन जुलाई, 2019 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव, विधानसभा सदन के पटल पर रखेंगे।

प्रमुख सचिव, विधानसभा (श्री चन्द्र शेखर गंगराड़े) :- मैं नियम 267-"क" के अधीन जुलाई, 2019 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखता हूं।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12:41 बजे

सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय :- विधानसभा की नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट करता हूं -

1. श्री सत्यनारायण शर्मा
2. श्री धनेन्द्र साहू
3. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
4. श्री मनोज सिंह मण्डावी
5. श्री शिवरतन शर्मा

समय :

12:42 बजे

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदया के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं, अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिये मंगलवार, दिनांक 26 नवम्बर, 2019 की तिथि निर्धारित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- ध्यानाकर्षण शुरू कर लें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप पहले स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करें।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय के द्वारा अध्यक्ष महोदय को आदेश दिया जाये कि ऐसा किया जाए, यह बड़ी गंभीर बात है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री अजय चन्द्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपत्तिजनक है। जब आपने स्वीकार कर लिया, आप अभी चर्चा शुरू करवायें।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने उसको स्वीकार भी कर लिया है, आप सीधे स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराईये। ध्यानाकर्षण कल के लिए रख दीजिए, आपको अधिकार है।

श्री नारायण चंदेल :- किसानों का विषय सबसे महत्वपूर्ण है।

श्री धरमलाल कौशिक :- ध्यानाकर्षण कल के लिए रख दिया जाए। उस दिन तो यह चर्चा भी आई थी कि 4 ध्यानाकर्षण रखेंगे। आप कल के लिए 6 ध्यानाकर्षण रख दीजिए।

असंपादित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- मैं व्यवस्था कर रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्थगन पर चर्चा करवायें। स्थगन पर तत्काल चर्चा शुरू होनी चाहिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज धान के स्थगन पर चर्चा करेंगे, ध्यानाकर्षण कल के लिए रख दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले किसान के स्थगन पर चर्चा होनी चाहिए। किसानों की समस्या महत्वपूर्ण है।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन का अर्थ ही यह होता है कि सदन की सारी कार्यवाही रोक कर स्थगन पर तत्काल चर्चा प्रारंभ की जाये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये आप शुरू होईए। धरमलाल कौशिक जी।

स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश की जो सबसे ज्वलंत समस्या है, प्रदेश के जो अन्नदाता हैं, आज सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वह किसान है और वह किसान केवल इस सरकार की नीति के कारण परेशान है, जिसके कारण आज किसानों की आर्थिक स्थिति बदहाली की स्थिति में है। किसानों के साथ जिस प्रकार से इस सरकार के द्वारा बर्बरता, क्रूरता के साथ में व्यवहार किया जा रहा है। किसान अपने धान को सड़क में फेक करके आये हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद आज तक प्रदेश में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई है कि किसान अपनी मेहनत की कमाई धान को सड़क में फेकने के लिए मजबूर हो। यह सरकार की जो नीति है, इस सरकार की नीति के कारण में ये स्थिति आई है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय नेता जी, सब धान कहां फेका हुआ है, आप हमें बता दीजिए, हम लोग उठाकर ले जायेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैनपुर, धमतरी और अनेक जगहों में। माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्य विभाग के द्वारा 6 नवंबर 2019 को एक सर्कुलर जारी हुआ है, इसमें जो उपार्जन की नीति बनाई गई है।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार के समय किसान आत्महत्या करते थे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बैठ जाता हूं, आप उनसे बोलवा लीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा।

श्री देवेन्द्र यादव :- अभी ये इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं इनकी केन्द्रीय सरकार हमारे हमारी छत्तीसगढ़ सरकार को क्यों सहयोग नहीं कर रही है, उसमें समर्थन करने के बजाय यहां राजनीति और नेतागिरी करने की बातें करते हैं।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- राजनीतिक व्यक्ति तो राजनीति करेंगे, और क्या करेंगे ?

श्री धरमलाल कौशिक :- उनका भाषण करवा लीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, आप उन्हीं का भाषण करवा लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- मैं भाषण कहां करवा रहा हूं मैं तो इनको बोल रहा हूं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, आप यादव जी का ही भाषण करवा लीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बीच-बीच में खड़े होकर बोले रहे हैं, पहली बार के विधायक हो ना, पहले इन्हीं का भाषण हो जाए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- सरकार की जो पॉलिसी है कि कोई महत्वपूर्ण विषय आए तो, मुझे यह बोलना नहीं चाहिए लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस विषय में पिछली बार जिन सदस्यों को पुकारा गया, वे अपने विषय में बोलने के लिए खड़े नहीं हुए । उस विषय में उन्होंने पांच लाईन नहीं बोला । जब भी विपक्ष से कोई भी वक्ता खड़ा होता है तो एक साथ वे खड़े होकर व्यवधान उत्पन्न करते हैं। स्थगन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर यह व्यवहार है । अध्यक्ष महोदय, किसान को इस प्रदेश का आधार स्तंभ है । यदि उस विषय में बोलने की शुरूआत हुई है तो उसमें भी राजनीति आ रही है । मैं इस बात को बोलना चाहता हूं कि 15 वर्षों तक डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही । लेकिन धान कभी विषय नहीं बना और कभी किसानों पर राजनीति नहीं की गई । यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार धान को लेकर और किसानों को लेकर राजनीति कर रही है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, ये इनकी सरकार के आंकड़े हैं, कितने किसानों ने आत्महत्या की । (व्यवधान) आप उस समय सदन में नहीं थे ।

श्री देवेन्द्र यादव :- इन्हें इनके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारी धान खरीदी 2500 रूपए समर्थन मूल्य के साथ हो ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप तय कर लीजिए और इन्हीं से बोलवाइए ।

श्री शैलेश पाण्डे :- 10 महीने हो गए मोदी जी ने समर्थन मूल्य क्यों नहीं दिया है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री देवेन्द्र यादव :- इनके कार्यकाल में हर तीसरे दिन एक किसान आत्महतया करके मरता था । उसका दुख नहीं दिखा ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- मोदी जी को समर्थन मूल्य देना चाहिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, आप तय कर लीजिए, हमें कोई दिककत नहीं है ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- प्रधानमंत्री जी से दिलवा दीजिए तो यह मामला खत्म हो जाएगा ।

श्री देवेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था आपने दी है कि जब आप खड़े होंगे तो कोई नहीं बोलेगा, जबकि ये खड़े होकर बोलते हैं । हम नये सदस्य इनके इस व्यवहार से क्या सीखेंगे ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए बैठिये ।

श्री शैलेश पाण्डे :- हमारी सरकार ने कालाबाजारी बंद कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए बैठिये ।

श्री शैलेश पाण्डे :- नहीं, यह गलत बात है । [1][XX]

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, [XX] की बात कहां से आ गई । इन्हें प्रताड़ित करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं इसको विलोपित करता हूं ।

श्री शैलेश पाण्डे :- पूरे प्रदेश में माहौल खराब कर दिया गया है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- पॉलिसी मैटर पर बात करोगे, नीति की बात करोगे तो क्या यह [XX] है ।

श्री देवेन्द्र यादव :- लोकतंत्र की हत्या हो रही है, [XX]

श्री धरमलाल कौशिक :- नये विधायकों को यही प्रशिक्षण दे रहे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष का भाषण हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं बोल ही रहा हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- हंसता हुआ नूरानी चेहरा और भाषा देख लो [XX] की बात कर रहे हैं । अरे, यहां कोई [XX] करने नहीं आया है भाई । जनता ने चुनकर भेजा है, जनता की आवाज और उनकी बात कर रहे हैं । यहां सब आदरणीय है, हमारे लिए (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- धर्मजीत भइया, मेरा अनुरोध है कि जितनी मजबूती से वे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, उतनी ही मजबूती से किसानों के पक्ष में भी बोलें । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, इनको माफी मांगना चाहिए ।

---

[1] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- वे अपने भाषण में [XX] शब्द का उपयोग कर रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- क्लास फ़ाइव की भाषा में बात करेंगे क्या ।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज़, प्लीज़ बैठिये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मतभेद हो सकते हैं लेकिन भाषा की शालीनता खत्म नहीं होनी चाहिए ।

श्री देवेन्द्र यादव :- मेरा भी धर्मजीत भइया से अनुरोध है कि वे किसानों के समर्थन में बोलें, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम न करें ।

श्री शैलेश पाण्डे :- [XX][2], ये कौन सा तरीका है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अक्ल हो तो अध्यक्ष से शिकायत करो ना । अक्ल नहीं है आपके पास । शिकायत करो अध्यक्ष महोदय से ।

श्री देवेन्द्र यादव :- मेरा निवेदन है कि आप किसानों के समर्थन में बोलिए, बी टीम बनकर काम न कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- देवेन्द्र यादव, देवेन्द्र यादव ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपको हमारे किसी आचरण से शिकायत हो तो आप अध्यक्ष से बात कीजिए, मुझसे बात नहीं कर सकते, आपको अधिकार नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- पाण्डे जी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, इस पर आपत्ति है इसमें सख्त कर्रवाई करिये।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिये । मैं आपके साथ ही सभी माननीय सदस्यों को नये आए हैं, उनको यह बताना चाहता हूं कि जब अध्यक्ष अपनी आसंदी छोड़कर खड़ा रहता है तो आपको खड़े नहीं होना चाहिए । पहले आप यह गलती स्वीकार करें । दूसरी बात, जब वरिष्ठ नेता या विपक्ष के नेता अपना भाषण कर रहे हों तो अनावश्यक टीका टिप्पणी न करें । तीसरी बात, आप सब पढ़े लिखे हैं, गुंडागर्दी जैसे शब्दों का उपयोग न किया जाए । मैं इसे विलोपित करता हूं, माननीय कौशिक जी अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अपने शब्द वापस लें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर विषय है ।

श्री देवेन्द्र यादव :- मेरा यह निवेदन है कि यह सीख सम्माननीय सभी वरिष्ठ सदस्य भी, जब आप खड़े होते हैं तो आपकी गरिमा का ख्याल रखकर, खड़े होकर टीका टिप्पणी न करें । (व्यवधान)

2 [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, यह विलोपित होना चाहिए, उनको खेद व्यक्त करना चाहिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बैठ जा, बैठ जा ।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने माननीय सदस्य का जो भाषण है उसमें से जो शब्द आपत्तिजनक थे उनको विलोपित कर दिया है और मैंने शालीन आचरण की उनसे अपेक्षा की है। यदि उसके बाद वे समझते हैं कि उनको आज माफी मांगना चाहिए, तो वे अपनी ओर से मांग सकते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह तो सरकारी संरक्षण में वह भाषा चल रही है। वे कहां खेद व्यक्त करेंगे और माफी मांगेंगे ?

श्री देवेन्द्र यादव :- क्रिया की प्रतिक्रिया होती है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अपने नेता की उपस्थिति में विधायक से ऐसी बात कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री भी उपस्थित हैं। इसका मतलब साफ है कि उनसे सरकारी संरक्षण में ऐसी भाषा बोलवाई जा रही है।

श्री देवेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, आप खड़े होते हैं तो ये सम्माननीय वरिष्ठ सदस्य लोग खड़े होकर आपकी भी बात नहीं सुनते हैं। रोक देते हैं। तो हम इन्हीं से सीख रहे हैं, लेकिन आपने जो कहा, उसका हम लोग पूरे अनुशासन के साथ पालन करेंगे।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नये सदस्यों को बार-बार यह कह रहे हैं कि आप नये सदस्यों के साथ (व्यवधान) कर रहे हैं तो इसके लिए भी इनको माफी मांगना चाहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- नेता प्रतिपक्ष के भाषण के दौरान [XX] [3] कर रहे हैं, यह सत्य कहा गया और सदन के नेता माननीय भूपेश बघेल जी उपस्थित हैं। संसदीय कार्य मंत्री भी उपस्थित हैं और दोनों के द्वारा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। यह इस बात को सिद्ध करता है कि इनके द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आपने मंत्री जी के भाषण में किसान मंत्री कैसे कह दिया?

श्री शिवरतन शर्मा :- सदन के नेता और संसदीय कार्य मंत्री सदन में मौन बैठे हैं और उनकी पार्टी के नेता, नेता प्रतिपक्ष के भाषण (व्यवधान)। इससे यह सिद्ध होता है कि आपका कहीं न कहीं संरक्षण है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- इससे यह सिद्ध होता है कि संसदीय कार्य मंत्री का संरक्षण है। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि क्या ये नरेन्द्र मोदी जी से किसानों का समर्थन मूल्य मांगने के लिए हमारे साथ चलेंगे ? अगर ये किसान के हितैषी हैं तो?

---

[3] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- यदि यह भाषण खत्म होता है और खेद व्यक्त नहीं होता है तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि संसदीय शब्दावली के फिर से पूरी परिभाषा सदन में होनी चाहिए और यह मान्य भी किया जाना चाहिए। कोई खेद व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। वे कोई नये सदस्य नहीं हैं। यह उनका तीसरा सत्र है।

श्री शिवरतन शर्मा :- सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संसदीय कार्य मंत्री जी उपस्थित हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेश पाण्डे :- अध्यक्ष महोदय, मैं खेद व्यक्त करता हूं। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार नहीं सौ बार हमारे सभी सदस्यों की तरफ से खेद व्यक्त करता हूं, लेकिन आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप 25 सौ रूपये समर्थन मूल्य के लिए हमारा सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे?

समय :

12:58 बजे **(सभापति महोदय(श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

श्री अजय चन्द्राकर :- सरकारी संरक्षण में ...।

श्री शिवरतन शर्मा :- जो भी सदस्य इस तरह की भाषा का करता है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी, बैठिए। माननीय कौशिक जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, पहले इस बात का निर्णय हो जाए। माननीय अध्यक्ष जी ने तीन निर्णय दिये, उन निर्णयों के ऊपर में सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उन्होंने सदस्य के विवेक पर छोड़ा कि वे खेद व्यक्त करना चाहते हैं या माफी मांगना चाहते हैं। उसके बाद भी सदस्य भाषण दे रहे हैं। तो इससे शर्मनाक बातें और कुछ नहीं हो सकतीं। सदन के नेता और संसदीय कार्य मंत्री जी जो कह रहे हैं कि खेद की बात है। यह तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और हम चाहेंगे कि आपकी तरफ से ऐसे व्यवहार की निंदा होनी चाहिए, जिससे कि उन सदस्यों को समझ में आये कि सदन में किस भाषा का उपयोग करना चाहिए। आपकी तरफ से निंदा प्रस्ताव आना चाहिए।

सभापति महोदय :- माननीय अध्यक्ष जी निर्णय दे चुके हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, इन माननीय वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा नये सदस्यों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, इन पर रोक लगाइए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो भी भाषा माननीय सदस्य के द्वारा माननीय नेता प्रतिपक्ष के बारे में बोली गई है। जो भी व्यवस्था आई है, बस विलोपन की आई है। ठीक है विलोपित हो गया, लेकिन सदन के नेता और संसदीय कार्य मंत्री यहां हैं। यदि उस भाषा में

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सरकार पक्ष नहीं बोलता है, ये वरिष्ठ लोग नहीं बोलते हैं तो सीधे तौर पर यह माना जायेगा कि वह भाषा विधान सभा में स्वीकार कर ली गई और उसके प्रति यदि कोई खेद व्यक्त नहीं हो रहा है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप फिर से संसदीय शब्दावली परिभाषित कीजिए। इस विधान सभा का स्तर इस शब्दावली से है। इस तथ्य को लगातार कह रहे हैं। (व्यवधान) इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते। यह सदन इस बात के लिए नहीं चाहेगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- (व्यवधान) सदन में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न करते हैं। चन्द्राकर जी का चेकअप करवाइए। ये बार-बार सदन में गड़बड़ करते हैं।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, आसंदी से व्यवस्था आ गई है। किसानों के गंभीर मुद्दों को लेकर यह सरकार गंभीर है। इसके लिए चर्चा कराना चाहते हैं, मगर हमारे सम्माननीय विपक्ष के साथी बार-बार व्यवधान डालना चाह रहे हैं। सरकार गंभीर है, यह सदन गंभीर है। हम चर्चा करना चाहते हैं। मगर किसानों के मुद्दे पर विपक्ष के साथियों को राजनीति करना है, वे किसानों के प्रति गंभीर नहीं हैं। हम, सदन चर्चा करना चाहती है, बार-बार चर्चा करना चाहती है।

श्री अजय चन्द्राकर :- गाली बको, गाली बको। .....(व्यवधान)

सभापति महोदय :- शिवरतन जी, बैठिये। .....(व्यवधान)

डॉ0 (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- यह असंसदीय व्यवहार का नमूना है। .....(व्यवधान)

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी बैठिये, ननकीराम जी बैठिये, आप बैठिये, मैं देख रहा हूँ। (व्यवधान) आप लोग बैठिये। बृहस्पत सिंह जी बैठिये। यादव जी बैठिये। बघेल साहब, बैठिये। देखिये, माननीय अध्यक्ष जी ने माननीय सदस्य से शालीन आचरण की बहुत स्पष्ट अपेक्षा की है। दूसरी बात, माननीय सदस्य ने खेद व्यक्त कर दिया है। ऐसी स्थिति में ...(व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- आप रिकार्ड निकलवा लीजिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के भाषण में गुण्डागर्दी करने की बात आई। सदस्य ने खेद व्यक्त नहीं किया और आसंदी से व्यवस्था आई। माननीय सदन के नेता भूपेश बघेल जी उपस्थित हैं, माननीय ससंदीय कार्यमंत्री जी उपस्थित हैं। क्या वे सदस्य की भाषा से सहमत हैं ? सहमत हैं या असहमत हैं ? आप बताये। कहीं न कहीं आपकी सहमति है।

श्री बृहस्पत सिंह :- उससे ज्यादा तो आप कर रहे हैं। आपके नेता प्रतिपक्ष का भाषण हो रहा है और आप लगातार बोले जा रहे हैं। सभापति महोदय, जब नेता प्रतिपक्ष को बोलना है, माननीय सदस्य सुपरसीट कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- नहीं, ऐसा नहीं है। आप बैठिये, आपकी बात आ गई है। आप बैठिये, आप बैठिये। जोगी जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजीत जोगी (मरवाही) :- माननीय सभापति महोदय, मेरा नाम लिया गया है। सभापति जी, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से बड़ी विनम्रता से, पूरे सदन से निवेदन कर रहा हूँ कि सम्माननीय संबंधित सदस्य प्रकाण्ड विद्वान हैं। एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं। उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया, हम सबकी दृष्टि से वह उपयुक्त नहीं था। उस पर आसंदी से व्यवस्था आ गई है। एक गंभीर विषय पर चर्चा होनी है। मैं माननीय सदस्य से फिर अनुरोध करूंगा कि इस शांत वातावरण में वे खड़े होकर अपने शब्दों को वापस ले लें, माफी मांग लें। नये सदस्य हैं। आगे की कार्यवाही शांतिपूर्ण हो। हम बड़े ही गंभीर विषय पर , जिसका प्रदेश के किसानों से सम्बन्ध है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। टोका-टाकी न हो। एक-दूसरे को सुने और सरकार का पक्ष भी सुने।

सभापति महोदय :- ठीक है। अब देखिये, माननीय सदस्य ने खेद भी प्रकट कर दिया है और माननीय अध्यक्ष जी ने ..।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, रिकार्ड निकलवा लीजिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष जी ने विलोपित कर दिया है।

सभापति महोदय :- विधान सभा की कार्यवाही में है। मैंने कार्यवाही देख ली है। अब मैं प्रकरण को समाप्त करता हूँ। माननीय कौशिक जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति जी, कैसी कार्यवाही है ? आप कैसी कार्यवाही देख लिए, हम तो सुने ही नहीं हैं और न आंख से हमको दिखा। अब आप कहां से देख लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।

सभापति महोदय :- रिकार्ड दिखवा लिया।

श्री धर्मजीत सिंह :- न हमको आंख से दिखा न कान से सुनाई दिया।

सभापति महोदय :- माननीय कौशिक जी, मैंने रिकार्ड देख लिया। आप कृपया चालू करे।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, आप माननीय इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। आपने उनका नाम पुकारा। नाम पुकारने के बाद उन्होंने जिन शब्दों से माननीय सदस्य से अपेक्षा की, उसके बाद माननीय सदस्य यदि इतने के लिए भी तैयार नहीं हैं तो मैं बहुत द्रवित हूं, मैं बहुत दुखी हूं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- नेता जी, अध्यक्ष जी की व्यवस्था आ गई, उसके बाद ये बात कहां से आ गई ।

सभापति महोदय :- बृहस्पत सिंह जी, आप बैठिए ।

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, मैं तो पूरे विस्तार से चर्चा करना चाहता था, लेकिन मेरा बोलना यदि [XX][4] है तो मैं इस बात से दुखी हूं, मैं नहीं बोलना चाहता । मेरे दल के बाकी सदस्य बोलेंगे, कृपया मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं ।

श्री अजीत जोगी :- एक बार फिर से बोल दो ।

श्री शिवरतन शर्मा :- चलिए, कोई नहीं बोलेगा । अगर आपका कहना [XX] है तो ये [XX] इनको मुबारक हो । (व्यवधान)

श्री अजीत जोगी :- मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि आपका शब्द रिकार्ड में जरूर आया, पर लोगों ने नहीं सुना । हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया खड़े होकर एक बार फिर से बोल दें ।

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, सम्मानीत सदस्य....

श्री अजीत जोगी :- आपको नहीं बोल रहा हूं, सम्माननीय विद्वान सदस्य को बोल रहा हूं ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय सभापति जी, सदन आपकी भी बात को सुनेगा, हमारी भी बात को सुनेगा । आपने स्थगन रखा, सरकार की ओर से उत्तर आयेगा, चर्चा होगी । आप सबको अपनी बात कहना है, हमको भी कहना है । माननीय धरम भैया, जब आप विधान सभा अध्यक्ष थे, एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं । माननीय मूणत जी यहां बैठे थे, सदन 7 दिन से इसी प्रकार मांग कर रहा था, तब आपने आसंदी से कहा था कि उसके विवेक पर छोड़ता हूं, खेद व्यक्त करे या न करे, लेकिन आसंदी से आपने व्यवस्था दी थी कि सदन चलाना हम सबकी जवाबदारी है इसलिए मैं खेद व्यक्त करता हूं, उसके बाद सदन बहुत सुचारू संचालित हुआ था। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, सदन के नेता हैं । हम सबका, हम सबका, मेरा आशय अपने को जोड़ते हुए मतलब हम सबका दायित्व आप सबका सम्मान करना है । कभी उत्तेजना में कोई बात हो जाती है, सदस्य के खेद को सुन नहीं पाए तो एक बार चूंकि माननीय आसंदी ने विलोपित कर दिया है...।

श्री अजीत जोगी :- फिर से बोलना दीजिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय जोगी जी, मैं कह रहा हूं । सदस्य की तरफ से क्या, मैं खुद संसदीय कार्यमंत्री होने के नाते मैं उसकी तरफ से खेद व्यक्त करता हूं । हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में किसानों का मसला है, प्रतिपक्ष से सुझाव आयेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपनी बात कहेंगे, हम लोग पूरे प्रदेश के हित के लिए अगर दोनों पक्ष बैठे हैं तो हमारी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं अलग हो सकती हैं, लेकिन आसंदी ने स्थगन ग्राह्य किया है तो सब चर्चा के लिए तैयार हैं । मैं नये सदस्यों से भी कहना चाहता हूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी अपनी बात कहेंगे तो हम लोग ध्यान से सुनें और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं । आप इतना जल्दी नाराज हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा । ये

[XX][4] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

नये सदस्य हैं । आपको ज्यादा उदार होना है इसलिए मैं संसदीय कार्यमंत्री होने के नाते मैं खेद व्यक्त करता हूं और मैं आपसे चाहूंगा कि बहुत अच्छे से बहस हो, चर्चा हो और आप अपनी तरफ से भाग लें । माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से मैं आग्रह करता हूं ।

श्री शैलेश पाण्डेय :- सभापति महोदय, इसमें मैं कुछ कहना चाहता हूं...

सभापति महोदय :- पाण्डेय जी, बैठिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अब तो बात हो गई । अब माफी मांगने का कोई औचित्य नहीं है, संसदीय कार्यमंत्री जी ने खेद व्यक्त कर दिया है । जब उनको माफी मांगना था तो पहले ही मांग लेना था । अब वह विषय समाप्त हो गया ।

माननीय सभापति महोदय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्त संरक्षण विभाग के द्वारा धान खरीदी को लेकर 6 नवम्बर, 2019 को एक परिपत्र जारी हुआ । इसमें धान खरीदी के संबंध में दिया गया है कि कामन धान 1850 रूपये प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए 1835 रूपये प्रति क्विंटल और मक्का का 1760 रूपये प्रति क्विंटल दिया गया है । फिर उसके बाद में इसकी समयावधि 1 दिसम्बर, 2019 से 15 फरवरी, 2020 तक दिया हुआ है और प्रति एकड़ 15 क्विंटल दिया हुआ है । सभापति महोदय, इसके पूर्व छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डा. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और 1 नवम्बर से धान खरीदी की जाती थी । किसानों का भुगतान किया जाता था क्योंकि 1 नवम्बर हमारे छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस एवं राज्योत्सव है और ये माना जाता था कि राज्योत्सव मतलब छत्तीसगढ़ के अन्नदाता हमारे किसान हैं और उसका यह उत्सव है इसलिए राज्योत्सव से धान की खरीदी सुनिश्चित व्यवस्था हो । किसान धान कटाई करते थे, सोसायटियों में, सहकारी समिति में बेचने का काम करते थे और उनके धान का विक्रय है, जो समर्थन मूल्य है, उसके अनुसार उनको राशि मिल जाती थी । एक बार 15 नवम्बर को धान की खरीदी हुई, तब उस समय तत्कालीन प्रदेश कांग्रेसके अध्यक्ष, भूपेश जी थे, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री है । उन्होंने डॉ. रमन सिंह जी को सलाह दिया, उन्होंने पत्र लिखा, 15 नवम्बर के बजाय 1 नवम्बर को धान खरीदी होनी चाहिये । 1 नवम्बर को धान की खरीदी प्रारंभ हो तो पिछले वर्ष डॉ. रमन सिंह जी ने मुख्यमंत्री के रूप में 1 नवम्बर से धान की खरीदी की व्यवस्था शुरू कर दी । आज पूरे प्रदेश में आप जिधर भी जायेंगे, धान कटाई का काम चल रहा है । माननीय सभापति महोदय, आजकल जो पहले प्रथा रही है, पहले कटाई करना, फिर खलिहान में लाना, फिर उसको मिजाई करना, फिर कोठी में रखना, फिर सोसायटी में ले जाना, वह प्रथा अब समाप्त हो गई है । न आपको गांव में खलिहान मिलेगा, न घर में कोठी मिलेगी । ऐसे स्थिति में किसान, जहां कटाई करते हैं, यदि हार्वेस्टर है तो हार्वेस्टिंग करने के बाद सीधा सोसायटी में ले जाते हैं, यदि खेत में कटाई करते हैं तो थ्रेशर ले जाते हैं, थ्रेशर से मिंजाई करने के बाद में सीधा सोसायटी में ले जाते हैं । हमारे यहां

छत्तीसगढ़ में दशहरा के बाद और दीपावली के आसपास धान कटाई शुरू हो जाती है । मैं पूरे प्रदेश में जहां पर दौरा किया हूँ, सभी तरफ धान कटाई प्रारंभ हो गयी है । किसान अपने धान को थ्रेशर और हार्वेस्टिंग करने के बाद में अब उस धान को जहां पर सोसायटियों में ले जाना चाहिये । जो उनको 2500 रूपये मिलना चाहिये, आज किसान के सामने में जो स्थिति उत्पन्न है, यदि प्रदेश में सबसे कोई लाचार दिखाई दे रहा है, प्रदेश में सबसे कोई हलाकान है, प्रदेश में सबसे यदि कोई परेशान है, वह है प्रदेश का अन्नदाता किसान । माननीय सभापति महोदय, इतने दु:खी है, जब मण्डी में ले जा रहे हैं तो खरीदने को तैयार नहीं है । जब व्यापारी के पास ले जा रहे हैं तो खरीदने को तैयार नहीं है, अपने धान को सड़क में बिछकर आ गये, ऐसी हालत किसानों की छत्तीसगढ़ में कभी नहीं हुई है, जो इस सरकार में किसानों की हालत हो रही है । माननीय सभापति महोदय, मैंने बिलासपुर कलेक्टर से बात किया । पथरिया में एक हमारे जो समस्या निवारण शिविर लगा हुआ था, खाद्य विभाग के अधिकारी से मैंने बात की, कलेक्टर से मैंने यह पूछा, जो किसान अपने घर से निकालकर मंडी में ले जा रहे हैं, उसके धान को जब्ती कर रहे हैं । यह किसान अपने धान को कहां ले जाकर बेचे ? आप उसका स्थान नियत कर दीजिए । मैंने कहा आप मुख्यमंत्री से बात कर लीजिए । मैंने कहा आप उस विभाग के अधिकारियों से बात कर लीजिए । आप चीफ सेक्रेटरी से बात कर लीजिए । यह तय करिये कि आखिर धान को किसान कहां बेचे ? लेकिन आज तक कलेक्टर का जवाब नहीं आया । वह खाद्य विभाग के अधिकारी का जवाब नहीं आया है । आखिर किसान अपने धान को ले जाकर कहां बेचे ? मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी का इसमें जवाब आयेगा कि किसान अपने धान को कहां ले जायें ? हालत क्या हो रही है? आप 25 सौ रूपये देने वाले हैं, माईक में दहाड़-दहाड़ के बोल रहे हैं, अरे भईया हमने तो कहा नहीं था कि 25 सौ रूपये में किसानों का धान खरीदो । आज जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, किसान को समस्या बता रहे हैं, धान को समस्या बता रहे हैं, वास्तविक में सभापति महोदय, न इस प्रदेश के लिए किसान समस्या है, न इस प्रदेश के लिए धान समस्या है, समस्या है कांग्रेस का घोषणा पत्र । जन घोषणा पत्र में इन्होंने दोनो हाथ फैलाकर और हाथ में गंगा जल लेकर उन्होंने कहा कि किसान भाईयों आप हमको वोट दीजिए, हमारी सरकार आप बनायेंगे, तो हम 25 सौ रूपये में हम आपके धान को खरीदेंगे । दो साल का आपको बोनस देंगे, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि 25 सौ रूपये में खरीदेंगे, आपको न प्रेस लेने की जरूरत है, न आपको दहाड़ने की जरूरत है, न आपको बोलने की जरूरत है । आपने घोषणा किया, आपके घोषणा पत्र को आपको लागू करना है । इसमें किसान बीच में कहां से आ गये ? किसान की नीयत ठीक है, उन्होंने तो आपको वोट दिया । वोट देने के बाद में उन्होंने अपना वचन निभा दिया । अब आपको वचन अपना निभाना है तो अपना वचन निभाने के लिए आपने राजनीति शुरू कर दिये । माननीय सभापति महोदय, इसके बाद में क्या हो रहा है । जब किसानों के लिए हम लोगों ने

धरना प्रदर्शन किया, इस बात के लिए हम लोगों ने आवाज उठाई कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है और उनको एक क्विंटल में 1000 रूपये से लेकर 1300-1400 रूपये तक कम पैसे मिल रहे हैं। आप 2500 रूपये प्रति क्विंटल बोल रहे हैं, 1800 रूपये आपने इसमें कहा है, आपने बीच में संभाग आयुक्त को पत्र भी भेज दिया, अब जब वह सोसायटी में लेकर जायेंगे तो मुझे नहीं मालूम कि आपने दूसरा परिपत्र जारी किया या नहीं किया। आखिर वह बीच की राशि का वहां पर क्या करेंगे? जब वह सोसायटी में 2500 रूपये में खरीदी की रशीद कटवायेंगे तो उस समय क्या स्थिति बनेगी वह भी अस्पष्ट है। किसान का धान आज पानी के मोल 1200, 1300 रूपये में और मंडी में 1500 रूपये की रशीद कटी है। यदि 2500 रूपये प्रति क्विंटल का हिसाब लगायेंगे तो एक क्विंटल में 1000 से 1300 रूपये तक की उसको हानि है। आप एक एकड़ में 15 क्विंटल धान खरीद रहे हैं तो कितना हो गया? एक एकड़ में एक किसान को 15 हजार से 18 हजार रूपये की जो कमी होगी इसकी भरपाई सरकार करने वाली नहीं है। मैंने तो कभी किसानों के साथ इतना अन्याय नहीं देखा कि किसान को एक एकड़ में 15 हजार से 18 हजार रूपये का नुकसान हो। आज क्या स्थिति बनी हुई है? पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है कि किसान अपने धान को लेकर जाए तो जाए कहां। हमारे कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और उन्होंने कहा कि गांव-गांव जाकर धान खरीदेंगे, किसानों का एक-एक दाना धान खरीदेंगे, 15 क्विंटल की सीमा भी खत्म होगी, यह हमारे कृषि मंत्री जी की वार्ता है। कृषि मंत्री जी, वादा निभाने का समय आ गया है। एक-एक दाने की बात तो छोड़िए, 15 क्विंटल धान खरीदने की बात को छोड़िए आप तो तारीख भी तय नहीं कर पा रहे हैं। आपकी सोयायटी में एक दिसंबर से खरीदी हो आज उसकी भी व्यवस्था नहीं है। आजकल मोबाईल में मिसकॉल बहुत आते हैं और उस मिसकॉल में यह दिया जाता है कि आप पैसा जीत गये, आप अपना कोड नंबर भेज दीजिए और जब कोड नंबर भेजते हैं तो उसकी जो जमा राशि है उसे भी वह लोग निकाल लेते हैं। तो इसी प्रकार से सरकार ने अपना कोड जारी किया कि हम 2500 रूपये देंगे, 2500 रूपये देंगे और लोगों ने कोड के रूप में अपना वोट दे दिया और वोट देने के बाद आज जब खरीदने की बारी आई तो उनका जमा हिस्सा एक क्विंटल में 1000 रूपये से 1300 रूपये इस सरकार ने निकाल लिये। ये सरकार की हालत है कि यह सरकार ऑनलाईन ठग बन गई। ये ठगने का काम इस प्रदेश में शुरू हुआ है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- नेता जी, हम तो 2500 रूपये देना चाहते हैं लेकिन उस मिस्ड कॉल की हेकिंग केन्द्र में मोदी जी की तरफ से हो गयी है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। उसको थोड़ा रिलीज करवा दीजिए, हम लोग तो पूरा 2500 रूपये में खरीदने को तैयार हैं।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- पूछकर घोषणा किए थे क्या? घोषणा पत्र के समय मोदी जी से पूछे थे क्या?

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, दूसरी बात जब डॉ. रमन सिंह जी से आप अपेक्षा किए कि 1 नवंबर से धान की खरीदी करें, उन्होंने धान की खरीदी की, तो आप 1 दिसंबर से खरीदी की ओर क्यों जाना चाहते हैं? इसका कोई कारण आपके पास है? आज किसान को एक माह में 2 प्रतिशत सूखती आ रही है यानी एक क्विंटल में 2 किलो। एक किलो की दर 25 रूपये है तो दो किलो की दर 50 रूपये हो गई। इस प्रकार एक एकड़ का 30 किलो सूखत हो गई। इस प्रकार एक एकड़ में किसान को जो 750 रूपये का सूखत घाटा हो रहा है उसकी देनदारी कौन करेगा? आखिर किसान ने इनको वोट देकर कौन सा पाप किया है कि जिसका भुगतान आज उनको भुगतना पड़ रहा है? ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, जहां अन्नदाता का सम्मान होना चाहिए, किन्तु इस सरकार के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है, मैंने आपको कहा कि खलिहान की व्यवस्था समाप्त हो गई है, कोठी की व्यवस्था खत्म हो गई है, अब किसान अपने धान की कटाई करके उसके लिए अब मजदूर लगा रहे हैं। अपनी रोजी लगाकर उसकी रखवाली कर रहे हैं। वह 1 दिसंबर तक उसकी रखवाली करेंगे। मैं सरकार को इसमें एक सलाह देना चाहता हूं कि आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप किसान के धान को खरीद लीजिए। आप 1 दिसंबर से पेमेंट करने वाले हैं, आप किसान के धान को खरीदकर तौल करा लीजिए और उसका 50 प्रतिशत पेमेंट अभी कर दीजिए और आपके पास जब पैसा हो जाए तो बाकी पेमेंट आप बाद में कर दीजिए। इससे किसानों को शोषण से रोका जा सकता है। औने-पौने मोल में जो किसान धान बेच रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं, यह किसान को बचाया जा सकता है। इसलिए सरकार को यदि आपके पास पैसा नहीं है, यह बात सही है, हम लोग स्वीकार करते हैं, अब पता नहीं 21 हजार करोड़ रूपये का कर्जा या 22 हजार करोड़ रूपये का कर्जा ले रहे हो। आप कर्जा लीजिए लेकिन किसानों का भुगतान आप अभी 50 प्रतिशत कर दीजिए। उनके धान को आप खरीद लीजिए, धान का अपमान मत करें, ये न केवल किसान का अपमान है, यह धान का भी अपमान है। यदि लक्ष्मी कहा गया है तो किसान का लक्ष्मी धान है। धान का अपमान करेंगे तो आपको उस प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। मैं इस बात को आपको कहना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में पहली बार आपकी सरकार थी क्या आप भूल गये ? आपने क्या किया ? सभापति महोदय, पहली बार सरकार में क्या किया ? उस समय किसानों के धान को डूबा-डूबाकर पानी में देखा। किसानों ने ऐसा डूबा-डूबाकर दिया कि 15 साल बाहर रखे। दोबारा गलती आप फिर कर रहे हो। इस बार यदि डूबाकर देखोगे और किसानों का अपमान करोगे तो इस बार 15 साल के लिये नहीं 25 साल के लिये जाओगे। किसान का प्रकोप यह 25 साल के लिये आपको सहना पड़ेगा। इसलिए आप किसान का अपमान करना छोड़िए। केवल इतना ही नहीं है, बल्कि यह जो बात करते हैं कि कहां से अपने वचन को निभाने के लिए, अरे भैया मैं तो संविधान में ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं देखा हूं। वास्तविक में सरकार की घोषणा पत्र नहीं है, चौबे जी, यह आपकी सरकार की भी घोषणा पत्र नहीं है। यह घोषणा

पत्र को कांग्रेस की घोषणा पत्र है। शायद कांग्रेस के घोषणा पत्र में उस समय इनको विश्वास नहीं थी कि हमारी सरकार बनेगी। जब इतने बड़े राष्ट्रीय पार्टी चला रहे हो और आपको धान खरीदी करना है तो अकबर जी बैठे हुए हैं, उसका हिसाब-किताब तो लगाये होंगे। उसमें कितना खर्चा आयेगा। यह पैसा हम कहां से ले करके आयेंगे ? हमको दो साल का बोनस देना पड़ेगा। 2500 रूपये हमको किसानों को भुगतान करना है। यह बात विचार किये होंगे लेकिन मुझे लगता है और यह प्रमाणित है कि इनको लगा कि सरकार तो आ नहीं रही है, जो बोलना है बोल दो और आ गया तो देखेंगे, वहीं हाल हो गयी है। आपको 2500 रूपये घोषणा करने के लिए किसने कहा था ? 2500 रूपये घोषणा करने के लिए जनता ने नहीं कहा था। मैंने इसलिए कहा था कि किसानों के उपर राजनीति मत करो। जब आपने कहा है तो आप हिसाब-किताब लगाये होंगे और आप उसका हिसाब-किताब लगा करके दिये होंगे, किसान को न मोदी जी से मतलब है, न किसान को आपसे मतलब है, छत्तीसगढ़ के किसान को अपने 2500 रूपये से मतलब है। यह उनका हक है हर किसानों के साथ खड़े हुए हैं। यह 2500 रूपये उनका हक है। यह 2500 रूपये उनको देना पड़ेगा। इसके लिये आपको बार-बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय :- माननीय कौशिक जी, कितना समय और लेंगे ?

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, अभी तो शुरू किया हूं।

सभापति महोदय :- 12 मिनट हो गया है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय भाटो जी, आप मेज थपथपा रहे थे, उन्होंने कहा कि किसान को मोदी जी से मतलब नहीं है और आप खुश हो रहे थे। (हंसी)

श्री ननकीराम कंवर :- सभापति महोदय, देखिये मतलब तो आपसे ही है। इसलिए की 2500 रूपये है। अभी तो एक घोषणा है, अभी तो हजारों घोषणा की बात चलेगी।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति महोदय, मोदी जी अगर सुनेंगे न कि वे मोदी जी को किसान से कोई मतलब नहीं करके नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे हैं। आप खुश हो रहे हो करके...। (व्यवधान)

श्री ननकीराम कंवर :- सभापति महोदय, आप उसको भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- सभापति महोदय, संकल्प पत्र में भाटो जी को जर्शी गाय देने वाले थे अभी तक मिला नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, आज मैं जो बता रहा था कि जिस प्रकार से धान के साथ और उसी प्रकार से गन्ना के साथ में पिछली बार जो गन्ना की खरीदी की है, आज भी उसका भुगतान नहीं हुआ है। (शेम-शेम की आवाज) केन्द्र के द्वारा 261 रूपये का समर्थन मूल्य घोषित किया गया। उसके साथ में 50 रूपये लाभांश, उसके साथ में रियायत दर पर किसान को शक्कर और

आज जब इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया तो 355 रूपये का जारी किया। लेकिन आज कहते हुए इस बात का दुख हो रहा है कि 261 रूपये के हिसाब से भी भुगतान नहीं हुआ है। आप अंबिकापुर का शक्कर कारखाना देख लीजिए। 250 रूपये के हिसाब से भुगतान हुआ है। 261 रूपये भी नहीं दिया है। आप कवर्धा जा करके देख लीजिए किसान कितने आक्रोश में हैं। जब वहां धरना-प्रदर्शन हुआ तो अभी इसका भुगतान हुआ है और उसमें भी उनका लाभांश नहीं मिला, 355 के हिसाब से नहीं मिला है। जब आपने अपना जनघोषणापत्र बनाया, उसका पालन तो आपको करना है और इसलिए छत्तीसगढ़ के किसान उसके हकदार हैं। उस छत्तीसगढ़ के किसान को उसका हक मिलना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनके साथ में है। कल जब सरकार में थे तब भी उनके सहभागी थे और आज भी हैं।

माननीय सभापति महोदय, सम्मान निधि के रूप में जो 6 हजार रूपये की राशि दी जाती है। केवल इस सरकार की अव्यवस्था के कारण आज भी 15 लाख किसान हमारे उस राशि से वंचित हैं। अभी पूरी राशि नहीं मिली है। केवल 15 लाख किसानों को राशि मिलने की संभावना है। यह केवल कुव्यवस्था और अव्यवस्था के कारण हुआ है। माननीय सभापति महोदय, केवल उतना ही नहीं, आज जिस प्रकार से इस सरकार में किसानों की दुर्गति हो रही है और यह सरकार किसानों की हालत बिगाड़ कर रखी है। अब प्रश्न यह है कि संसदीय कार्यमंत्री, कृषि मंत्री खुद खेती करते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय चौबे जी कृषि कार्य करते थे।

श्री धरमलाल कौशिक :- वे कृषि कार्य करते थे नहीं। वे कृषि कार्य करते हैं। मैं माननीय चौबे जी को मानता हूँ कि वे कृषि कार्य करते हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- और हम कृषि कार्य जीवनभर करेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- डॉ. साहब, क्योंकि मैं उनका देखा हूँ कि वह बात करते रहते हैं कि इस साल क्या स्थिति है? वे फसल का आंकलन करते रहते हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय शिवरतन शर्मा जी नहीं जानते हैं। हम लोग अभी भी कृषि कार्य करते हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय शिवरतन जी फसल खरीदते हैं और आप बेचते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- सुनिये। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, इस प्रदेश में सबसे पहला पम्प कनेक्शन, वर्ष 1961 का मेरा है। आप पता कर लीजिए। मेरा पूरा परिवार खेती पर ही आश्रित है और मैंने हल भी जोता है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, कृषि मंत्री जी, मैं एक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 16 तारीख से मेरे यहां बिल्हा में 10-15 गाड़ी खड़ी हुई है। मण्डी वाला उसको जप्त करके ले गया है। अब उस धान का क्या होगा? उस परिवहन का क्या होगा? ये तो एक जगह का उदाहरण बता

रहा हूँ। ऐसे पूरे प्रदेश में मामला है और उसके बाद में यह परिस्थितियां हैं कि जो 1 हजार में धान खरीदे, जो 1300-1500 रूपये में धान खरीदे, ये मानकर चलिए कि वह धान केवल अपने लिए नहीं खरीदे हैं जो खरीदे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ कि आखिर 1 दिसम्बर को यह सरकार क्यों धान के निर्धारित समय सीमा को बढ़ाई है, उसके पीछे कारण है इनको मालूम है कि जो हमारे छोटे किसान हैं उनकी क्षमता नहीं है कि वह धान को रोक सकें, औने-पौने में बिचौलिये के हाथ में बेचे और जब यह किसान का धान बिचौलियों के हाथ में चले जाए तो ये सरकार बिचौलिये को ढाई हजार रूपये देने के लिए बैठी हुई है, उस आश्वासन के साथ में बिचौलिये धान खरीद रहे हैं। ये कोई धर्मार्थ का काम नहीं कर रहे हैं। ये 1000 रूपये और 1300 रूपये में किसानों का धान खरीदे। मैंने जब पूरे किसानों से बात की और निष्कर्ष में आया । आखिर 1 दिसम्बर बढ़ाने की क्या आवश्यकता थी? जब एक नवम्बर में धान खरीदी होती है। उसके अंतर्गत भी बहुत बड़ी साजिश है, इस सरकार की बहुत बड़ी चाल है और इसी कारण जो किसान के हाथ में पैसा जाना चाहिए, वह किसान के हाथ के बजाए बिचौलियों के हाथ में जाने वाला है क्योंकि बिचौलिये को तो ढाई हजार रूपये मिलेगा। हमारे किसान के हाथ में 1000-1300-1500 रूपये आएगा। ये सरकार चल रही है।

माननीय सभापति महोदय, आज मेरे पास पूरे प्रदेश की कतरन है। जब आपको सीमा बंदी करनी चाहिए तो आप सीमा एरिया में कीजिए कि यहां पर आंध्रा का धान मत आये, यहां पर महाराष्ट्र का धान मत आये, यहां पर झारखण्ड का धान मत आये। यहां पर मध्यप्रदेश का धान मत आये।

सभापति महोदय :- कौशिक जी, आप कितना समय और लेंगे?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, ये बिल्हा में जो दगौरी से 6 किलोमीटर है वहां नाकेबंदी कर रहे हैं। जहां नाकेबंदी करना चाहिए वहां का धान तो ला रहे हैं, लेकिन कहां कर रहे हैं ? बेलतरा हमारे विधायक रजनीश कुमार सिंह जी का क्षेत्र है। उनके क्षेत्र के धान को बिलासपुर आना है तो बेलतरा से बिलासपुर आ रहा है, वहां नाकेबंदी कर रहे हैं। मंत्री जी, आप थोड़ा सा विचार कीजिए। आप किसान हैं। आप सीमावर्ती एरिए में नाकेबंदी लगाईये। हम आपके साथ हैं। क्योंकि यहां के जो सरकार के पैसे हैं, वह हमारे किसानों को मिलना चाहिए। लेकिन आप जो नाकेबंदी कर रहे हो, आप लोकल किसान के लिए कर रहे हो। आखिर आप क्या करना चाहते हैं? आप किसान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहते हैं? किसान ने धान उत्पादन कर लिया तो क्या उसने पाप किया है? आप किसान को बीच चौराहे में लाकर खड़ा कर दिये।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य का भाषण जारी रहेगा। सभा की कार्यवाही भोजन अवकाश के लिए अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित।

(1.30 से 3.01 बजे तक अंतराल)

समय :

3:01 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)**

<u>स्थगन प्रस्ताव (क्रमश:)</u>

अध्यक्ष महोदय :- माननीय कौशिक जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकारी दीर्घा खाली है, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। हम सब आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- अधिकारी दीर्घा मुख्यमंत्री के डर से खाली है।

श्री धरमलाल कौशिक :- मुख्यमंत्री जी के डर से खाली नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अधिकारी दीर्घा आपके डर से खाली है या और किसी कारण से खाली है?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जिसको सुनाना चाहते हैं वह तो नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि अभी तक तो हम लोग सोच रहे थे कि कौशिक जी किसी और की बात मानकर कुछ काम करते हैं, लेकिन अभी पता चल रहा है कि डायरेक्शन तो पीछे तरफ से आ रहा है, शिवरतन शर्मा जी की तरफ से आ रहा है और नेता प्रतिपक्ष जी को बैठे-बैठे डायरेक्शन दे रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धान के पंजीयन का जो समय था, उस समय के अंदर में आवेदन पत्र जमा किया गया और आज पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में एस.डी.एम., तहसील कार्यालय में प्रपत्र जमा हैं, लेकिन उसके बाद भी धान की खरीदी के लिए उनका पंजीयन नहीं हुआ। निर्धारित समयावधि के अंतर्गत 11/10/2019 को जमा किये हैं, एक नहीं अनेक किसान हैं। मैं आपको दो-चार लोगों के नाम पढ़कर बता देता हूं। ये कवर्धा सूखाताल के हैं- परमानंद, राजकुमार सूखाताल, गौकरण, भगवानी सूखाताल, फरसराम, ईश्वर, संतोष, बनवा, नकुल भूकरसा, सहदेव, जगदीश भूकरता, गंगोत्री बाई, सनतकुमार घुघरी, यह केवल उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, उनका पंजीयन है। बंडल तहसील कार्यालय में रखा हुआ है। बंडल रखने के बाद भी किसान परेशान है, चक्कर लगा रहे हैं। आज अधिकारी यह बता रहे हैं कि आपका पंजीयन का समय समाप्त हो गया है। क्या यह किसान की गलती है? मैं इसमें आग्रह करना चाहता हूं कि जो किसान निर्धारित अवधि के अंदर में अपना आवेदन प्रोफार्मा के साथ में जमा किये हैं, उन सारे किसानों की धान खरीदी की व्यवस्था होनी चाहिए। केवल पंजीयन नहीं है, इस आधार पर उसके धान की खरीदी न हो और उनके धान को अस्वीकृत कर दें, ये उचित नहीं है। ऐसे लगभग पूरे प्रदेश में सभी तहसील कार्यालयों में प्रपत्र रखे हुए हैं।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। विपक्ष में जो काम करते हैं, उस काम को सत्तापक्ष ने अपने हाथों में ले लिया है, सांसदों के घर में ढोल बजाना। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो क्या सांसदों ने घोषणा-पत्र जारी किया कि हम 2500 रुपये में धान की खरीदी करेंगे और आप हमको वोट दीजिए? वास्तविक में सांसदों के घर में ढोल बजाने की आवश्यकता नहीं है। मोहन मरकाम जी, आप ढोल बजवाओ कि जागो मुख्यमंत्री जागो और अपने वादा को निभाओ और अपने कार्यकर्ता को बोलो कि मुख्यमंत्री जी के घर के सामने ढोल बजाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- ढोल या नंगाड़ा।

श्री धरमलाल कौशिक :- नंगाड़ा । सांसदों के घर बजाने की जरूरत नहीं है । क्योंकि वायदा आपका है इसलिए यह ढोल और नंगाड़ा मुख्यमंत्री जी के घर के सामने बजना चाहिए । मैं तो इस बात को सुनकर हैरान हुआ कि सांसदों के घर के सामने नंगाड़ा बजाएंगे । आखिर प्रदेश में आप क्या तमाशा करना चाहते हैं । आप किसको दोष देना चाहते हैं ? अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए आप सांसदों के घर नंगाड़ा बजाएंगे ? यदि हमारे सांसदों ने चुनाव के पूर्व घोषणा पत्र जारी करते या मौखिक रूप से भी उन्होंने कहा होता कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके धान को 2500 रूपए में खरीदेंगे तो आपको अधिकार था । लेकिन आप अपने वचन को निभाने के बजाय, अपने वायदे को निभाने के बजाय सांसदों पर थोपना चाहते हैं । आप अपने घोषणा पत्र को किस-किस पर थोपना चाहते हैं ? क्यों थोपना चाहते हो आप ?

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय नेता जी, ये लड़ाई किसके लिए है ? लोग किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं ?

श्री धरमलाल कौशिक :- मैंने पहले ही बता दिया कोई लड़ाई नहीं है, आपकी बारी आएगी तब आप बोलना ।

श्री बृहस्पत सिंह :- नेता जी, 2500 रूपए देने से आपको तकलीफ है क्या? आप दिलाना नहीं चाहते क्या ?

श्री धरमलाल कौशिक :- किसान का अधिकार है, किसान को 2500 रूपए मिलने चाहिए, हम किसान के साथ खड़े हुए हैं ।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- यही पूछने तो जा रहे थे, सांसदों से । आप किसानों की तरफ हैं या नहीं हैं ?

श्री धरमलाल कौशिक :- हम सदन में बोल रहे हैं और जवाबदारी के साथ बोल रहे हैं । आप जैसे टरकव्वल नहीं कर रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- इसीलिए निवेदन कर रहा हूं कि मोदी जी से बोलिए । हुजूर छत्तीसगढ़ को 2500 रूपया दीजिए, छत्तीसगढ़ का धान खरीदिए । उनसे बोलने में क्या डर लग रहा है ? यदि आपको डर लगता है तो हम भी आपके साथ चलने को तैयार हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अभी तो शुरूआत है, बोलने के लिए आपको कई अवसर मिलेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का जो स्थगन है वास्तव में प्रदेश के किसानों के हित में लाया गया है और केवल 1 नवम्बर के बजाय 1 दिसम्बर करने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है । इसलिए बाजार में अफरा-तफरी का माहौल और किसानों के बीच जो परिस्थितयां निर्मित हुई हैं, प्रदेश में किसान जो परेशान और बेहाल है और केवल इस सरकार की नीति के कारण है । यदि ये नीति को सुधार लेंगे तो सारी व्यवस्था हो जाएगी । इसलिए आज विधान सभा की बैठक समाप्त होने के पहले ही निर्धारित अवधि में मैंने जिन दो-तीन बातों का उल्लेख किया कि पैसा भले ही आज न दें, लेकिन खरीदी की व्यवस्था आज सुनिश्चित कर दें। भले ही दिसम्बर में पैसा दे दिया जाए, तो हम किसानों को शोषण से बचा सकते हैं । इसलिए इस स्थगन में यह चर्चा करने के बाद मुझे लगता है कि चर्चा के समापन के पूर्व यह बात आ जाना चाहिए जिससे किसानों को लाभ मिले ।

अध्यक्ष महोदय, वास्तव में हम किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए बैठे हैं । यदि मुख्यमंत्री जी अपने आपको किसानों का हितैषी और किसानों का मसीहा समझते हैं तो जिस प्रकार वोट लेते समय आपने कहा, आज इस स्थगन के समाप्त होते होते आप धान खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित कर देंगे । मुख्यमंत्री जी, बहुमत के अहंकार में आने की जरूरत नहीं है ।

अहंकार न करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है ।
शीशा वही रहा है, तस्वीर बदलती रहती है ।

इसको स्वीकार करते हुए आप अपने वायदे को निभाएं, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद ।

श्री रविन्द्र चौबे :- ये आपको पीछे प्राप्त हुआ है क्या ?

श्री भूपेश बघेल :- ये लाइन बगल वाले के लिए थी, वे नहीं हैं इसलिए नेता जी बोल पाए । आपने अपना भाषण दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद् । अहंकार जैसी कोई बात नहीं है, मैं नमस्कार करता हूं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- इस बार का नेता जी का भाषण निर्भीक होकर दिया गया भाषण था ।

श्री शिवरतन शर्मा :- ये भाषण आपके लिए समर्पित होने वाला है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सदन में हैं और आपके प्रदेश अध्यक्ष जी प्रथम वक्ता हैं, लगता है कि आपके विधायकों और मंत्रियों को यह नहीं मालूम है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहन मरकाम (कोंडागांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा स्थगन के माध्यम से किसानों का मुद्दा, धान खरीदी का मुद्दा लेकर चर्चा प्रारंभ की गई है । सरकार ने किसानों के इस मुद्दे को लेकर चर्चा पर सहमति दी है और आपने सहमति दी है इसलिए आपको दिल से धन्यवाद् । माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने 15 साल तक किसानों को ठगा, जो किसानों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं वे आज किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं । आज हम 15 साल का रिकार्ड देखते हैं। 15 साल में लगभग 14 हजार किसानों ने आत्महत्या की है। छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने जो कहा, उसे दो घण्टे के अंदर पूरा किया। छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार और हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री 17 दिसंबर को शपथ ग्रहण करते हैं और शपथ ग्रहण करने के बाद 2 घण्टे के अंदर पहला अगर दस्तखत करते हैं तो छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं के लिए करते हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिये जो वायदे किये थे। हमने किसानों का कर्ज माफी करने का लगभग 11 हजार करोड़ रूपया कर्ज माफ, लगभग 20 हजार किसानों का कर्जा माफ करने का निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है। देश की पहली सरकार छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार है जो लगभग 11 हजार करोड़ रूपये कर्ज माफ किया। छत्तीसगढ़ के 1 लाख करोड़ रूपये बजट में 38 हजार करोड़ रूपये बजट सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं के लिए व्यवस्था करने की अगर किसी सरकार में हिम्मत है तो माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार की है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने 80 लाख मीट्रिक टन धान छत्तीसगढ़ के लगभग 20 हजार करोड़ रूपये में धान खरीदे। आज देश के किसी भी कोने में किसी भी सूबे की सरकार 2500 रूपये में धान नहीं खरीदती। कांग्रेस की सरकार जो कहती है, वह करती है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मोहन जी, आप यह बता दो कि धान की जो जब्ती हो रही है, वह सही हो रही है क्या? पूरा प्रदेश का किसान इसके माध्यम से मूल्य लेगा। आप इससे सहमत है?

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, बता दूं कि 4 हजार क्विंटल आपके एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के राइस मिल से उत्तर प्रदेश की सीमा में जब्त हुआ है। क्या वह भी गलत हुआ है क्या ?

श्री मोहन मरकाम :- आप हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार देश की पहली सरकार है जो आज किसानों आज किसानों का धान समर्थन मूल्य में इतने में खरीद रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस घोषणा पत्र की माननीय नेता प्रतिपक्ष कौशिक साहब आप बात करते हैं। क्या आज आपको 2003 का संकल्प पत्र याद है? भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ। आप 15 साल सरकार में रहे। आपने कितने किसानों का कर्जा माफ किया? हमारी सरकार ने जो कहा, वह दो घण्टे के अंदर कर दिया। ऐसी सरकार देश के किसी भी कोने में नहीं है। (मेजों की थपथपाहट) आज हमारे 11 महीने की सरकार ने जो कहा है, वह किया है। कौशिक साहब, क्या आपको

2013 का संकल्प पत्र याद है? किसानों को हम 2100 रूपये समर्थन मूल्य देंगे और 300 रूपये बोनस देंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप एक मिनट बैठेंगे। आप मुझे जो बार-बार बोल रहे हैं न। आपके मुख्यमंत्री की स्थिति यह हो गई है कि बड़ी बात तो बोल दिये कि कर्जा माफ करेंगे, परंतु उनका चेहरा देखने लायक था कि जब वे बोले कि हम एक बार कर्जा माफ कर दिये और कितनी बार कर्जा माफ करेंगे ? वे इतना झल्लाना शुरू हो गये हैं और आप उसके कसीदा पढ़ रहे हैं। (हंसी)

श्री मोहन मरकाम :- मैं भारतीय जनता पार्टी का 2013 का भी संकल्प पत्र याद दिलाना चाहता हूं। 2100 रूपये समर्थन मूल्य देंगे। 300 रूपये बोनस देंगे। वर्ष 2013-14 का बजट भाषण तत्कालीन मुख्यमंत्री का 5 साल तक किसानों का एक-एक दाना धान खरीदेंगे। सरकार बनने के बाद 2013 का मुख्यमंत्री जी का हिस्ट्री निकाल लीजिए। मैंने पूरा डिटेल निकाला है। आपने कैसे धान खरीदा? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 2013 का संकल्प पत्र डॉ. मनमोहन सिंह से पूछकर बनाये थे कि 2100 रूपये समर्थन मूल्य देंगे। 300 रूपये बोनस देंगे। आज मोदी जी से पूछकर बनाने की बात कर रहे हैं। सांसदों से पूछकर बनाने की बात कहते हैं। हमारी सरकार ने जो कहा है, उसे पूरा किया है। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के 37 लाख किसानों के उन्नति और प्रगति के लिए काम कर रही है। आज हम देखते हैं कि पूरे देश में मंदी का असर है, मगर छत्तीसगढ़ में मंदी का असर नहीं है। आज हम देख रहे है कि सरकार की नीतियां लगातार यहां के लिए काम कर रही है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। छत्तीसगढ़ के 80 प्रतिशत किसानों की खुशहाली के लिए, उनकी समृद्धि के लिए छत्तीसगढ़ के माननीय भूपेश बघेल की सरकार लगातार काम कर रही है। आज उसी का असर है कि जहां डॉ0 मनमोहन सिंह की सरकार के समय पूरे देश में जी0डी0पी0 7 प्रतिशत से अधिक हुआ करता था, वहीं मोदी जी के राज में जी0डी0पी0 5 प्रतिशत है। पूरे देश में कल-कारखाने बंद हो गए हैं। 90 लाख से अधिक कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। मगर आज छत्तीसगढ़ में साढ़े पांच लाख से अधिक रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। आज ही इण्डिया टुडे का रैंकिंग आया है जिसमें समावेशी विकास में छत्तीसगढ, देश का पहले नंबर का राज्य बना है। (मेजों की थपथपाहट) आज छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज छत्तीसगढ़ के विकास में कांग्रेस की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आते ही "छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा, घुरवा, गरूवा, बाड़ी एला बचाना हे संगवारी।" आज छत्तीसगढ के गौरवशाली इतिहास और गौरवशाली परम्परा के साथ-साथ उस बात को चिन्हित करने का काम कर रही है। आज उसी का परिणाम है कि हमारी सरकार लगातार काम कर रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, आप उसको हाथ में गोदना गुदवा लो।

श्री शिवरतन शर्मा :- मरकाम जी, उसमें एक शब्द और जोड़ लो। नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी पी के रहव मस्त संगवारी।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को नेतागिरी करने का अवसर नहीं मिला। आज ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आज मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज किसानों के गंभीर मुद्दे पर सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज बात आ रही है, आज माननीय वरिष्ठ सदस्य बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे थे कि किसानों की स्थिति बदहाल है। आज छत्तीसगढ़ का किसान खुश है। आप सबको पता है कि वर्ष 2017-18 में 15,75,645 किसानों ने पंजीयन कराया था। मगर आज छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों के कारण पिछले वर्ष से 3 लाख अधिक किसानों ने पंजीयन करवाया है।(मेजों की थपथपाहट) आज हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जहां 37 प्रतिशत गरीबी थी, लेकिन 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 41 प्रतिशत की दर से गरीबी बढ़ी।

श्री केशव चन्द्रा :- रकबा कितना बढ़ा है ?

श्री मोहन मरकाम :- जहां पिछले 15 सालों में मजदूरों की संख्या बढ़ी थी। मगर आज हमारी सरकार बनने के बाद मजदूरों की संख्या घटी है और किसानों की संख्या बढ़ी है। माननीय अध्यक्ष जी, लगातार बातें आ रही हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने क्या कहा कि आपको किसानों का प्रकोप लगेगा। भारतीय जनता पार्टी को किसानों का प्रकोप लगा है। इसीलिए 90 सीटों में से 14 में आकर सिमट गई। जब 2003 में चुनाव हुआ तो हम 33 सीट पर थे। 2008 के चुनाव में 38 सीट पर थे और 2013 के चुनाव में 39 सीट पर थे। मगर किसानों का प्रकोप इन्हें लगा है। इन्होंने किसानों को ठगा है इसीलिए 14 सीटों पर आकर सिमट गए हैं। आज छत्तीसगढ़ में किसान खुश हैं। आज माननीय भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ के किसान बधाई दे रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ सरकार की नीति की, नीति आयोग तारीफ कर रही है। आज छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियां की 7 समुन्दर पार संयुक्त राष्ट्र में तारीफ हो रही है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये समाप्त कीजिये।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहला वक्ता हूँ। आपका सरंक्षण चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री मोहन मरकाम :- बस, मैं 10 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। आज छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार काम कर रही है। रही बात सांसदों के घरों में नंगाड़ा बजाने का, ये छत्तीसगढ़ के वही किसान हैं, जो मोदी जी के बहकावे में आये । मोदी जी ने कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे । मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से, भारतीय जनता पार्टी

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि वही छत्तीसगढ़ के किसान हैं, जो 11 लोकसभा सीटों में 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीताकर भेजा । आज मोदी जी जगाने की जरूरत है, जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बात की थी और किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी । आज किसानों की आय दोगुनी करने की बात तो दूर, जब 2013 तक डा. मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो वे हर साल किसानों को बोनस देते थे, छत्तीसगढ़ के पुल का चांवल भी खरीदते थे, वहीं मोदी जी से 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन किया था कि छत्तीसगढ़ को बोनस देने की छूट दी जाये । आज छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को बोनस देना चाहती है तो मोदी जी को तकलीफ क्यों हो रही है ? हम तो वही मांग कर रहे हैं कि केन्द्रीय पुल का लगभग 32 लाख टन चांवल केन्द्र सरकार खरीदे और हम छत्तीसगढ़ के किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं, उसकी भी परमिशन दे । छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार अपने संकल्प पर दृढसंकल्पित है, भले कर्ज लेकर छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं का धान 25 सौ रूपए में खरीदना पड़े, वह हम खरीदेंगे । (मेजों की थपथपाहट) छत्तीसगढ़ में 15 सालों में क्या हुआ ? छत्तीसगढ़ में नान और धान का बहुत खेल हुआ । हमने 15 सालों में देखा कि यहां तो 36 हजार करोड़ का नान घोटाला हुआ । छोटी मछली को तो आपने अंदर कर दिया, मगर सी.एम., सी.एम. मैडम और पी.ए. लोगों का नान घोटाले में नाम था, मगर बड़ी मछलियां बाहर है, छोटे मछलियों को आपने अंदर कर दिया । भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह धान और नान का खेल चला था । हमारी सरकार किसानों के लिए लगातार काम कर रही है । आज हम देखते हैं तो किसानों के चेहरे खिले हुए हैं । माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया, सरकार की ओर से जवाब आया । किसानों के धान उत्पादन के रकबा में जबरदस्त बढ़ोत्तरी हुई है । हमारे मंत्री जी ने जो जवाब दिया था, उसमें भी उल्लेख है कि छत्तीसगढ़ में जबरदस्त धान के रकबे में बढ़ोत्तरी हुई है । हमने पिछले साल देखा है कि जो रबी का फसल हो या खरीफ का फसल हो, बड़े-बड़े उद्योगपतियों को तो पानी देते थे, मगर हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि गर्मी की फसल के लिए भी छत्तीसगढ़ के किसानों को पर्याप्त पानी देगी, यह एक ऐतिहासिक निर्णय है । आज ये लोग किसानों की चिंता करते हैं । हमारी सरकार 11 महीने की सरकार है, जो किसानों के लिए लगातार काम कर रही है ।

समय :
3:24 बजे

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति जी, सेन्ट्रर फॉर मानीटरिंग इंडियन इकानॉमी की एक रिपोर्ट आई है । देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, मगर छत्तीसगढ़ में लगातार रोजगार के अवसर छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार कर रही है । चाहे गोठानों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से हो, लगातार काम कर रही है ।

हम देखते हैं कि लगातार जो बातें आई हैं, केन्द्र की रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर घटाकर जहां 7 प्रतिशत हुआ करती थी, आज वह 5.6 प्रतिशत यहां की जीडीपी है । छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो केन्द्र की माननीय मोदी जी को छत्तीसगढ़ की सरकार से सीखना चाहिए, वहां के वित्तमंत्री जी को छत्तीसगढ़ की सरकार से सीखना चाहिए कि वित्तीय प्रबंधन कैसे किया जाता है । छत्तीसगढ़ के संसाधन, छत्तीसगढ़ के बजट का, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कैसे काम कर सकती है । माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नान घोटाले के आरोपी हैं, उन्होंने पिछली सरकार पर लगातार आरोप लगाया है । उन्होंने 21 लाख से अधिक फर्जी राशन कार्ड बनाकर छत्तीसगढ़ के संसाधनों का दुरूपयोग किया । माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले वही कहना चाहता हूँ कि आज छत्तीसगढ़ के किसान बहुत खुश है । छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था किसानों के इर्द-गिर्द घूमती है । इसीलिए हमारी सरकार ने, माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने, एक वित्त मंत्री के रूप में आज छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को, मजबूत करने का काम किया, आज 38 हजार करोड़ रूपये जनता के बीच में गया है, तो वही राशि मार्केट में भी गई, व्यापारी भाईयों के पास गया, आटोमोबाईल सेक्टर में गया, अन्य के पास में गया, इसीलिए छत्तीसगढ़ की स्थिति अच्छी है । हमारी सरकार ने आते ही जो 206 करोड़ रूपया सिंचाई कर था, उसे माफ किया । इसीलिए आज छत्तीसगढ़ का किसान बहुत खुश है । माननीय सभापति महोदय, आज यहां की गूंज चेन्नई में गूंजती है । आज वहां के किसान मिठाई बांटते हैं, फटाका फोड़ते हैं । देश की ऐसी भी सरकार है, जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार, जो हिम्मत करती है, 25 सौ रूपये धान की कीमत देने की किसी में हिम्मत है तो कांग्रेस की सरकार में है, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में है । सभापति महोदय, मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथियों को, सम्मानित सदस्यों को कांग्रेस सरकार के लिए धन्यवाद करना चाहिये । घड़ियाली ऑंसू बहाने से कुछ नहीं होता । कांग्रेस की सरकार, किसानों के सुख में दु:ख में खड़ी है, छत्तीसगढ़ के 37 लाख किसानों की उन्नति और प्रगति के लिए काम कर रही है, इसके लिए धन्यवाद देना चाहिये । अब विपक्ष के साथियों से कहूंगा कि घडियाली ऑंसू बहाना छोड़ दें । सभापति महोदय, हमारी सरकार 11 महीनों में ही किसानों की तस्वीर और तकदीर बदलने जा रही है और आने वाले 4 साल तथा 1 महीने में छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए लगातार काम करेंगे । छत्तीसगढ़ के किसान आज छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं । छत्तीसगढ़ के किसान स्वयं को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं । माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- माननीय श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी ।

श्री अजीत जोगी (मरवाही) :- धन्यवाद, सभापति जी । मैं सच में अपनी बात धन्यवाद और प्रशंसा से प्रारंभ करना चाहता हूँ । यद्यपि स्थगन मैंने भी दिया है, धन्यवाद और प्रशंसा इस बात की

कि बारम्बार हमारे मुख्यमंत्री दोहरा रहे हैं कि परिस्थितियां जो भी बनें, पर धान 25 सौ रूपये क्विंटल ही खरीदा जायेगा । इसलिए अपने वादे को पूरा करने की जो अभिव्यक्ति है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ ।

श्री केशव चन्द्रा :- मरकाम जी धन्यवाद दे दिये ना ।

श्री अजीत जोगी :- इसके आगे भी सुनो ना केशव । पर मैं कहना चाहूंगा सभापति जी, माईक दूर है, इसलिए मुझे जोर से बोलना पड़ रहा है । जोर से बोलने की आदत नहीं है । ऐसे समय में जब एक चुनौती हमारे सामने हो तो किसी ने ठीक कहा है-

उनको ए साहिरा, मंजिल अपनी मिलती नहीं
जिनको तूफां में भी किनारों का ख्याल आता है
जोर डूब जाते हैं वे जोर तलातुम में
जिनको तूफां में भी सहारों का ख्याल आता है

चुनौती है, तूफान है, किनारे और सहारे हमको नहीं ढूंढ़ने हैं, उसका सामना करके जो वादा किया है कि 25 सौ रूपये में धान खरीदेंगे, वह पूरा करना है । इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि चूंकि पक्ष और विपक्ष की बात चल रही है, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, हमारे प्रतिनिधि भी गये थे, उसमें हमने ये वायदा किया था कि केंद्र से मदद मांगने के लिए, केन्द्र से चावल खरीदने के लिए आप जो भी आंदोलन करेंगे, जो भी कदम उठायेंगे, उसमें हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आपने तब ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे। वह संभव नहीं हो पाया। उसके बाद हमने सुना आपने कहा था कि 100-150 बसें ले जायेंगे और दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे, घेराव होगा, धरना होगा, प्रदर्शन होगा पर ये वायदा/ये संघर्ष भी आप नहीं कर पाये। तूफां में किनारे मत ढूढिए, तूफां में सहारे मत ढूंढिए। आपने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी का घेराव करेंगे, पी.एम. का घेराव करेंगे, पी.एम. के घर के आगे नगाड़े बजायेंगे पर पी.एम. की जगह बदल दिया और अब एम.पी. के घर के आगे नगाड़े बजायेंगे। मैं प्रदर्शन के खिलाफ कभी नहीं रहा पर मैं ये बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि ये तो केवल आज सांसदों के घर में प्रदर्शन की बात हो रही है कि हमको कोई भी प्रदर्शन किसी के घर में जाकर नहीं करना चाहिए। ये सच्चा लोकतंत्र नहीं है। घर में केवल सांसद नहीं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं इसका भी ख्याल रखना चाहिए। हमें बापू ने प्रदर्शन के बहुत से तरीके सिखाए हैं। बापू का एक आंदोलन बता दीजिए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के बंगले में जाकर प्रदर्शन किया हो या गवर्नर जनरल के घर के सामने प्रदर्शन किया हो, या गवर्नर के घर के आगे प्रदर्शन किया हो? बापू ने प्रदर्शन के, आंदोलन के रास्ते बनाये हैं उन्हें ही हमें अख्तियार करना चाहिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है बापू जी को इन्होंने दो दिन में श्रद्धांजलि देकर समाप्त कर दिया। बापू जी को श्रद्धांजलि हो गई।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय नाथूराम गोडसे जी ने जो सिखाया वही करेंगे ना।

सभापति महोदय :- देखिए, चंद्राकर जी का गोडसे से कोई संबंध नहीं है।

श्री बृहस्पत सिंह :- ये मुझे प्रमाण पत्र दिखा रहे थे कि देखिए मेरे गोडसे के साथ संबंध थे।

श्री अजीत जोगी :- सभापति महोदय, मैं बृहस्पत सिंह जी से कहना चाहूंगा कि टोकाटाकी अच्छी होती है पर यदाकदा टोकाटाकी हो तो अच्छी होती है अन्यथा टोकाटाकी करने वाले टोकाटाकी करते हुए ही सदन से बाहर चले जाते हैं और कोई उनको स्मरण नहीं करता। तैयारी से, समझदारी से, बुद्धिमत्ता से अगर बात कही जाए तो वह बात याद रखी जाती है। तो टोकाटाकी करें मुझे एतराज नहीं है पर कम करें ऐसी मेरी सलाह है।

श्री बृहस्पत सिंह :- इनको कहा था सर। आपको टोक रहे थे इसलिए कहा था सर।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं टोंका थोड़ी हूं, समर्थन में बोला हूं।

श्री अजीत जोगी :- मैं आपका समर्थन भी नहीं चाहता हूं। (हंसी) ये भी हमने सुना कि 15-20 लाख किसानों के पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखे जायेंगे और ले जाकर प्रधानमंत्री जी को देंगे। अब कल या परसों मैंने पढ़ा कि अब प्रधानमंत्री जी को नहीं देंगे, राज्यपाल महोदया को दे देंगे। तो इससे क्या आपको केंद्र की सहायता मिल जायेगी? मैं अपनी खुद की प्रशंसा में नहीं कहना चाहता पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और जो मेरे साथ मंत्री रहे हैं चौबे जी, अकबर जी, प्रेमसाय सिंह टेकाम हैं इन सबको याद दिला रहा हूं, सभापति महोदय आप भी थे कि देश में पहली बार धान की खरीदी जब मैं मुख्यमंत्री बना तब करने का फैसला हमने लिया था। इसके पहले देश क्या विश्व में भी धान की खरीदी नहीं होती थी। उस समय केंद्र सरकार की नीति नहीं थी कि धान की खरीदी का चावल हम खरीदें। हम लोगों ने फैसला किया उसमें आदरणीय भूपेश जी भी शामिल थे, मैंने मंत्रिमंडल में यह बात रखी कि हर हालत में हमारे किसान का शोषण हो रहा है, उसको बिचौलिये से, व्यापारी से आधी कीमती मिलती है, खड़ी फसल खरीद लेता है। हम उसको पूरी कीमत देंगे और धान खरीदेंगे। हम दिल्ली गये, आप सब साथ थे, आदरणीय अटल जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मिलने से इंकार किया। हम लोग पैदल चलकर उसमें हम लोग करीब 50-55 लोग थे, सारे कांग्रेस के विधायक थे, सारे मंत्री कांग्रेस के थे और मुख्यमंत्री, हम पैदल चलकर प्रधानमंत्री जी के घर तक गये, जैसा अपेक्षित था, आपको हमको रोका गया, आपको हमको गिरफ्तार करके तुगलक रोड थाने में एक दिन बंद रखा गया। पूरे देश में टेलीविजन पर दिखाया जाने लगा कि संवैधानिक संकट हो गया है। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री और पूरी सरकार गिरफ्तार है। उसके बाद आदरणी अटल जी ने हम लोगों को फिर से बुलाया, बात की समझाया। बड़ी अच्छी से एक घंटे बात

हुई। चौबे जी को याद होगा, उन्होंने समोसा और जलेबी दोनों खिलाया था और उसके बाद यह कह दिया, जोगी जी व्यापार करना हमारा काम नहीं है। किसान बेचेगा और व्यापारी खरीदेगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, मैं धान खरीदने के लिए आपको पैसा नहीं दे सकता। हम लोग वापस आये, आपको याद होगा मैंने कहा, नंदकुमार जी थे, चौबे जी थे, भूपेश जी भी थे, आपसे कहा कि आप लोग रायपुर वापस जाओ। आप लोग सरकार चलाओ। मैं तब तक रायपुर वापस नहीं आऊंगा, जब तक किसानों के लिए धान खरीदने के पैसे का इंतजाम नहीं कर लूंगा। मैं विशेष वायुयान लेकर बंबई गया। बंबई में रिजर्व बैंक और और अन्य बैंकों से बात करके कर्ज की व्यवस्था की। पहली बार उस कांग्रेस सरकार ने देश में पहली बार धान खरीदी की। मैंने यह घटना इसलिए याद दिलाया कि आप सब लोग भी उपस्थित थे, धनेन्द्र साहू भी उपस्थित थे। आज अगर हमको केन्द्र से सहायता प्राप्त करनी है तो नरेन्द्र मोदी जी को आईना भेजकर, नरेन्द्र मोदी जी के खिलाफ व्यक्तिगत आक्षेप लगाकर क्या हम उनको सहमत कर लेंगे कि हमारा चावल खरीदें? मेरा आपसे यह निवेदन है कि संकट है, मुझे मालूम है 30-35 हजार करोड़ रूपये चाहिए, आप अपने साधन से खरीद भी लेंगे तो इस धान का क्या करेंगे यदि केन्द्र एफ.सी.आई. नहीं खरीदे ? चावल बन जायेगा उसका क्या करेंगे ? मैंने मुख्यमंत्री जी का एक बयान पढ़ा, मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं। आपने आई.बी.सी. की इंटरव्यू में कहा कि हम धान से पेट्रोल बनायेंगे। ये तो नोबेल पुरस्कार मिल जायेगा, अगर कोई धान से पेट्रोल बनायेगा तो। धान से पेट्रोल नहीं बन सकता। इतना चावल कन्जूयम करने के लिए हम क्या करेंगे ? इसीलिए मैंन वह शेर कहा कि - तूफां में किनारा और सहारा मत ढूंढिये। चलिये अपन सब चलते हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगा और मैं सोचता हूं कि आदरणीय रमन सिंह भी आपके साथ चलेंगे। बात करने में क्या है ? हम लोग सब चलकर बात करें, हल कुछ निकलना चाहिए। मोदी जी ने एक बाद कही है, बोले हमने मेरी चर्चा उनके प्रमुख सचिव से हुई थी, उनका एक ही कहना है कि हमारी नीति है, हम पूरे देश में एक ही भाव पर खरीदेंगे। देश के लिए हमने एक भाव निर्धारित किया है। वह भी उन्होंने कहा कि हमने निर्धारित नहीं किया, एक एक्सपर्ट की कमेटी है जो एम.एस.पी. (Minimum support price) for all food grains. गेंहूं, चने, चांवल, धान का भी, जितने food grains हैं उनकी कीमत को तय करते हैं। उसमें बड़े कृषि विशेषज्ञ होते हैं, कुछ किसान, व्यापारी भी होते हैं। वह सब लोग मिलकर तय करते हैं और इस साल उन्होंने तय कर दिया कि धान का समर्थन मूल्य 1815 रूपये, 1845 रूपये होगी। उनका ये तर्क है कि अगर एक प्रदेश से ज्यादा में खरीद लेते हैं तो पूरे देश में असंतुलन की स्थिति बन जाएगी। आंध्र वाले कहेंगे कि छत्तीसगढ़ 2500 रूपये में खरीद रहा है। रेड्डी जी आप 2500 में क्यों नहीं खरीद रहे हैं ? तेलंगाना वाले कहेंगे राव साहब, आप 2500 रूपये में क्यों नहीं खरीद रहे हैं? बिहार में नीतिश जी से कहेंगे कि आप क्यों नहीं खरीद रहे हैं ? उत्तरप्रदेश में योगी जी से कहेंगे कि आप भी 2500 रूपये में खरीदीए। उनका उत्तर ये है कि हम

किसी एक राज्य को अधिक में खरीदने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, पर मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि यह नीति बहुत पहले से बनी है। आपने हमने धान खरीदी चालू की, उसके बाद रियम्बर्समेंट की नीति बाद में चालू हुई। तब से यह लगातार डॉ. मनमोहन सिंह जी के जमाने से चली आ रही है, पर जब चुनाव आसन्न था भारतीय जनता पार्टी के दोस्त नाराज न हों, इनको जब अपनी परिस्थिति अच्छी नहीं दिखी तो इन्होंने जिद्द की और एक्सेप्शन किया गया, केवल छत्तीसगढ़ के लिए अपवाद किया गया और समर्थन मूल्य से ऊपर डॉ. रमन सिंह जी की सरकार को बोनस देने की अनुमति दी गई। हमारे सामने यह उदाहरण है। जब आप एक बार अपवाद कर सकते हैं तो दूसरी बार भी अपवाद कीजिए। छत्तीसगढ़ और कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जिसकी 80 प्रतिशत अर्थव्यवस्था केवल धान की खेती पर आधारित है। ये जो बात निकली कि मंदी का असर हमारे यहां ज्यादा नहीं पड़ा है, यह पड़ा है नोटबंदी का असर पड़ा है, जी.एस.टी. का असर पड़ा है उस विषय पर मैं अभी नहीं आना चाहता, पर अगर बहुत कम असर पड़ा तो उसका एक कारण यह था कि श्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने 2500 रूपये में धान खरीदी।(मेजों की थपथपाहट) किसान के पास पैसा आया। मैंने सोनारों से पूछा, देवभोग के एक सोनार से पूछा उसने मुझे बताया, अभी पुजारी जी नहीं है, उसने मुझे बताया। मैं अभी उनका नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अभी उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल से 2500 रूपये मिलने के कारण देवभोग जैसे छोटे शहर में सोने की खरीदी दो गुना ज्यादा हुई। (मेजों की थपथपाहट) वैसी कपड़ा, बर्तन, फर्नीचर खरीदे तो हमारी अर्थव्यवस्था यू.पी., बिहार, पंजाब या हरियाणा वाली अर्थव्यवस्था नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था मोनोक्राप्ड एरिया की अर्थव्यवस्था है धान का मूल्य मिलेगा तो किसान, व्यापारी, उद्योगपति भी मालामाल होगा और हमारे बेरोजगार भी रोजगार पायेंगे। इसलिए हमारी स्थिति बिल्कुल अलग है। समय कम बचा है, पर अभी भी हम सब को मिलकर प्रयास करना चाहिए और मैं यह भी बात कहना चाहूंगा कि मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूँ। आपने भी शराब बंदी का वायदा किया था, हमारी पार्टी ने भी किया था। मैं अभी आंकड़े देख रहा था अभी तक शराब से आपकी सरकार ने 36 हजार करोड़ रूपये कमाये हैं और धान में कितना लगने वाला है? 25000-30000 करोड़ रूपये। इन महीनों में 36 हजार करोड़ रूपये की शराब बिकी है और छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्रति व्यक्ति शराब पीने की जो दर है, हमसे पहले तमिलनाडु, पंजाब आता था। इन 11 महीने में प्रति व्यक्ति शराब की खपत छत्तीसगढ़ में नंबर एक है। अगर शराबबंदी नहीं करना है तो अपने पैसे से किसान का धान तो खरीदो। 25 हजार करोड़ रुपये, 30 हजार करोड़ रुपये लगेंगे। शराब से खूब कमाओ, लोगों को खूब शराब पिलाओ, शराबबंदी नहीं करके, शराबमंडी बना दी। पर मैं ये कहता हूं कि आपने वादा किया, भाजपा, जनता कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या नरेन्द्र मोदी जी ने वादा नहीं किया। वायदा केवल आप लोगों ने नहीं किया, केवल आप लोग करते तो शायद ये आप 70 सीट पर आ

गये हैं, नहीं आते। आपकी पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी आये और जहां भी गये, उन्होंने ये कहा।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें। आपने 10 मिनट कहा था, 15 मिनट हो गये हैं।

श्री अजीत जोगी :- मैंने 10 मिनट कभी नहीं कहा, मैं तो यदा-कदा बोलता हूं।

सभापति महोदय :- चलिये संक्षेप में कर लीजिए। यहां पर बोलने वालों की काफी लंबी सूची है।

श्री अजीत जोगी :- तो एकाध दिन और चलने दीजिए।

सभापति महोदय :- वह तो सदन जैसा चाहेगा, वैसा चलेगी, लेकिन आप कृपया संक्षिप्त कर लें।

श्री अजीत जोगी :- चलिये, मैं बहुत संक्षेप में बोलने की कोशिश करूंगा। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वायदा आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया कि अगर 10 दिन के अंदर कर्ज माफ नहीं होगा और 2500 रुपये में धान खरीदी नहीं होगी तो मैं मुख्यमंत्री को बदल दूंगा। ये वादा आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया था। मैं इस वादे को याद दिला रहा हूं और आपसे ये कह रहा हूं कि केन्द्र से पैसा मिले, यह मैं भी चाहता हूं। उसके लिए हम संघर्ष करें, ये मैं भी चाहता हूं। पर अगर नहीं मिलेगा और ज्यादा उम्मीद ये है कि नहीं मिलेगा, तो भी आपने वादा किया है तो निभाना पड़ेगा और 2500 रुपये में धान खरीदना पड़ेगा। सभापति महोदय, आपने मुझे संक्षेप में बोलने के लिए कहा है, इसलिए मैं केवल एक बिन्दु और बताना चाहता हूं। वह बिन्दु यह है कि यह जो धान खरीदी की तारीख आपने बढ़ाई है इससे हाहाकार मच गया है। मैं पिछले दिनों भाटापारा, तखतपुर, मुंगेली और पथरिया तक यह देखने गया कि धान की खरीदी कैसे हो रही है, क्या हो रहा है? मैंने भाटापारा की मंडी में 5 आदमी भेजे कि जाकर देखो और बताओ कि मंडियों में किस मूल्य पर धान खरीद रहे हैं। मुझे तकलीफ हुई, वेदना हुई कि 1300 रुपये, 1400 रुपये, 1600 रुपये में मंडी में धान खरीद रहे हैं। वह 15 दिन इंतजार नहीं कर सकते। यह 15 नवंबर की तारीख और उसके पहले 1 नवंबर की तारीख हमने, आपने सोच, समझ के तय की थी। क्योंकि हरहुन धान जल्दी कट जाता है और जो किसान दूसरी फसल लेता है, उसको दोहरी आवश्यकता होती है। उसको काटने की मजदूरी देना है, यदि हार्वेस्टर से करा रहा है तो उसे मिसने का खर्चा देना है और उसे नई फसल के लिए बीज, खाद, दवा चाहिए। तीज, त्यौहार दीवाली निकल गई, उसमें भी उसने उधार लिया। उसको तत्काल पैसे की जरूरत है, इसलिए वह मजबूरी में 1300 रुपये में धान बेच रहा है। मुझे यह बताया गया कि जब से छापे की कार्यवाई चालू हुई है तो इतना आतंक फैल गया है कि अब 1 हजार रुपये में भी खरीदने वाला नहीं मिलता। सड़क में फेंकना चालू हो गया है, धमतरी के लोग बतायेंगे। खरीददार नहीं मिले तो धमतरी में लोगों ने धान सड़क में फेंक दिया। मेरा तो यह कहना है कि आज तो 25 तारीख ही हुई है, हमारी बात सुनकर, मानकर 26, 27 तारीख से भी चालू कर देंगे तो किसान इतनी तकलीफ में नहीं आयेगा। मैं ये भी कहना

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

चाहूंगा । मैं यह भी कहना चाहूंगा, केवल एक सुझाव है उस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए कि केवल धान पर आधारित अर्थव्यवस्था क्या हमारे लिए लाभदायक है? अंग्रेजी में एक बहुत पुरानी कहावत है - पैडी एण्ड पावर्टी, गो-टूगैदर । जहां केवल धान होगा, वहां गरीबी अवश्यमेव होगी । इसलिए हम लोगों ने फसल चक्र परिवर्तन चालू किया था । इसको गंभीरता से लीजिए । जो किसान कवर्धा में धान पैदा करता था, वहां शक्कर की मिल खोल दी, 10 हजार रूपए एकड़ धान का मिलता था, आज गन्ने में एक बार लगाता है, 3 साल चलता है । 1 लाख रूपया एकड़ मिल रहा है । मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं । राजनांदगांव के यादव नाम के किसान ने आकर मुझे बताया कि उसने एक एकड़ में मुनगा लगाया और मुनगे को लगातार चेन्नई भेजा और एक एकड़ के पीछे 15 लाख रूपया कमाया । मैं कोंडागांव में रूका था, कोंडागांव के आदरणीय विधायक जी बताएंगे, एक आदिवासी किसान ने मुझे बताया 4 एकड़ में उसने 1 करोड़ रूपया कमाया । वहां सीड के प्रोडक्शन के लिए वहां की धरती हिंदुस्तान में सबसे अच्छी पाई गई है । मल्टीनेशनल कंपनी ने सीड के प्रोडक्शन के लिए सीड दे रही है, फर्टीलाइजर दे रही हैं, ड्रिप वाला इरीगेशन दे रही हैं और सिखा रही हैं कि कैसे सीड प्रोडक्ट करना है और एक एकड़ में 25 लाख । हम कभी कल्पना नहीं कर सकते कि धान में एक एकड़ में इतनी कमाई कोई कर सकेगा । यह फसल चक्र परिवर्तन इसका स्थायी हल है । केवल धान की अर्थव्यवस्था से छत्तीसगढ़ आगे नहीं बढ़ेगा । सभापति जी, बहुत सी बातें और बोलनी थी लेकिन सभापति जी ने संक्षिप्त करने को कह दिया ।

सभापति महोदय :- 11 सदस्य इधर से बोलने वाले हैं, 5 सदस्य उधर से बोलने वाले हैं ।

श्री अजीत जोगी :- मैं तो आपकी आज्ञा मान रहा हूं ।

सभापति महोदय :- आज्ञा नहीं, मैंने निवेदन किया है ।

श्री अजीत जोगी :- आप आसंदी पर है, मैं निवेदन ही कर सकता हूं ।

सभापति महोदय :- मैंने भी निवेदन किया है, धन्यवाद् । माननीय धनेन्द्र साहू जी ।

श्री अजीत जोगी :- आदरणीय सभापति जी विद्वान हैं, ब्राहमण हैं, इसलिए एक श्लोक से बात समाप्त कर दूं - सेतुबंध रामेश्वरम्, गंगा सागर संगमम्, मुच्यते सर्वपापग्रम, न मुच्यतेतु राजस्य कृतघ्नता । इसकी हिंदी बता दूं - सेतुबंध, रामेश्वर, गंगा सागर और प्रयाग ये ऐसे तीर्थ हैं कि बड़ा से बड़ा पाप करके जाएंगे तो स्नान ध्यान करने से माफ हो जाते हैं । केवल एक पाप ऐसा है, आदरणीय भूपेश जी, केवल एक पाप ऐसा है जिसको ये तीनों तीर्थ मिलकर भी माफ नहीं कर सकते और वह पाप है जब राजा अपनी प्रजा से कोई वायदा करे और उसको पूरा न करे । आपने वायदा किया है तो उसको पूरा करिये । धन्यवाद् ।

श्री भूपेश बघेल :- बहुत बहुत धन्यवाद् जोगी जी, बहुत बढ़िया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- जिस तरह पूर्व राजाओं ने अपना वायदा पूरा नहीं किया उस तरह से ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप बार-बार अपने पीरियड के आंदोलन का जिक्र कर रहे थे, आपने चौबे जी का नाम लिया, प्रेमसाय जी का नाम लिया, भूपेश जी आपके मंत्रिमंडल में नहीं थे क्या उस समय ? आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया ?

श्री धनेन्द्र साहू (अभनपुर) :- सभापति महोदय, आज विपक्ष के द्वारा जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया है । उनका कर्तव्य है लेकिन पिछले 15 सालों का कार्यकाल देखें तो किसानों के पक्ष में इन्हें बोलने का कोई नैतिक अधिकार बिल्कुल नहीं रह गया है । इन 15 सालों को आप याद करें । अभी आदरणीय जोगी जी बता रहे थे कि रामेश्वरम् और अन्य तीर्थों का । आपने जो वायदा किया तो कभी उस वायदे को पूरा नहीं किया, उसी का परिणाम किसानों ने आपको दिया जो यहां दिखाई दे रहा है । सभापति महोदय, 5 दिन बचे हैं, निश्चित तौर पर हमारे किसानों के लिए यह गंभीर विषय है और उसके लिए हमारी सरकार कृतसंकल्पित है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बार-बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि पूरे 2500 रूपए क्विंटल से धान की खरीदी की जाएगी (मेजों की थपथपाहट) और यह 01 दिसंबर से धान खरीदी चालू हो जाना है। मैं यही कहूंगा कि हंगामा है क्यों बरपा, जो थोड़ी सी देरी हो गई तो। (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जोगी जी भी वही बोल रहे हैं कि पीना पिलाना बंद करो।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, आज निश्चित तौर पर यह विषय आज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज लगभग 85-86 प्रतिशत लोगों की सारी अर्थव्यवस्था खेती-किसानी पर सिर्फ और सिर्फ धान पर टिकी हुई है। जब हमारे किसान संपन्न होंगे, किसान संपन्न होंगे, किसान खुशहाल होंगे, तभी हमारा प्रदेश खुशहाल होगा। आज यह बात साबित हो चुकी है कि सिर्फ हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों का कर्जा माफ किया, जो किसानों के सिंचाई कर भी माफ किये, जो 2500 रूपये क्विंटल में धान खरीदी किया, तेंदूपत्ते का 4000 रूपये प्रति क्विंटल में खरीदी की है, ये सारा पैसा आज आम आदमी के पास गया है। इन सारी योजनाओं का लाभ बिना एक पैसा भ्रष्टाचार के आज लगभग 24-24 हजार करोड़ रूपये सीधे किसानों और गरीबों के जेब में गया है। किसानों के नाम पर आप बहुत सारे अनुदान देते हैं, स्प्रिंकलर देते हैं, सामग्री वगैरह: देते हैं, मोटर वगैरह: देते हैं। आधा पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है। ये पैसा पहली बार किसानों को बिना एक पैसा रिश्वत दिये बिना, एक पैसा किसी को पेट्रोल खर्च दिये बिना उनके खाते में जमा होकर यह पैसा गया। आज हमारे 95 हजार करोड़ रूपये के बजट में से 23-24 हजार करोड़ रूपये की राशि यदि सीधे किसानों के खाते में गया है और उसका असर आज पूरे छत्तीसगढ़ के बाजार में गया है, जिसकी आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। आज यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। चाहे वह देवभोग का किसान हो, चाहे सरगुजा का किसान हो, चाहे बस्तर का किसान हो। आज प्रदेश के हर इलाके के किसानों को आज इसका लाभ

मिला और यह बात आज साबित हुई है। आज निर्माण कार्य की आड़ में पिछले 15 सालों में कितना भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लेकिन आज यह सीधा पैसा हमारे यहां के जो छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, उनके पास गया है, जिसका कि हम राज्य बनने के पूर्व सपना देखते थे कि राज्य हमारा होगा। यहां पर राज्य अलग बनेगा। हमारे किसान खुशहाल होंगे। समृद्ध होंगे। आज 19 साल बाद वह सपना वह सपना पूरा हुआ है कि आज किसानों के हित में पहली बार सरकार ने इस तरह के फैसले लिये हैं। आज माननीय जोगी जी याद दिला रहे थे। हम लोग भी उमसें थे। आपने जो ऐतिहासिक फैसला लिया, उसके लिए हम आज भी आपको धन्यवाद देते हैं। पहली बार किसी सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू किया है। आपके साथ हम लोग भी वहां गिरफ्तारी दिये। पूरा मंत्रिमंडल व आप मुख्यमंत्री थे, आपकी गिरफ्तारी हुई और आज पुन: वही परिस्थिति बनी है। केन्द्र सरकार धान खरीदी से जिस तरह से पीछे हट गयी है, आज निश्चित तौर पर इस प्रदेश के लिए संकट का यह विषय है और हम सब लोगों को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। लेकिन बार-बार इस कोई संदेह की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी बार-बार दोहरा रहे हैं कि हम 2500 रूपये क्विंटल में धान खरीदी करेंगे। चाहे जितना भी कर्जा लेना पड़े। इसके लिए हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि समर्थन मूल्य केन्द्र सरकार तय करती है। क्या केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? चाहे वह 15 क्विंटल की बात हो, 30 क्विंटल, 35 क्विंटल, 40 क्विंटल का धान आज हमारे प्रदेश का किसान पैदा कर रहा है। वह धान क्यों समर्थन मूल्य में नहीं बिकना चाहिए ? क्या यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? केन्द्र सरकार जब मूल्य तय करती है। कृषि मूल्य आयोग। ठीक है कृषि मूल्य आयोग धान का भाव या अन्न का दलहन, तिलहन का भाव तय करती है, लेकिन किसके बिहाफ में? केन्द्र सरकार के ही बिहाफ में तो राज्य कृषि मूल्य आयोग मूल्य तय करती है। क्या केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है कि हम सारे उपजों को समर्थन मूल्य में बिकने की व्यवस्था कर सकें ताकि किसान इसे बेच सके। आप यदि समर्थन मूल्य तय करते हैं तो समर्थन मूल्य में बिकने की भी जिम्मेदारी आपकी बनती है। आपको उसके लिए जो भी करना पड़े। नहीं तो फिर समर्थन मूल्य घोषित करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। एक तरफ आप समर्थन मूल्य घोषित करते हैं और उसके विरूद्ध यदि हमारी सरकारी मंडियां कृषि उपज मंडियां हैं, सरकारी मंडियों में यदि समर्थन मूल्य से नीचे यदि धान बिक रही है तो जिम्मेदारी किसकी है? आज कहीं न कहीं इन तमाम व्यवस्थाओं का शिकार किसान को होना पड़ रहा है। आज भी यदि 15 क्विंटल धान किसी भी सरकार ने खरीदी की, आज हमारी वर्तमान सरकार भी 15 क्विंटल धान खरीद रही है । आज खरीदी में क्या हुआ, ठीक है देरी हुई। आज 13 सौ, 14 सौ, 15 सौ क्विंटल में धान बिक रहा है। लेकिन आज यदि हम खरीद भी लें तो 15 क्विंटल से अतिरिक्त जो धान है, वही 14 सौ, 15 सौ रूपया क्विंटल में

आज नहीं बिकेगा तो कल बिकेगा। लेकिन आज हमारी सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प्ति है कि 15 क्विंटल धान 2500 रूपये समर्थन मूल्य में खरीदी करेगी। ठीक है, खरीदी में थोड़ी देरी हुई। आज हम औसत उपज लें तो 25 क्विंटल से कम कोई किसान धान पैदा नहीं कर रहा है। तो आखिर 10 क्विंटल धान कम मूल्य में बिक ही रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- धनेन्द्र जी, जब्ती क्यों कर रहे हो? उसको जब 10 क्विंटल बाजार में बेचना ही पड़ेगा तो वह उसी को ही बेच रहा है। तो जब्ती क्यों हो रही है ?

श्री धनेन्द्र साहू :- नहीं। आप के लोग जो प्रदेश के बाहर से जो लोग ला रहे है न, ..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, बाहर का नहीं। प्रदेश वाली उपज की जब्ती हो रही है।

श्री केशव चन्द्रा :- चार क्विंटल धान बाहर से कौन लायेगा ?

श्री धनेन्द्र साहू :- जिनकी आदत पड़ी है, प्रदेश के बाहर से लाने में जो लोग एक्सपर्ट हैं, वही लोग ला रहे हैं।

डॉ0 शिव कुमार डहरिया :- भैय्या बताओ कि गरियाबंद में दो हजार क्विंटल धान कहां से आया ?

सभापति महोदय :- बृजमोहन जी, आपको इसके बाद बोलना है। बृजमोहन जी इसके बाद आप ही का नाम है।

डॉ0 शिव कुमार डहरिया :- गरियाबंद में 10 हजार क्विंटल धान कहां से आ गया ?

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद में बैठे माननीय नरेन्द्र मोदी जी बार-बार इस बात को दोहराये हैं कि हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे। हम समर्थन मूल्य तय करेंगे लागत मूल्य से डेढ़ गुना। उन्होंने इस साल कितना बढ़ाया ? धान में मात्र 65 रूपया क्विंटल बढ़ोत्तरी की है। सिर्फ जो डीजल के भाव बढे हैं, वह 65 रूपया उसी के बराबर ही नहीं होता है। पिछले समय आपकी सरकार थी। आपने 2013 के चुनाव के समय कहा था कि हम 2100 रूपया धान का समर्थन देने की पहल करेंगे और 300 रूपया बोनस देंगे। आपने 2400 रूपया क्विंटल धान खरीदने की बात आप सन् 2013 में करते हैं लेकिन आज वही हम 2500 रूपया क्विंटल में खरीद रहे हैं तो आज केन्द्र सरकार उसका विरोध कर रही है। जब आपने समर्थन मूल्य तय किया, तब आपके केन्द्र के हाईकमान ने क्या इस बात की मंजूरी नहीं दी होगी ? मैं मानता हूँ कि घोषणा-पत्र को राष्ट्रीय स्तर की जो संगठन है, वह मंजूरी देती है। वैसे ही 2500 रूपया क्विंटल धान खरीदी को हमारे राहुल गांधी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते दिया था। आपको भी दी गई होगी। तो आपने उसको पूरा क्यों नहीं किया ? यदि हम आज 6 साल बाद 2500 रूपया क्विंटल धान का दाम दे रहे हैं तो कौन सा गलत कर रहे हैं ? केन्द्र सरकार क्यों उसमें सहयोग नहीं कर रही है ? आप उस लड़ाई में क्यों शामिल नहीं होते

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हैं ? आप प्रधानमंत्री जी के पास जाकर दबाव क्यों नहीं डालते हैं ? आपके सारे सांसद, सारे विधायक, आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आप सन् 2013 में 2400 रूपया क्विंटल धान की कीमत देने की बात करते हैं तो आपको 2500 रूपया दिलाने में, प्रदेश के किसानों के समर्थन में क्यों एक शब्द नहीं बोलते हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जितने में खरीदे, एकदम सही है। लेकिन आज यह जो बोलते हैं कि नैतिक जिम्मेदारी सबकी बनती है, वह गलत है।

श्री धनेन्द्र साहू :- नहीं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार है।

डॉ0 शिव कुमार डहरिया :- अच्छा आप यह बताओ कि आप 2500 रूपये के समर्थन मे हो या 1800 रूपये के समर्थन में हो ?

श्री धनेन्द्र साहू :- दिल्ली में आपकी पार्टी की सरकार है। इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप सब जायें और माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने किसानों के पक्ष में बात रखें और 2500 रूपये क्विंटल में धान खरीदी की बात करें। केन्द्रीय पुल में यहां के सारे चावल की खरीदी की बात करें, यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। माननीय सभापति महोदय, आज मात्र 1815 रूपये एवं 1835 रूपये धान का समर्थन मूल्य है। आज 2100 रूपया धान का मूल्य दिलाने की बात किए थे, 300 रूपये बोनस के साथ 2400 रूपया देने की बात किए थे। माननीय सभापति महोदय, निश्चित तौर पर यह धान खरीदी का विषय हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज प्रदेश के किसान खुशहाल और समृद्ध हुए हैं। हम लोग आज इस बात पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि यह जो प्रथा, यह जो परम्परा माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है, उनका पूरा वादा है कि पूरे 5 साल हमारी सरकार 2500 रूपया क्विंटल में धान खरीदी करेगी। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन अग्रवाल।

डॉ0 शिव कुमार डहरिया :- भैय्या, स्पष्ट बताना कि आप 1800 रूपया वाले हो या 2500 रूपया वाले हो ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर दक्षिण) :- माननीय सभापति महोदय, जो वादा किया है, वह निभाना पड़ेगा । नहीं तो आपको सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा ।

श्री बृहस्पत सिंह :- जैसे आप लोगों का हुआ । (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जमीन जल चुकी है, आसमां बाकी है । धान खरीदी करने का इम्तिहान बाकी है, राज्य सरकार तत्काल धान खरीदी करे, नहीं तो मकान गिरवी है, किसी की बेटी का हाथ पीला

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

होना बाकी है । ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यह पूरे छत्तीसगढ़ का किसान बोल रहा है । 40 रूपये का नुकसान, दूसरे बाजार में जाएंगे । 8 किलोमीटर पैदल चली, दवा तक नहीं ले पायी ।

सभापति महोदय :- कृपया समाचार-पत्रों का उल्लेख न करें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कहां कर रहा हूं ?

सभापति महोदय :- समाचार-पत्र आपके हाथ में है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, मैंने तो समाचार-पत्र का उल्लेख ही नहीं किया, मुझे हाथ पर रखने का अधिकार है । कागज रखने का अधिकार है ।

सभापति महोदय :- उसको देखकर आप पढ़ रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मुझे पढ़ने का भी अधिकार है, उल्लेख करने का अधिकार नहीं है । मैं कागज रखा हूं, सभापति जी, आप कृपा करिए, नहीं तो मैं बंद कर देता हूं और आप इतना ही चाहते हैं, आज तक सदन में ऐसा नहीं हुआ ।

सभापति महोदय :- छोटी-छोटी बात में आप लोग तुनुक मिजाजी करते हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सदन में आजतक कभी ऐसा नहीं हुआ, आप बोलने से रोक रहे हैं ।

सभापति महोदय :- ऐसा नहीं होता ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप बोलने से रोक रहे हैं ।

सभापति महोदय :- छोटी-छोटी बातों में आप बोलेंगे नहीं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आपसे एक आग्रह है, उसमें मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं पहले बोल लूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट साहब । जब प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी जब बोल रहे थे तो हाथ में वे क्या रखे थे, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं ।

सभापति महोदय :- उन्होंने लिखित में अपना जो भाषण बनाया था, वह रखे थे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- जब हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे थे तो वे नोट्स रखे थे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने व्यवस्था मांगी, वे हाथ में रखे थे, वह क्या चीज है ? कागज था या लिफाफा था या क्या चीज थी ?

सभापति महोदय :- मैं इतना कह सकता हूं कि पेपर कटिंग नहीं थी । अखबारों की कटिंग नहीं थी ।

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- मुख्यमंत्री जी सुबह पढ़ रहे थे...

श्री बृहस्पत सिंह :- चन्द्राकर जी, लिफाफा के बारे में आपको ज्यादा अनुभव है । मरकाम जी तो नोट्स रखे थे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष भी सुबह कंडोलेंस में भी कागज रखे थे ।

सभापति महोदय :- आज आप लोगों को क्या हो गया है ? सुबह से ऐसा हो रहा है कि हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे । बृजमोहन जी, अपनी बात रखें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, आप भी बहुत सीनियर हैं, मुझे भी 7 बार रहने का मौका मिला है ।

सभापति महोदय :- मैं इस बात को जानता हूं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम रिफ्रेंश ले सकते हैं, हमें समाचार-पत्रों का उल्लेख नहीं करना चाहिए, देखकर बोलने पर कहां प्रतिबंध है, मुझे आप नियम बता दीजिए । मैं भी नियम जानना चाहता हूं ।

सभापति महोदय :- आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं भी नियम जानना चाहता हूं कि देखकर बोलने पर कहां प्रतिबंध है, मुझे वह बता दीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- हमेशा ऐसा होता है, हर बार आपकी यह व्यवस्था आती है ।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, आप बैठिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र आग्रह है....

सभापति महोदय :- मैं भी विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, प्रारंभ में ही आपके टोक देने से व्यवधान उपस्थित होता है ।

सभापति महोदय :- ऐसा कोई व्यवधान नहीं हुआ । इसलिए कोई सीरियस बात नहीं थी । कोई गंभीर बात नहीं थी ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय सभापति जी, धान खरीदी पर चर्चा होना है, सबके सब इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- किसान तकलीफ में हैं इसलिए उत्तेजित हो रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- किसानों की पीड़ा है ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- यह व्यवस्था, सबके भाषण में वह टिप्पणी आनी चाहिए । हम यह कह रहे थे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सच बात बहुत कड़वी लगती है । जैन धर्म के एक महामुनि थे, इतना कड़ा प्रवचन आता था कि बहुत लोग सुन नहीं पाते थे, वही हाल है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति जी, सबेरे नेता प्रतिपक्ष अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए । अब इंट्रप्शन पर तो थोड़ा बहुत कोई अपनी बात कह दिया तो एकदम से आप भाषण देना बंद दिए । अभी बृजमोहन जी ने कहा कि मैं 7वीं बार का विधायक हूं । सभापति जी 7वीं बार के हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, संसदीय कार्यमंत्री जी, मैं आपकी बात को और आगे बढ़ा देता हूं । यदि इस रिफ्रेंश में आपको आपत्ति है तो संदर्भ शाखा बंद करवा दीजिए।

डा. शिवकुमार डहरिया :- आप भी बता दो कि कितने बार के हो ।

श्री अजय चनद्राकर :- यदि आपको रिफ्रेंश पर आपत्ति है तो आप विधान सभा की संदर्भ शाखा बंद करवा दीजिए, हम एक्सटेम्पोर बोलने के लिए तैयार हैं । किसी कागज का इस्तेमाल नहीं होगा, यह नियम बना दीजिए। आप किसी को भाषण मत बटवाईएगा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति महोदय, ये सदन का कितना दुर्भाग्य है कि पूर्व संसदीय कार्यमंत्री जी कह रहे हैं कि संदर्भ शाखा बंद करवा दीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप आपत्ति ले रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं।

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी, अपना भाषण जारी रखें। चन्द्राकर जी, आप बैठिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, तो कहां जाएं बेचने, किसानों पर दोहरी मार, न सरकार, न व्यापारी खरीद रहे हैं धान । ये मैं नहीं कह रहा हूं । पूरा छत्तीसगढ़ चिल्ला-चिल्लाकर कह रहा है । पिता बोले कैसे कराऊंगा बेटी का ईलाज, बच्चों के साथ आया था, ताकि गर्म कपड़े ले लूं । दो घंटे से बोहनी नहीं हुई, सन्नाटा पसरा हुआ है । अब नमक के साथ खाना, खाना पड़ेगा । मुर्रा के बदले धान ही देते हैं । धंधा चौपट हो गया । ये मैं नहीं कह रहा हूं । मोहन मरकाम जी, आप तो वनवासी क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी क्षेत्र से आते हैं । ननकीराम जी बैठे हैं, वे सुबह बता रहे थे कि किसान बच्चों की दवाई नहीं ले पा रहे हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इसी विधान सभा में कहते थे कि छत्तीसगढ़ में 48 लाख किसान हैं, आप 14 लाख किसान का धान खरीद रहे हैं । बाकी किसानों का कर्जा कौन माफ करेगा? बाकी किसानों को बोनस कौन देगा? आज आप धान कितने लोगों को दे रहे हैं, 48 लाख किसान है ना ? आप धान कितने लोगों का खरीद रहे हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- यह आंकड़ा कहां से लाये हैं ?

सभापति महोदय :- कार्डधारियों की संख्या बता रहे हैं ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- समाचार पत्र में जो छपा था, उसका संदर्भ लेकर आये थे ।

श्री भूपेश बघेल :- आप ही कृषि मंत्री थे, आप ही ने छपवाया है । मैं तो पहले ही मीटिंग में बोला कि वह आंकड़ा आया कहां से ?

श्री शिवरतन शर्मा :- यह आंकड़ा मैं बता देता हूँ ना ।

श्री भूपेश बघेल :- मैं उनसे पूछा हूँ ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं बता देता हूँ ना ।

सभापति महोदय :- शिवरतन जी, बोलने वालों में आपका नाम है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- शिवरतन जी, यह इस तरह से आंकड़े आये हैं शिवरतन शर्मा जी, जैसे आपने 72 लाख परिवारों को चावल देना बता दिया था । कई करोड़ का घोटाला हो गया, इस तरह से आंकड़े आये हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में ऐसे किसान भी हैं, जिनकी छोटी-छोटी बाड़ियों में कहीं 5 किलो धान पैदा होता है, कहीं 10 किलो धान पैदा होता है, कहीं 25 किलो धान पैदा होता है, कहीं 1 क्विंटल धान पैदा होता है, कहीं 2 क्विंटल धान पैदा होता है । वह पंजीयन नहीं करवाते । वह बाजार में जाकर अपना धान बेच देते हैं, अपना खर्चा चलाते हैं...।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- भईया, पूरे प्रदेश में एक भी हो तो 10 किलो धान पैदा करने वाले किसान का नाम बता दो ?

श्री बृहस्पत सिंह :- वह भी पेपर में नहीं छपा होगा, उसको पढ़कर बोल रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, आज पूरे छत्तीसगढ़ में किसान परेशान है । सिर्फ पंजीयन कराने वाले 18 लाख किसान है । यह 18 लाख किसान आप किस आधार पर मानते हैं ? जो कृषि बैंक से लोन लेते हैं, सहकारी बैंक से लोन लेते हैं, उन्हीं का कर्जा माफ हुआ है । ऐसे बहुत सारे किसान है, छोटे मजदूर हैं, जो अधिया में खेत लेकर काम करते हैं। जो रेगहा में खेत लेकर काम करते हैं, उनका पंजीयन नहीं होता । जिनके नाम से खेत होता है, उन्हीं के नाम से धान बिक जाता है, पैसा मिल जाता है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, जो किसान रेगहा लेकर काम करते हैं, वह कर्जा लिये नहीं है, तो माफ कहां से होगा ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, आज ही प्रश्नोत्तरी के छठवें नंबर पेज में आपने स्वीकार किया है कि 37 लाख किसान छत्तीसगढ़ में है । आपके प्रश्न में है, निकालकर देख लीजिए । आपने 37 लाख स्वीकार किया है, 48 लाख किसान है । आप 37 लाख स्वीकार करते हैं । 18 लाख का पंजीयन हुआ है, बाकी किसानों का क्या होगा ? बाकी किसान क्या कर्जा वाले नहीं है ? कर्जा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माफ का डेफिनेशन, कर्ज माफी सुंदरलाल पटवा जी के समय भी हुई थी, कर्जा माफी क्या होती है ? कर्जाकाफी का मतलब किसानों के ऊपर में जो पुराना कर्जा है, उसको माफ किया जाये । आपने किसानों का पुराना कर्जा माफ नहीं किया कि उनका आधा कर्जा माफ करेंगे । खाली पिछले वर्ष जो कर्जा लिया, उसको माफ करेंगे ? हमने इसीलिए इस स्थगन प्रस्ताव में किसानों की बदहाली की चर्चा की है । जब तक किसानों का पुराना कर्जा माफ नहीं करोगे, तक तक वह किसान अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो पायेगा ?

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- बृजमोहन भईया, आपने पटवा जी का नाम लिया । पटवा जी के समय डिफाल्टर किसानों का मात्र 200 करोड़ माफ किया था । हमारी सरकार ने 12000 करोड़ माफ किया है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय सहकारिता मंत्री जी ने जवाब दिया है । उस जवाब में कहा है कि 35-40 साल पुराने कर्जों को भी हमने माफ किया है । जरा बतायें, कितने डिफाल्टर किसान थे ? उनका कितना कर्जा माफ हुआ ? अगर उनका कर्जा माफ नहीं हुआ, दोबारा क्या कर्जा लेने के लायक होंगे ? आपने आधा कर्जामाफ किया तो क्या आधा उन्होंने पटा दिया, मेंरी जानकारी में अभी उन्होंने आधा कर्जा भी नहीं पटाया है । वह डिफाल्टर हैं । उनको दोबारा कर्जा नहीं मिल रहा है। जब जोगी जी भाषण दे रहे थे, धनेन्द्र साहू जी भाषण दे रहे थे, सभी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में 86 प्रतिशत यहां पर खेती किसानी करने वाले यहां पर किसान है । उसके ऊपर अर्थव्यवस्था है । अगर हम टुकड़ों-टुकड़ों में बांटकर यहां के किसानों को देखेंगे, तो छत्तीसगढ़ की बदहाली को हम दूर नहीं कर सकते । अगर छत्तीसगढ़ की बदहाली को दूर करना है तो हमको संयुक्त रूप से विचार करना पड़ेगा । हमको ज्वाईंट रूप से विचार करना पड़ेगा । हमें किसानों के बारे में विचार करना पड़ेगा, जो खेती-किसानी करने वाले मजदूर हैं, उनके बारे में भी विचार करना पड़ेगा । जो खेती-किसानी करने वाले मजदूर हैं उनके बारे में भी विचार करना पड़ेगा, जो अधिया-रेगहा में लेते हैं उनके बारे में भी विचार करना पड़ेगा, जो किसान ऐसे हैं जिन्होंने पंजीयन नहीं करवाया है जो प्रायवेट लोगों से कर्ज लेकर काम करते हैं उनके बारे में भी विचार करना पड़ेगा। जब तक हम सबके बारे में संयुक्त रूप से विचार नहीं करेंगे तब तक उन किसानों की बदहाली को दूर नहीं कर सकते। माननीय सभापति महोदय, मैं पंप के कनेक्शन के बारे में पूछना चाहता हूं कि पिछले एक साल में आप पंप के कनेक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? आपने बिजली विभाग से पंप का कनेक्शन देने के लिए जो 1 लाख रूपये सब्सिडी मिलती थी, उसे देना आपने बंद कर दिया। सोलर पंप के कनेक्शन जो हमारी सरकार ने तय किए थे उसे आपने देना बंद कर दिया। आज किसान की हालत क्या है? आज माननीय मुख्यमंत्री जी से बिजली कटौती से संबंधित प्रश्न था जो आज नहीं आया, उसमें जनवरी से जून तक कितनी बिजली का उत्पादन हुआ, कितनी कटौती हुई, किसानों के पंप में बिजली नहीं मिली, किसान अपनी सिंचाई नहीं कर पाया,

उत्पादन नहीं कर पाया उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? हमको संयुक्त रूप से इस मामले में विचार करना पड़ेगा। सभापति महोदय, 2500 रूपये की बात कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी कर रहे थे, धनेन्द्र साहू जी कर रहे थे। अभी आप ही की सरकार समाचार पत्रों में छपवा रही है कि अभी तक 1 लाख क्विंटल धान हमने जप्त कर लिया। अब 1 लाख क्विंटल धान मैं आपके साथ दाव के साथ कहना चाहता हूं कि इसमें 75 हजार क्विंटल धान छत्तीसगढ़ की धरती में पैदा हुआ है, कहीं बाहर से नहीं आया है। बाहर से आने वाला 25 हजार क्विंटल होगा। आप प्रूफ करके बता दें। आप अगर प्रूफ कर देंगे कि 1 लाख टन धान बाहर से आया है तो मैं विधायकी से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, मैं भी आपकी अनुमति से एक निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी मेरे साथ चलें, उत्तर प्रदेश की सरहद सीमा से आने वाला जो सनावल गांव है वहां पर भाजपा के एक बहुत बड़े नेता की राईसमील से 4 हजार क्विंटल हम लोगों ने जप्ती किया है, 8 गाड़ियां जप्त किया है, अगर ये प्रूफ नहीं होगा तो मैं भी सदन से इस्तीफा देकर जाने को तैयार हूं।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य कुरूद के विधायक ने भी एक घोषणा की थी कि अगर किसानों का कर्ज माफ होगा तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। वे पीछे वाले विधायक जी बैठे हुए हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, आज आपके निर्देश में कमेटी बना दी जाए, बृजमोहन अग्रवाल जी साथ में चलें, यदि उत्तर प्रदेश के धान की बरामदगी और जप्ती के सबूत नहीं मिलेंगे तो मैं भी विधायक पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं। आप आदेश कीजिए।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- अभी आप बिल्हा थानेदार को फोन लगाकर पूछ लीजिए, 16 तारीख को गाड़ी की जप्ती है, कहां का धान है, कौन किसान है आप पूछ लीजिए। आप तो रायपुर के बीच में नाकेबंदी लगा रहे हैं, बेमेतरा और बिलासपुर के बेलतरा में लगा रहे हैं, ये नाकेबंदी अंतर्राज्यीय धान के लिए नहीं है। ये लोकल किसान जो हैं वह मर रहे हैं, पिस रहे हैं, उसकी आवाज उठा रहे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, आप सनावल थानेदार से पूछ लीजिए, आप सनावल थानेदार और कलेक्टर से पूछ लीजिए कि वह धान किसके राईसमिल से जप्ती हुई।

श्री बृजमोहन अग्रवाल: - माननीय सभापति महोदय, हमारी सीमाएं हैं सीमाओं पर आप जप्त करिये, कौन रोक रहा है? आप उनको जेल भेजिए, सील करिये, गाड़ियों को जप्त करिये, हमें कोई एतराज नहीं है पर छत्तीसगढ़ की धरती में पैदा हुआ एक-एक दाना धान खरीदना आपकी जिम्मेदारी है। उसे जप्त करके आप जो अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, नहीं खरीद पाऊंगा बच्चों के गरम कपड़े,

थोड़ा सोचना चाहिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कहां से ले आये भैय्या ? इनकी सरकार में किसानों को यही सब तकलीफ थी इसीलिए बहुत सारे किसान आत्महत्या किए हैं। ये गर्म कपड़े और इलाज के नाम से 14 हजार से ज्यादा लोग आत्महत्या किए हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, इसी पवित्र सदन में इनके राजस्व मंत्री जी ने प्रश्न के जवाब में लिख दिया है कि कौन किसानों ने आत्महत्या की है। उस समय माननीय हमारे कृषि मंत्री हुआ करते थे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल: - माननीय सभापति महोदय, मैं जो बातें बोल रहा हूं यह मैं नहीं बोल रहा हूं बल्कि यह छत्तीसगढ़ का किसान बोल रहा है और आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं जो किसान अपनी बच्ची की दवाई नहीं खरीद पा रहा है?

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, ये मजाक उड़ाने का काम साहब आपने किया और इसी पवित्र सदन में आपके वरिष्ठ मंत्री जी ने जवाब दिया था मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, अगर ऐसे ही होना है तो उन्हीं को बुलवा लीजिए। पहले उनका भाषण करवा लीजिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति जी, यह इतने वरिष्ठ सदस्य हैं और आप इतना नाराज होते हैं।

सभापति महोदय :- बृजमोहन जी, आप थोड़ी-थोड़ी बात पर नाराज मत हुआ करिये। (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों की बहुत बुरी हालत है। आपने धान एक नवंबर से क्यों नहीं खरीदा ? आपको खरीदने में क्या दिक्कत थी ? क्या तकलीफ थी ? मैंने पिछले दिनों की प्रेस कांफ्रेंस देखी, उसमें कहा कि किसानों का धान गिला है, अभी कटाई नहीं हुई है। अरे भैया, नहीं होती, नहीं आता धान, परंतु जिन्होंने कटाई कर लिया, जिनका सूखा धान है, जो बेचने आते हैं, जिनको तकलीफ है, उनका धान तो खरीदा जा सकता था। आपने उसको एक नवंबर से क्यों नहीं खरीदा ? हमारी सरकार ने हमेशा दीवाली के पहले धान खरीदने की शुरूआत की कि जो बेचारे कमजोर किसान हैं, जो गरीब किसान हैं, जिनको दीवाली मनाने के लिए पैसा चाहिए। जो धान बेचना चाहते हैं, बहुत कम धान आता था, एक प्रतिशत धान भी नहीं आता था। परंतु अगर एक हजार किसानों के घर में भी दीवाली का दिया जल गया तो हमारा जो प्रयास है वह सफल हो गया, यह हम सोचते थे। अगर एक किसान अगर दवाई नहीं खरीद पा रहा है तो आपको इसके बारे में आपकी अंतर्आत्मा कचोटना चाहिए। एक किसान गरम कपड़ा नहीं खरीद पा रहा है तो आपकी अंतर्आत्मा कचोटना चाहिए। आप उनके सारे धान को जप्त कर रहे हैं। आप उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। इसके बारे में आपको विचार करने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय मैं तो यह सरकार से कहना चाहूंगा कि अगर थोड़ी सी भी आपमें गैरत है तो आप कल से किसानों का धान खरीदना शुरू कर दीजिए। एक नवंबर से धान खरीदने की सरकार की तैयारी होती है। आप बार-बार केन्द्र सरकार, केन्द्र सरकार कर रहे हैं, 2500 रूपये में वादा आपने किया है, आपको खरीदना है। उससे किसानों को कोई लेना देना नहीं है। यह जो झगड़ा है यह राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के नियमों का है, किसान को क्या लेना देना ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- सभापति महोदय, बार-बार केन्द्र सरकार, केन्द्र सरकार चार पांच बार बोले, एकात बार बोल तो देते कि केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ का चावल ले लें। (हंसी) हरियाणा का चावल खरीद रहे हो, पंजाब का चावल खरीद रहे हो, बंगाल का चावल खरीद रहे हो। दिल्ली को ये तो बता दो कि छत्तीसगढ़ भी हिन्दुस्तान का हिस्सा है। यहां के किसान भी इसी देश के किसान हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्पादित धान का यहां जो चावल है उसको ले लो इतना तो सदन में बोल दो। हम आपकी प्रशंसा करेंगे।

बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं नहीं कह रहा हूं आपके केबिनेट के फैसले से उधर धान की सबसे अधिक जप्ती दुकानों और गोदामों से हो रही है। केबिनेट फैसला खुश रहती है, अधिकारी अपनी साबासी लेने के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए गोदामों से और दुकानों से धान की जप्ती करते हैं, आखिर गरीब किसान जायेगा तो कहां जायेगा ? जिसका पंजीयन नहीं है वह कहां जायेगा ?

सभापति महोदय :- चलिये, कृपया समाप्त करें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, धनेन्द्र साहू जी बोल रहे थे कि 40-40 क्विंटल एक किसान धान पैदा करता है। आप 15 क्विंटल खरीदोगे तो बाकी धान को कहां बेचेगा ?

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति महोदय, पहले 10 क्विंटल का आपने आदेश दिया था उसका क्या हुआ ?

सभापति महोदय :- चलिये, बृजमोहन जी समाप्त करिये। बहुत से माननीय सदस्य बोलने के लिए हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- बृजमोहन भैया, आप संयुक्त रूप से बार-बार बात कर रहे हैं, बार-बार संयुक्त शब्द का उपयोग कर रहे हैं। चलिये, संयुक्त रूप से दिल्ली में 14 तारीख को चले चलते हैं। आप भी बात रख लीजिएगा, पूरा धान हमारा केन्द्रीय पुल में खरीदें।

सभापति महोदय :- बृजमोहन जी, कृपया समाप्त करें। माननीय बहुत से सदस्य बोलने के लिए हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, कभी आपने सुना है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में, छत्तीसगढ़ बनने के बाद पिछले 19 सालों में, मध्यप्रदेश बनने के बाद कि छत्तीसगढ़ के किसान ने अपने धान को सड़क पर फेंक दिया। इस सरकार को लज्जा आनी चाहिए कि किसान को अपना धान सड़क पर फेंकना पड़ रहा है।

श्री द्वारिकधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, किसान सड़क में धान नहीं फेंके हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य राजनीति करने के लिए फेंके हैं। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, किसानों ने धान नहीं फेंका।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि धान का मुद्दा छत्तीसगढ़ में आग लगाने वाला मुद्दा है। धान का मुद्दा किसान के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। धान का मुद्दा छत्तीसगढ़ के गैरेज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। धान के साथ में जो भी खिलवाड़ करेगा उसको जनता माफ करने वाली नहीं है। एक बार आपने भुलावे में लाकर, हमको जो सजा दी है हम भुगत रहे हैं। (हंसी) परंतु आप भी सजा के भागीदार बनोगे। आपको जनता इसका भुगतान करने वाली है। आपने कर्जा माफी की बात की। डिफाल्टर किसानों का पूरा कर्जा माफी नहीं किया।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, ऐसा लगता है कि आप बगल में डॉ. रमन सिंह को सुना रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपको 1 नवम्बर से धान खरीदना था। आप 1 दिसम्बर से धान खरीद रहे हैं।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, किसान दवाई, गरम कपड़े, खाने के लिए तरस रहा है और ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि इस स्थगन प्रस्ताव को...।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, सबके चावल खाने के लिए कार्ड बना दिये हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, आप सरकार को निर्देश दें कि हमने इस स्थगन प्रस्ताव में जिन बिन्दुओं को उठाया है उसको वह लागू करें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- माननीय श्री केशव प्रसाद चन्द्रा जी।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजैपुर) :- माननीय सभापति महोदय, यह छत्तीसगढ़ के किसान का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज पूरे छत्तीसगढ़ के किसान परेशान एवं दु:खी हैं। वे परेशान एवं दु:खी इसलिए हैं क्योंकि वे धान को काटने के बाद, बेच नहीं पा रहे हैं और सरकार भले ही घोषणा कर रही है कि हम 2500 रूपये में लेंगे, लेकिन आदेश केवल 1815 रूपये का दे रही है, वे संशय की स्थिति में है

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

क्योंकि पूर्व की सरकार से उन्होंने धोखा खाया है। आज भी उनको लगने लगा है कि यह सरकार भी कहीं केवल चुनाव तक ही घोषणा की है आने वाले दिनों में हमको धोखा देने वाली है।

माननीय सभापति महोदय, यहां यह बात इसलिए आ रही है। माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हैं। कृषि विभाग का सालभर का कैलेण्डर बनता है कि धान की बोवाई कब होती है ? धान कटाई कब होती है ? रबी फसल की शुरूआत कब होगी ? नहर पर कब-कब पानी देंगे तो सरकार को यह मालूम होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कब धान कटता है ? यहां कृषि विभाग का कैलेण्डर बना है और आप एक महीने खिसका कर, 1 दिसम्बर से धान खरीदी प्रारंभ करवा रहे हैं और उसके कारण पूरे किसान परेशान हैं। आज पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई है। आज किसी भी दाऊ के घर कोठी नहीं है, धान रखने के लिए जगह नहीं है और अगर किसान ऐसी परिस्थिति में धान को काटकर, अपने खलिहान या घर में भी रखा है तो आपके अधिकारी कर्मचारी छापा मारकर, उसकी जप्ती बना रहे हैं। एक तरफ धान नहीं खरीद रहे हैं और दूसरी तरफ, उनके ऊपर जप्ती बनाकर, उसको मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित भी कर रहे हैं। आपकी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। केन्द्र सरकार क्या कर रही है ? उससे किसानों को मतलब नहीं है। आपने 2500 रूपये में खरीदने की बात कही, वह भी न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम 2500 रूपये देंगे । इस साल केन्द्र की सरकार ने तो 65 रूपये बढ़ाया है तो आपको 2500 रूपये में 65 रूपये भी बढ़ाना चाहिए। आपको किसानों को 2565 रूपये देना चाहिए। केवल राजनीति, आप राजनीति कर रहे हैं और पहले की सरकार राजनीति कर रही है और किसानों के साथ राजनीति हो रही है जिस किसान के वोट से आप सरकार बनाये हैं। उनके साथ राजनीति कर रहे हैं उनको क्या मतलब ? उनको तो अपने उपज का दाम चाहिए, उन्होंने वोट देकर आपको जीता दिया, सेन्ट्रल गर्वमेंट पैसा नहीं दे रही है, आप लड़िये।

समय :
4:28 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मोदी जी आपकी सुन नहीं रहे हैं। आप उनसे लड़ाई लड़िए। आप व्यवस्था बनाईये। लेकिन आप किसान के धान को खरीदीये। आप किसान को परेशान मत करिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद ये 15 नवम्बर से भी धान खरीदना शुरू हो जाता तो आज प्रदेश में जो आग लगी है वह नहीं लगती। एक तो धान नहीं खरीद रहे हैं ऊपर से ढोल नंगाड़ा बजा रहे हैं एक बार बोलते हैं कि हम दिल्ली जाएंगे, दूसरी बार बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है हम दिल्ली नहीं जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान इस बात को समझ रहे हैं कि आप केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं। आपको किसान की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। आपको दिल्ली भी नहीं जाना है। आपने मीडिया पर देने के लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलायी। उस दिन हम लोग गये थे हम लोगों ने कहा कि

हम विधायक बाद में है, दल और पार्टी बाद में है पहले हम किसान हैं और किसान के हित के लिए अगर आप दल के आधार पर लड़ाई नहीं लड़ते हैं किसान के हित के लिए आप लड़ाई लड़ते हैं तो हम, आपके पास हैं जहां आप जाएंगे हम वहां जाने के लिए तैयार हैं। आप दिल्ली क्यों नहीं गये ? आप दस्तखत करवाये हो, रोज समाचार पत्रों, टी.व्ही. में आ रहा है। हमने इतना सारा दस्तखत करवाया, वह किस काम आएगा ? धान खरीदी शुरू हो गई। केवल राजनीति न करें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- केशव चन्द्रा जी, किसान दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है, यह 20 लाख दस्तखत करवाकर कब दिल्ली जाने वाले थे। अभी तक 13 लाख फर्जी दस्तखत हुए हैं, 20 लाख पूरा नहीं कर पाये। किसान बोल रहे हैं कि हमको क्या लेना-देना है, जाओ तुम लड़ो। एक महीना लेट होने के बाद में अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

श्री केशव चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो सरकार 15 क्विंटल धान ले रही है। हमारे वरिष्ठ सदस्य सम्माननीय धनेन्द्र साहू जी ने कहा कि 25 क्विंटल, 30 क्विंटल और 40 क्विंटल तक आज किसान धान का उत्पादन कर रहे हैं। सरकार की ही योजना है, हरित क्रांति आपने लाया। आपने विपुल उत्पादन की बात किया, आपने आधुनिक तकनीकी से खेती करना सिखाया और विपुल उत्पादन हो रहा है तो किसान उसको कहॉ बेचे? 15 क्विंटल ठीक है, आप देर-सवेर ले लेंगे। चलिये 1 दिसंबर से ले लेंगे, लेकिन बाकी जो 10 क्विंटल, 15 क्विंटल धान बचता है, उसको कहॉ बेचेंगे? आप कहां व्यवस्था बनाये हैं? आपके पास मंडी कहां है? कौन व्यापारी लाईसेन्सधारी है? आप किसान के धान को जब्ती कर रहे हैं। प्रशासन के मुखिया जगह-जगह मीटिंग लेकर बोल रहे हैं कि धान को जब्ती करो। कलेक्टर को टारगेट दिया जा रहा है कि आपको एक दिन में 25 प्रकरण बनाना है, चाहे कैसे भी बनाओ, किसी भी हालत में बनाओ। किसान मर रहे हैं। आप वाहवाही लूटने के लिए 25-30 प्रकरण बना रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, आप भी उसी जांजगीर-चांपा जिले के हैं, जांजगीर-चांपा जिले में कौन सा बाहर का धान आ रहा है, कहां से बाहर का धान आ रहा है? 5-5 क्विंटल धान की जब्ती गांव के दुकानदार की दुकान में जा करके बना रहे हैं। अधिकारी अवैध वसूली कर रहे हैं। कृषि विभाग, मंडी के अधिकारी, खाद्य विभाग के अधिकारी, तहसीलदार संयुक्त टीम बना करके छापामारी कर रहे हैं। एक तरफ अभी दशहरा के समय पानी गिरा, फसल खराब हुई, किसानों ने आवेदन दिया, हमारा 6(4) में प्रकरण बना दीजिए। फसल की क्षति हुई है, उसके लिए पटवारी, तहसीलदार के पास समय नहीं है। लेकिन आज एक आदेश पर दुकान और घर-घर में छापा मारने के लिए वही तहसीलदार, पटवारी उनके दरवाजे में बैठे हैं। आप कैसा प्रशासन चलाना चाहते हैं? आप क्यों आतंक फैलाना चाहते हैं, क्यों किसानों में दहशत फैलाना चाहते हैं? आपने घोषणा किया था कि 2500 रुपये में हम धान खरीदेंगे, आप हमको वोट दो। बेचारे किसान लोग आपके झांसे में आ गये। आपको कम से कम आपने

जो घोषणा किया था, उसमें अमल करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान बहुत सरल आदमी है। किसान अपने मेहनत का खाता है, किसी का नहीं खाता। किसान भ्रष्ट नहीं है, तो कम से कम किसानों को प्रताड़ित करना बंद करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से मुझको पता चला है कि तहसीलदार समिति के कर्मचारियों को अपने आफिस में बुला करके जो किसान का पंजीयन हुआ है, उसमें कटौती कर रहे हैं। राजस्व मंत्री जी नहीं हैं। जो नेट में दर्ज नहीं है, उनके रकबा को काट रहे हैं। ऑनलाईन करना किसकी जवाबदारी है, राजस्व विभाग की जवाबदारी है। अगर मेरी जमीन आपके रिकार्ड में कम्पयूटर में ऑनलाईन नहीं हुई है तो वह मेरी जवाबदारी नहीं है, बल्कि वह प्रशासन की जवाबदारी है। आप पूरे प्रदेश में ऑनलाईन की स्थिति देखें तो कुल रकबा का केवल 60 प्रतिशत ऑनलाईन हुआ है। मतलब आप जिस गति से जा रहे हैं, जिस लाईन में जा रहे हैं, आप 40 प्रतिशत रकबा को काटेंगे, इसलिए काटेंगे कि आपकी नियत पूर्णरूपेण धान को खरीदने की नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमसे सबूत मांग रहे हैं कि आपके पास क्या सबूत है कि धान आपका है या नहीं है? किसान के पास क्या सबूत रहता है? किसान के पास ऋण-पुस्तिका के अलावा और कोई कागजात नहीं रहता। आज किसान ऋण-पुस्तिका बता रहे हैं, उसके बाद भी किसान की धान को जब्ती कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप गंभीर विषय पर चर्चा में इसको लिये हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री और सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि पिछले समय आपने 2500 रुपये में धान को खरीदा। आपने किसानों का कर्ज माफ किया, भले पूर्णरूपेण नहीं किया, आंशिक किया, लेकिन किया और उसके परिणाम आये। छत्तीसगढ़ के किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हुए हैं। निश्चित रूप से वह धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन यह केवल 1 साल के वादा नहीं किये थे, पूरे जब तक सत्ता में रहेंगे, तब तक के लिए वादा किये थे। आप केवल 15 के कार्यकाल की गिनती करेंगे, 15 साल की कमियों को बतायेंगे, 15 साल के पहले आपकी भी सरकार थी। हम पीछे क्यों जायें? आपने वादा किया है तो आपको करना होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को दहशत में लाने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए जो अवैध छापा और प्रशासन के अधिकारी अवैध वसूली कर रहे हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में घोषणा करें कि किसान को प्रताड़ित नहीं करेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसे सरप्लस चावल के लिए आप सरकार को एक सुझाव दे दीजिए कि जो सरप्लस चावल हो जाए, जो 32 लाख टन की अनुमति चाहते हैं उसे एलीफेंट रिजर्व में डलवा दीजिए, हाथी खाएंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, चन्द्रा जी समाप्त कीजिए ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अध्यक्ष महोदय, किसान को दहशत में न लाएं क्योंकि हर किसान का पंजीयन नहीं हुआ है । बहुत से किसान ऐसे हैं जो अधिया लेकर खेती करते हैं ऐसे किसान, कहां पंजीयन कराए हैं, कहां समिति में बेचेंगे, वह धान कहीं न कहीं तो बेचेंगे या तो फिर सरकार व्यवस्था बना दे । मंडी खोल दे, मंडी में आप हमें समर्थन मूल्य दीजिए, यदि समर्थन मूल्य नहीं दिलवाते हैं तो इतना तो दिलवा दीजिए कि किसानों से खर्चा ही निकल जाए । यदि आप ऐसी व्यवस्था बना देते हैं तो हम क्यों किसी व्यापारी के पास जाएंगे । क्यों हमारा धान जप्ती होगा । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप धान खरीदी की व्यवस्था जल्दी करवाएं । 1 तारीख का समय दिया गया है, हमको मालूम है कि आपने खरीदी का जो समय दिया है उसमें आप एक दिन भी नहीं बढ़ाएंगे । किसान का धान जो वहां पड़ा रहेगा, जिसकी एंट्री नहीं होगी वह वहीं पड़ा रहेगा । इसलिए हमारा निवेदन है कि आप कल से ही खरीदी प्रारंभ करवाएं । आपकी व्यवस्था हो गई है, बारदाना आ गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय खाद्य मंत्री जी बैठे हैं उनसे भी एक निवेदन करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- खाद्य मंत्री जी कौन हैं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- सहकारिता मंत्री जी उपस्थित हैं । सेवा सहकारी समिति कचंदा में पिछले साल से खरीदी बंद कर दी गई है । आपने नया खरीदी केन्द्र जांजगीर-चांपा में खोला है । लेकिन जो पुराना खरीदी केन्द्र हैं वहां धान खरीदी की घोषणा नहीं की है । आखिर उस सेवा सहकारी समिति के किसानों सरकार का क्या अहित कर दिया है कि उनको 20-25 किलोमीटर दूर दूसरी समिति में धान बेचने के लिए भेजा जा रहा है । क्या आप चाहते हैं कि किसानों के सड़क पर आने के बाद ही उनकी समस्याओं का समाधान होगा । आपके पास प्रशासन है, आप परीक्षण करवा लीजिए । एक आदेश में रात के 12 बजे जिला जांजगीर-चांपा का कलेक्टर, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के घर जाकर छापा मारता है, धान को जप्ती करता है तो क्या एक साल में परीक्षण नहीं करवा पाते हैं । मेरा निवेदन है कि किसान परेशान न हो और आज सदन में यह चर्चा आई है तो आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं आई है । आप दोनों ही कह रहे हैं कि यह प्रदेश कृषि पर आधारित है । इस प्रदेश के 85 प्रतिशत लोग किसान हैं, उनका घर परिवार खेती से चलता है तो इतनी बड़ी आबादी का कोई समाधान निकले । उनको न्याय मिले, उनको उनकी उपज की सही कीमत मिले । अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद् ।

अध्यक्ष महोदय :- शिवरतन जी शर्मा, आप बहुत विद्वान् सदस्य हैं, 10 मिनट में अपनी बात खत्म करें ।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के हमारे स्थगन का विषय है किसान की खराब आर्थिक स्थिति, खस्ता और बदहाल हालत । अध्यक्ष महोदय, 2018 के नवम्बर में

चुनाव हुए और कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में कर्जा माफी की बात थी । कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व दोनों की संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस हुई थी और गंगाजल उठाकर शपथ ली गई थी कि सरकार बनने के 10 दिनों के अंदर हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे । बार-बार हमारे इधर के साथी कहते हैं कि हमने कर्जा माफ कर दिया, हमने कर्जा माफ कर दिया । आज ही विधान सभा के प्रश्नों में स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्वीकार किया है कि सार्वजनिक बैंकों के ऐसे पात्र किसानों का 720.66 करोड़ रूपए कर्जा माफ करना बाकी है । अभी माननीय प्रदेश अधयक्ष जी मोहन मरकाम जी और बृहस्पत सिंह जी अजय चन्द्राकर जी की घोषणा की बात कर रहे थे । आप स्वयं स्वीकार कर रहे हो कि हम पात्र किसानों का 730 करोड़ का कर्जा माफ नहीं कर पाए हैं । तो वायदा किसने पूरा नहीं किया, अजय चन्द्राकर ने या श्री भूपेश बघेल ने ? यह पूरा प्रदेश जानना चाहता है । खाली कोटा क्षेत्र में आज का प्रश्न था जो मैं अभी बता रहा हूं। 688 लाख रूपये का कर्ज माफ करना बाकी है। रेणु जोगी जी के प्रश्न के जवाब में आया है। मरवाही क्षेत्र में 144 लाख रूपये का कर्ज माफ करना बाकी है। पटवा जी के कर्ज माफी की बात हुई। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि अगर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो कर्ज माफ करेंगे और पटवा जी की सरकार ने उस समय 764 करोड़ रूपये का कर्ज माफ किया था और वह कर्ज माफ करने वाली पूरे देश की पहली सरकार थी। ये कर्ज माफी की बात करने वाले लोग हैं। गंगा जल उठाकर शपथ लेने वाले लोग, आज स्वीकार कर रहे हैं कि कल माफ नहीं कर पाये। मानो इन्होंने पूरी हिन्दू संस्कृति को अपमानित करने का पाप किया है। (शेम शेम की आवाज) छत्तीसगढ़ में इस हिन्दू संस्कृति में गंगा जल का क्या महत्व है ? हमारे यहां तो यह मान्यता है कि जब एक व्यक्ति मृत्यु शय्या में रहता है और उसकी मृत्यु होने वाली रहती है तो उसे गंगाजल पिलाया जाता है ताकि उसे मुक्ति मिले और उस गंगा जल को अपमानित करने वाले लोग बात करते हैं किसानों के हित की। माननीय अध्यक्ष महोदय, बार-बार विषय आता है कि किसानों के लिए हमने यह किया, किसानों के लिए हमने यह किया। आज स्वयं एक उत्तर में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है। किसान सम्मान निधि हेतु 18 हजार 84 लाख 610 किसानों ने स्वघोषणा पत्र के हिसाब से फार्म भरा है और उनमें 14 लाख 80 हजार 323 किसानों को किसान सम्मान निधि मिली हे। 4 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं मिली। 4 लाख किसानों को सम्मान निधि इसलिए नहीं मिली, क्योंकि इनके खाते क्रियाशील हैं। आज ही एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि छत्तीसगढ़ में किसानों की संख्या 37 लाख 46 हजार 480 है और आज स्वयं बोल रहे हैं कि 18 लाख किसानों ने सम्मान निधि हेतु स्वघोषणा पत्र भरा है। तो जो शेष 18 लाख किसानों का स्वघोषणा पत्र नहीं भरा गया है, उस घोषणा पत्र को भराने की जवाबदारी किसकी है ? क्या प्रदेश सरकार की जवाबदारी नहीं है। क्या प्रदेश सरकार को इस बात के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए कि सारे किसानों को किसान सम्मान निधि मिल

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

सके। क्या राजस्व विभाग के अमले को इस काम में नहीं लगाया जा सकता? पर इस सरकार की नीयत किसानों के उत्थान की नहीं है। किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति करने की इनकी नीयत है। माननीय अध्यक्ष जी, जब माननीय नेता जी इधर बैठा करते थे तो भूपेश जी और धनेन्द्र जी का एक बड़ा प्रिय विषय हुआ करता था कि किसान अगर धान बेचता है तो छत्तीसगढ़ में किसान जो पंजीयन कराकर धान बेचता है, उन किसानों की संख्या मुश्किल से 18 से 19 लाख होती है। जबकि छत्तीसगढ़ में किसानों की संख्या 37 से 38 लाख है तो बाकी किसानों का धान कहां जाता है? आज स्वयं स्थगन के जवाब में माननीय मंत्री जी ने यह पढ़ा है कि कुल 19.70 लाख किसानों द्वारा धान खरीदी हेतु पंजीयन कराया गया है। जब आप हमको दोष देते थे कि आधे किसान ही पंजीयन कराते हैं और आज स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 19 लाख 70 हजार किसानों ने पंजीयन कराया है। बाकी 37 लाख 46 हजार किसानों में जो शेष रह गये, उसके पंजीयत की चिंता कौन करेगा? क्या इस सरकार की जवाबदारी नहीं है। या सिर्फ भाषण देना इस सरकार का काम रह गया है। धान जब्ती की बात आयी। विपक्ष में थे। माननीय टी.एस. सिंहदेव साहब जी बैठे हैं। भूपेश जी और आपका दोनों का पत्र जाया करता था कि धान खरीदी एक नवंबर से शुरू होनी चाहिए। सरकार ने निर्णय लिया कि अब धान खरीदी एक दिसंबर से होगी। कारण बताया गया कि बारिश लेट तक हुई है। धान गीला है और 17 प्रतिशत नमी रहेगी, इसलिए धान रिजेक्शन हो जायेगा। किसान परिवार के लोग सब जानते हैं। जमीन गली गीली रह जाती है, बल्कि हमारे धान की जो वैरायटी है और उसका जो पीरियड पूरा हो गया, उससे अगर लेट होता है तो धान की बाली टूटने लगती है और भले पौधा हरा दिखे, पर धान की बाली पक जाती है और किसान को धान काटना पड़ता है। आज किसान धान काट रहा है। उसे पैसे की आवश्यकता है। धान कटाई का पैसा देना है। रबी की तैयारी करनी है। अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है और किसान धान बेचने आ रहा है तो किसान के धान की जब्ती की जाती है। आज स्वयं उत्तर में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि छत्तीसगढ़ में धान जब्ती के 1358 प्रकरण बनाये गये हैं । इस 1358 प्रकरण में 1,66,718 क्विंटल धान जब्त किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के बाहर से धान आये, उसको आज जब्त करो, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। परन्तु मैं अब पूछना चाहता हूँ, अभी कृषि मंत्री जी नहीं हैं। कृषि मंत्री जी के विधान सभा क्षेत्र का धान भाटपारा में जब्त हुआ, भाटापारा मण्डी में किसान धान बेचने आया था। बेमेतरा की सरहद कहां प्रदेश के बाहर लगती है। भाटपारा के किसान का धान जब्त हुआ या बिल्हा के किसान का धान जब्त हुआ तो इसकी सरहद किस प्रान्त से लगती है, जरा यह बता दें? इसमें जो धान की जब्ती हुई है, बृजमोहन जी तो 75 प्रतिशत की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ कि 90 प्रतिशत किसान, छत्तीसगढ़ के किसान हैं, जो अपना धान बेचने आई है। इन्होंने धान बेचने के बाद क्या कार्यवाही की है ? मण्डी एक्ट के अन्तर्गत अगर किसी भी किसान का धान जब्त

किया जाता है तो मण्डी बहुत ज्यादा कार्यवाही कर सकती है कि 1 से 5 गुना उससे मण्डी टैक्स लगाकर उसको धान रिलीज करना पड़ेगा। परन्तु मुख्य सचिव का मौखिक निर्देश जाता है कि धान जब्त होना चाहिए, संख्या ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए। किसान का धान छूटना नहीं चाहिए। कहीं तो मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत जब्ती हो रही है, कहीं फूड एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही हो रही है। लेकिन कहीं मण्डी एक्ट तो कहीं लगा ही नहीं है। किसान को खाली परेशान करने के लिए यह धान जब्ती की कार्यवाही हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप स्वयं स्वीकार कर रहे हो कि पंजीकृत किसानों की संख्या 19 लाख 70 हजार है लेकिन छत्तीसगढ़ में किसानों की संख्या 47 लाख 46 हइजार है। तो शेष किसान तो बाहर धान बचेने जायेगा ही। लेकिन आज सिथति क्या बन गई है ? माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का गृह क्षेत्र कोण्डागांव है। कोण्डागांव में फुटकर और गल्ला व्यापारियों के घरों में घुसकर कार्रवाई की गई है। उसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि वहां व्यापारी एक सप्ताह से धान खरीदना बंद कर चुके हैं, बहिष्कार कर चुके हैं। उसके चलते न तो व्यक्ति अपनी आवश्यकता के लिए धान बेचने जा पा रहा है और न ही कुछ कर पा रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, 1358 प्रकरण बने। माननीय बृजमोहन जी विद्युत कनेक्शन का एक विषय उठाया। 01 जनवरी से लेकर 31 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ के 40,920 किसानों ने पम्प कनेक्शन के लिए आवेदन दिया है। 40,920 आवेदन में स्वीकृत कितना हुआ है, इन्होंने 6,531 प्रकरणों को स्वीकृत किया है। अभी भी लगभग 34 हजार कनेक्शन के आवेदन स्वीकृत नहीं किए गए हैं। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि आपने 6,531 प्रकरण स्वीकृत किए हैं। इन स्वीकृत प्रकरणों में भी अभी तक एक भी पम्प कनेक्शन का काम नहीं हुआ है। इन 11 महीने में एक किसान को भी पम्प कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। हमारी सरकार ने कि साल में कितने सोलर पंप देंगे, हम कितने किसानों को विद्युत कनेक्शन देंगे, इसका लक्ष्य निर्धारित करके काम किया था। लेकिन आप 11 महीने में क्या कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपकी सरकार तो माननीय उद्योगों को पानी दिया है। किसानों पर लाठी बरसाया है, उसका भी थोड़ा उल्लेख कर दीजये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है ? आज ही के प्रश्न में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 11 महीने में भूपेश बघेल जी की सरकार ने 13,343.66 करोड़ रूपये का ऋण लिया है। इसमें धान खरीदी के लिए जो ऋण का आवेदन लगा है, इसका उल्लेख नहीं है।

श्री बृहस्पत सिंह :- यह किसके लिए लोन लिया गया है शर्मा जी ? आप बहुत विद्वान साथी हैं, यह किसके लिए लोन लिया गया है ? किसानों के लिए न।

श्री शिवरतन शर्मा :- छत्तीसगढ़ में 18 साल में, 15 साल डॉ0 रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे, 3 साल माननीय जोगी जी मुख्यमंत्री रहे। इन 18 सालों में छत्तीसगढ़ की सरकार ने 40 हजार करोड़ रूपये का कर्ज लिया था और इस 11 महीने में इस सरकार ने 13,343 करोड़ रूपये का कर्ज लिया है। अभी समाचार-पत्रों के माध्यम से पता चल रहा है कि 21 हजार करोड़ रूपये के कर्ज का आवेदन और लगा हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव के समय तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी का भाषण होता था। वे भाषण में कहा करते थे, विशेषकर कोण्डागांव की सभा में उन्होंने भाषण में कहा था कि डॉ0 रमन सिंह जी, आपको दो साल का बोनस नहीं दे पाये हैं, हमारी सरकार बनेगी तो डॉ0 रमन सिंह की घोषणा का दो साल का बोनस भी हम किसानों को देंगे। मोहन मरकाम जी, आपकी सरकार किसानों के दो साल का बोनस कब दे रही है ?

श्री मोहन मरकाम :- देगी, देगी । हमारी सरकार आपकी तरह झूठे वायदे नहीं करती । हमारी सरकार जो बात करती है, वह पूरा करती है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार धान खरीदी में पीछे हट गई । हमारी सरकार ने धान खरीदा । जितना धान खरीदा, किसानों को तत्काल भुगतान की व्यवस्था की । डा. रमन सिंह के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कभी कोई किसान यह शिकायत लेकर नहीं आया कि मैंने धान बेचा है और मुझे भुगतान नहीं मिला । अभी राजिम की घटना है, माननीय धनेन्द्र साहू जी चले गए । वहां के बहुत से किसानों का भुगतान नहीं हुआ है और उन किसानों ने तय किया कि वे पद यात्रा करते हुए रायपुर आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे । पद यात्रा जारी हुई, राजिम में उनको गिरफ्तार किया गया, मंडी परिसर को अस्थायी जेल घोषित किया गया और किसानों को दिन भर रखा गया । पिछले बार आपने जो धान खरीदा, उस धान का बोनस भी आप नहीं दे पाये । सिर्फ धान की बात नहीं है । माननीय जोगी जी ने फसल चक्र परिवर्तन की बात की और फसल चक्र परिवर्तन अगर सबसे ज्यादा हुआ है तो कवर्धा में हुआ है । कवर्धा पण्डरिया में किसान गन्ने की खेती करते हैं । आपके जन घोषणा-पत्र में गन्ने का समर्थन मूल्य केन्द्र सरकार का मूल्य 261 रूपये क्विंटल है और माननीय सिंहदेव साहब ने जन घोषणा-पत्र में घोषणा की कि यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये 355 रूपये क्विंटल देंगे । किसानों को गन्ने की कीमत नहीं मिल रही थी ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- शर्मा जी, आपने आजतक गन्ने को कभी पकड़ा है ? गन्ने की बात कर रहे हो । अभी गन्ने को छूकर देखा है, कभी गन्ने को पकड़ा है ? गन्ने को चुसा करो ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपकी उम्र निकल गई है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- और ये जो चीज पकड़ते हैं, उसका नाम नहीं ले सकते ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, किसानों ने गन्ना बेचा, किसानों को गन्ने भुगतान नहीं हुआ । वहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में पण्डरिया और कवर्धा में किसानों का प्रदर्शन हुआ । युवा मोर्चा के अध्यक्ष विजय शर्मा जी उसका नेतृत्व कर रहे थे । किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करने का परिणाम यह हुआ कि विजय शर्मा और उनके साथियों के खिलाफ नॉन बेलेबल अफेंस (अजमानतीय अपराध) कायम किये और उसके बाद भुगतान हुआ, भुगतान किस दर पर हुआ ? 261 रूपए प्रति क्विंटल के दर पर । जब आपने 355 रूपये प्रति क्विंटल की जन घोषणा-पत्र में घोषणा की है तो आपको इसका भुगतान भी 355 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से करना चाहिए था ।

अध्यक्ष महोदय :- संतराम जी, 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, बस दो मिनट ।

अध्यक्ष महोदय :- मुख्यमंत्री जी भी आप लोगों की बातों का जवाब देंगे न, आप लोग चाहते हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जितनी घोषणा की हैं, वह किसी को पूरी नहीं कर पा रहे हैं । अब बार-बार यह बात आती है कि केन्द्र सरकार सेन्ट्रल पुल में चांवल खरीदे । क्यों भैया ? जब जन घोषणा-पत्र बना रहे थे तो मोदी जी से पूछकर बना रहे थे क्या कि हम जन घोषणा-पत्र में डाल रहे हैं, आप सेन्ट्रल पुल में चांवल खरीद लेना । अगर आज नगर पालिका का चुनाव हो रहा है और कोई नगर पालिका का अध्यक्ष घोषणा करेगा कि मैं अगर नगर पालिका का अध्यक्ष बनूंगा तो अपने पूरे शहर में सारे लोगों को पक्के मकान दूंगा, 5 हजार रूपये प्रति परिवार पेंशन दूंगा और बाद में कहेगा कि भूपेश बघेल जी को तो लिखकर दे रहा हूं, भूपेश बघेल जी नहीं दे रहे हैं तो मैं क्या करूं ? घोषणा आपने की है, उस घोषणा को आपको पूरा करना है और घोषणा करने के पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सरकार के पास निवेदन करने जा रहे हैं या केन्द्र सरकार को धमकी देने जा रहे हैं । इनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान आता है कि हम केन्द्र सरकार की आर्थिक नाकेबंदी करेंगे । इनके एक मंत्री का बयान आता है कि हम छत्तीसगढ़ से जाने वाला कोयला रोक देंगे । आपको सहयोग चाहिए । निवेदन करना सीखो, धमकी देने से काम नहीं होता ।

श्री बृहस्पत सिंह :- कौन सा गुनाह कर दिया । अगर छत्तीसगढ़ के कोयला से हिन्दुस्तान की फैक्ट्री चला रहे हो, छत्तीसगढ़ के आयरन से आप पूरा देश चला रहे हो तो कौन सा गुनाह किया, छत्तीसगढ़ की आवाज को बोला गया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- नरेन्द्र मोदी जैसा व्यक्ति धमकी से नहीं डरता। वे ऐसे लोगों से निपटना और सुधारना जानता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, जन घोषणा-पत्र में आपने जो भी जनता से वादा किया, उस वादा को पूरा करने की जवाबदारी आपकी है और उस पर आप पीछे हट रहे हैं तो इसके लिए

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दोषी आप हो और छत्तीसगढ़ का किसान इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करेगा । अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री बृहस्पत सिंह :- और आपको छत्तीसगढ़ को लूटने का अधिकार है?

श्री संतराम नेताम (केशकाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज विपक्ष के सम्माननीय सदस्यों द्वारा स्थगन लाया गया है, वह वास्तव में महत्वपूर्ण विषय पर है । प्रदेश में 80 प्रतिशत लोग किसान हैं । उनकी चिन्ता जायज है, लेकिन हम 15 वर्षों की बात करें, आप 15 सालों तक सरकार में थे । 2013 के चुनाव में इनकी घोषणा-पत्र में था कि हम किसानों को 21 सौ रूपये समर्थन मूल्य देंगे, 300 रूपये बोनस देंगे । उस समय हमारे विपक्ष के साथियों की चिन्ता नहीं हुई । हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि 15 वर्षों में 14 हजार किसानों ने आत्महत्या किया । आज 11 महीने में एक भी प्रकरण हमारे सामने में नहीं है, उसका कारण है कि 11 हजार करोड़ हमारे किसानों को कर्जामाफी हुआ है । हमारे विपक्ष के साथी भी हमारे माननीय भूपेश बघेल जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि कर्जा माफ हुआ है । अभी हमारे शिवरतन शर्मा जी कह रहे थे कि कर्जा माफ नहीं हुआ है । मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके एक सदस्य धन्यवाद दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आज के प्रश्न में आया है कि जितने भी लैम्प्स में हमारे किसानों का कर्जा माफ है, पूरे प्रदेश में किसान खुश हैं, इसलिए आप आंकड़े देखें कि सबसे ज्यादा ....।

श्री शिवरतन शर्मा :- संतराम जी, पेज नंबर 31, प्रश्न नंबर 41, स्वयं भूपेश बघेल जी ने स्वीकार किया है कि इतना कर्ज माफ करना बाकी है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह मोहन मरकाम जी को समर्पित करिये । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- यह पुस्तिका आपको समर्पित कर देता हूँ ।

श्री संतराम नेताम :- उन्होंने आर्थिक मंदी की भी बात कही है कि हमारे प्रदेश में अभी किसान खुश हैं । अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर खुश हैं । इसलिए हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा किसान लोग कर्जा माफ करने से शादी किये हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या कर्ज माफी होने के पहले शादी नहीं होती थी ।

श्री संतराम नेताम :- आंकड़ों की बात कर रहा हूँ । माननीय सदस्य जी आप सोचिये । जिस प्रकार से किसान लैम्प्स के तरफ से भागते थे...।

श्री अजय चन्द्राकर :- कर्जमाफी के बाद आपकी दोबारा तो नहीं हुई ना ।

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, डिफाल्टर किसान लैम्प्स में जाने के लिए भागते थे । ग्रामीण बैंक से भागते थे । आज उनका कर्ज माफ होने से लैम्प्स में जाकर कर्जा ले रहे हैं । बकायदा अपने यहां बोर खनन किये हैं । इसका परिणाम है कि कांग्रेस की सरकार में बैठे हमारे मुख्यमंत्री जी

किसानों की चिन्ता करते हैं । अभी हमारे शर्मा जी कह रहे थे कि इस्तीफा इसलिए नहीं दिये हैं, इस्तीफा तो हमारे चन्द्राकर जी को दे देना चाहिये । उसके बाद फिर हमारे पूर्व कृषि मंत्री इस्तीफा दूंगा कहें हैं, वास्तव में हमारे यहां उड़ीसा, झारखंड दूसरे प्रान्त से धान आता था । अच्छी पहल है कि जो किसान लोग 15 एकड़ में फसल कमाते थे, उन लोगों के पास फसल नहीं हुआ तो दूसरी जगह का धान खपाते थे । यह अच्छी पहल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 2500 रूपये प्रति क्विंटल धान खरीदी की बात हुई, आज तक पूरे देश में कोई राज्य नहीं खरीदा है । पिछले साल 2100 रूपये बोले, 300 रूपये बोनस देने की बात हुई, इसी विपक्ष में बैठकर किसानों के दर्द के बारे में अपनी बातें कही, केवल घड़ियाली ऑंसू विपक्ष में रो रहे हैं, क्योंकि आज उनकी संख्या 14 हो गई है । उनको चिंता है, अगर इसी प्रकार कांग्रेस काम करती रहेगी तो हम और घटते जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूँ कि इसी प्रकार अगर कांग्रेस करती रहेगी तो हम और बढ़ते जायेंगे । इसलिए आप बस्तर में भी देख लीजिए, आज केन्द्र में क्यों बात नहीं करते ? ठीक है, ढ़ोल नंगाड़ा नहीं, लेकिन आप अपने पत्र से, अपने नेता से बात करके, मोदी जी से यहां के किसानों के हित की बात क्यों नहीं करते ? अध्यक्ष महोदय क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्या मोदी जी को हमारे प्रदेश के किसान वोट नहीं किये हैं ? उनको प्रधानमंत्री बनाये हैं । आज से दो साल पहले उन्होंने बोनस के रूप में दिया है । आज प्रदेश में हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इसलिए केवल दुर्भावनापूर्वक यहां अनुमति नहीं दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉ.रमन सिंह जी ।

श्री संतराम नेताम :- वास्तव में अगर आपको चिंता है तो हमारे साथ चलना पड़ेगा और निश्चित तौर पर देना पड़ेगा । अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ.रमन सिंह जी ।

डॉ.रमन सिंह (कवर्धा) :- अध्यक्ष महोदय, आज जिस गंभीर विषय पर पूरा सदन अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है, इसकी गंभीरता यह है कि पूरा छत्तीसगढ़ का किसान इस सदन को, इस विधान सभा की, एक-एक बात को ध्यान से सुनना चाह रहा है । इस स्थगन का जो मूल विषय है, जिसके बारे में स्थगन लाने का काम किया, समय को लेकर 1 नवम्बर और 1 दिसम्बर, यह 30 दिन का समय, पिछली बार जब मुख्यमंत्री के नाते हम लोगों ने काम किया, हमारी सरकार थी, आज यहां बैठे हुये मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष पत्र लिखा करते थे कि 1 नवम्बर से धान खरीदी की जाये, किसानों में परेशानी है, पीड़ा है, वह पत्र मेरे पास है । आज वह कैसे भूल गये ? वह तारीख जो किसान की पीड़ा और तकलीफ थी, आज किसानों को बड़ी संख्या में इस बात के लिए पीड़ित और परेशान है कि 1

महीना का पूरा का पूरा समय निकल रहा है, 15 दिन, 20 दिन निकल गये, 25 दिन निकल गये, आज 1 दिसम्बर से धान खरीदी की जो व्यवस्था हो रही है । आज यहां बैठे हुए मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष जी पत्र लिखा करते थे कि एक नवंबर से धान खरीदी की जाए, क्योंकि किसानों में परेशानी है पीड़ा है। अध्यक्ष महोदय, वह पत्र मेरे पास है। आज वह कैसे भूल गये कि वह तारीख जो किसान की पीड़ा और तकलीफ थी आज बड़ी संख्या में किसान इस बात के लिए पीड़ित और परेशान हैं कि एक महीने का पूरा का पूरा समय निकल रहा है। 25 दिन निकल गये और आज एक दिसंबर से धान खरीदी की जो व्यवस्था हो रही है आज पूरी की पूरी धान खरीदी के विषय में जितने लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, किसानों की प्रतिक्रिया आ रही है, 36 हजार क्विंटल एक संभाग में जप्त होता है। 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो धान जप्त हो रहा है। मंडी में यदि किसान धान को लेकर जा रहा है तो मंडी में उसके धान को जप्त किया जा रहा है। क्या किसान को हम चोर समझते हैं जो किसान यदि मंडी जा रहा है तो उसके धान को रोका जा रहा है? वह अपने पारिवारिक संकट को देखकर, तकलीफ को देखकर धान खरीदी की व्यवस्था के लिए जाता है, मगर ये सरकार इतनी निर्ममता के साथ, जो लगातार इतनी कार्रवाई हो रही है इससे किसान व्यथित है। और ये समय 15 दिन और 30 दिन का समय है। यदि आज लाखों क्विंटल धान किसान बेच रहा है तो निश्चित रूप से वह बिचौलियों के हाथ जायेगा, उनके हाथ जाकर फिर वापस रिसाईकिल होगा और फिर 2500 रूपये क्विंटल के हिसाब से बेचा जायेगा। मैं कहता हूं कि बार्डर को सील कर दिया जाए, बार्डर को सील करने में कहीं किसी को आपत्ति नहीं है। एक भी दाना धान नहीं आना चाहिए मगर बार्डर को सील करने के बाद यदि बिलासपुर, मुंगेली, तखतपुर, कवर्धा जैसे क्षेत्रों में मंडी के सामने ही जप्ती की जाती है तो किसान कहां जायेगा? 15 क्विंटल के अतिरिक्त धान को कहां बेचेगा? उस धान को बेचकर अपनी गृहस्थी चलाना चाहता है, अपने परिवार को चलाना चाहता है तो मूल विषय इस विषय को लेकर है कि जो समय में विलंब हुआ और जो वायदा जनघोषणा पत्र में हुआ, जनघोषणा पत्र से इतना बड़ा बहुमत मिला, जनघोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से सरकार के द्वारा कहा गया था कि 2500 रूपये प्रति क्विंटल, दो वर्ष का बकाया बोनस दिया जायेगा। ये घोषणा उस समय के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जी करते तो अलग बात थी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सार्वजनिक रूप से मंच में कहते हैं कि दो साल का बोनस जो डॉ. रमन सिंह जी ने नहीं दिया है इसे हमारी सरकार 10 दिन के अंदर देगी, 2500 रूपये क्विंटल पर खरीदी की व्यवस्था करेगी और संपूर्ण कर्ज माफ किया जायेगा। ये सब यदि शार्ट टर्म, मिड टर्म और लांग टर्म लोन की बात है तो सिर्फ और सिर्फ शार्ट टर्म लोन को ही माफ करने से ही उस कर्ज माफी का वायदा पूरा नहीं होगा। आपने कहा कि सब किसान का कर्ज माफ। यदि सब किसानों का कर्ज माफ किया है तो ये शार्ट टर्म लोन को छोड़कर बाकी कर्ज माफी की बात कहां से भूल गये? इन सारे विषयों को लेकर आज लोगों के मन में पीड़ा है।

एक बड़ी बात आ रही थी, और बहुत सारे विषय में रिपीट नहीं करना चाहता जो हमारे साथियों ने कहा पर फसल चक्र परिवर्तन के दो कंपोनेंट हैं। यदि फसल चक्र परिवर्तन करना है और कृषि को लाभ का विषय बनाना है तो आज यदि आपने एक अच्छा काम किया कि पंप कनेक्शन के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में छूट दे दी और छूट देने का नतीजा ये हुआ कि पूरे छत्तीसगढ़ में 40 हजार से ज्यादा पंप के कनेक्शन हो गये। 40 हजार पंप कनेक्शन के बाद नई पालिसी आ गई कि अभी तक किसानों को पूरे छत्तीसगढ़ में पिछले 11 महीने में 1600 से 1800 किसानों को ही पंप के कनेक्शन दिये गये थे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो हमने पंप के ऊपर वेटिंग लिस्ट खत्म कर दी थी। किसी को वेट नहीं करना पड़ता था। एक महीने के अंदर पंप के कनेक्शन मिलते थे। 8 हजार 10 हजार तक के पंप कनेक्शन दिये गये। ये 40 हजार में से 36 हजार किसान हैं। यदि आप कृषि को लाभदायक बनाना चाहते हैं तो कम से कम यदि उसे पंप के कनेक्शन नहीं देंगे और यदि वह पांच साल तक इंतजार करेगा जैसा पहले होता था तो फिर किसान अपनी बेहतरी के लिए फसल कैसे लेगा? दूसरा विषय जो छत्तीसगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि फसल चक्र परिवर्तन की ओर जाना ही है तो इन सभी पंप कनेक्शनधारियों को पंप का कनेक्शन दीजिए और बाकी विषयों के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि यदि आप नई फसल लेते हैं, आज छत्तीसगढ़ में गन्ना उत्पादक जो तीन जिले हैं और सब मिलाकर 7 जिले हैं वहां पर गन्ना उत्पादकों के मन में घोर निराशा है। सबसे ज्यादा पीड़ाजनक स्थिति यह है कि कवर्धा और मुंगेली जिले में गन्ना का रकबा आधा हो रहा है। सरकार बदलने के एक साल के बाद ऐसा क्या हो गया कि गन्ना के उत्पादन में 50 प्रतिशत की कटौती हो गई और आने वाले समय में इसमें और कटौती होगी। उसका मूल कारण कि गन्ने की खरीदी की व्यवस्था नहीं होना है। गन्ना बेचने के बाद किसान 8-9 महीने तक इंतजार करता रहा कि उसे गन्ने की कीमत मिल जाए। एक साल होने के बाद नये गन्ने की पेराई सीजन आने के बाद उसको गन्ने का पेमेंट हो रहा है तो अब किसान को लगता है कि मैं यदि गन्ना पैदा भी कर लिया तो मेरे लिये दिक्कत है और 261 रूपये पेमेंट होता है। आपकी जन घोषणा पत्र की दूसरी लाईन फिर से याद दिलाना चाहता हूं। आपने कहा था कि 351 रूपये दिया जायेगा। किसानों को लगा कि गन्ने में, जैसे धान की खेती में उनको फायदा हो रहा है, गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा। तीन अलग-अलग क्षेत्रों में इसका विकास होगा। मगर आज छत्तीसगढ़ का किसान दोनों तरफ से ठगा महसूस कर रहा है। उसको न धान का न गन्ने का कीमत मिल रहा है। गन्ने की कीमत के साथ जो 50 रूपये बोनस देने की बात थी, वह बोनस उनको मिलने की स्थिति बनी हुई है। किसानों की स्थिति यह है कि वह फसल चक्र परिवर्तन के सिर्फ झांसा देने से काम नहीं चलेगा। सोयाबिन की फसल लगातार दो साल से खराब हो रही है। एक भी किसान को उसकी नुकसान की भरपाई नहीं हुई, पूरा का पूरा 4 जिले के बारे में मुझे जानकारी है-

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

राजनांदगांव से लेकर कवर्धा और मुंगेली, बेमेतरा से लेकर इस पूरे क्षेत्र में पूरा फसल बर्बाद हो गया। अब किसान नये फसल की ओर जाने के बारे में जाने से कैसे सोचेगा? तीन चार विषय जो धान की खरीदी के विषय को लेकर जुड़ा हुआ है। एक तो उनका पंजीयन कराया गया और पंजीयन कराने के बाद आनलाईन पंजीयन की सुविधा दी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। बहुत बेहतर किया, मगर पंजीयन के बाद भी आज 25 से 30 प्रतिशत लोग हैं, जिनका नाम जोड़ा नहीं गया है, जिनका नाम शामिल नहीं किया गया है। इस बात की चिंता करने की जरूरत है। उसके साथ ही साथ किसान के लिए जो सम्मान निधि की बात आयी। अध्यक्ष महोदय, किसान सम्मान निधि यदि आज यह किसान धान को औने-पौने में बेचने को मजबूर हो रहे हैं, यदि सम्मान निधि की पूरी राशि उनको मिल जाती तो वह छोटे-मोटे खर्च के लिए, दवाई के लिए, कंबल के लिए, स्वेटर के लिए, ईलाज के लिए जो भटकना पड़ रहा है, वह भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। 30 लाख लघु और सीमांत किसानों को पंजीयन कराकर सब घोषणा पत्र करना था। 11 लाख 92 हजार ने डाटा अपलोड किया और उनमें से सिर्फ और सिर्फ 88 हजार किसानों को इसका फायदा मिल रहा है। 7.38 प्रतिशत लोगों को ही इसका लाभ मिल रहा है। यदि इसमें तत्परता होती, प्रधानमंत्री सम्मान निधि सबको 6 हजार रूपये की राशि मिल जाती तो किसान छोटी-मोटी खरीदी और फरोख्त के लिए, छोटे-मोटे कामों के लिए भटकना नहीं पड़ता और धान को लेकर मंडी आने की जरूरत नहीं होती। कोचिया और बिचौलिये के हाथ में देने की जरूरती नहीं पड़ती, यह हालत यदि किसानों की है तो आज आप कहते हैं कि 38 लाख टन सरप्लस धान से इथनाल, बायोफ्यूल बनेगा। यह इथनाल और बायोफ्यूल क्या होता है ? इसकी क्या लागत आती है ? क्या उसका Cost of Production होता है, कितना उसके लिए Raw material लगते हैं। साहब, आप 25 रूपये क्विंटल धान खरीद रहे हो, उसका चावल 40 रूपये बनेगा। 40 रूपये क्विंटल में यदि आप 3 क्विंटल लगाओगे, उसका उत्पादन क्षमता एक तिहाई होगा। 120 से 125 रूपये पर लीटर cost आयेगा, दुनिया में ऐसा कौन सा विषय है, जो इथनाल के प्रोडक्शन में, इथनाल गोलाशीश से बन जाता है, इससे बन जाता है, दूसरा बन सकता है। मगर छत्तीसगढ़ के चावल से कभी यह कल्पना कर सकते हैं कि बायोफ्यूल बनेगा। बायोफ्यूल का Cost per liter क्या होता है ? coft of production क्या होता है ? धान और धान की फसल का उत्पादन की कीमत क्या है ? इस उत्पादन कीमत में क्या वह वाईवल रहेगा कि किसान की स्थिति क्या होगी? आज Government of India ने चावल की कीमत में 500 रूपये कटौती कर दी। 2700 रूपये को घटाकर 2200 रूपये में Open market में दो करोड़ टन राईस को खुली निलामी के लिए कर दिया है। Thats surplus rice pedy राईस वहां पड़ा है। अब ये स्थिति में आप नयी-नयी योजना बनाते हैं, उन योजनाओं को छोड़िये। ये बायोफ्यूल से, राईस से हमारे छत्तीसगढ़ के बायोफ्यूल का उत्पादन होना cost of vivel नहीं है जिसकी लागत मूल्य में इसका फर्क पड़ेगा। उसके साथ ही साथ बहुत सारे विषय डेड़ हजार में चौदह सौ पंद्रह सौ

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

में धान बिक रहा है। व्यवस्था इस बात की है कि किसान एक महीने तक इंतजार करता रहा। एक महीने तक भटकता रहा। आपके वादे पर भरोसा किया। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अब भी वक्त है, समय पर धान खरीदी की बेहतर व्यवस्था हो। जो वादा आपने किया था उस वादे को शत-प्रतिशत पूरा करें। धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव जो प्रस्तुत हुआ है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब चुनाव था, चुनाव के वक्त कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें आपने जनता से 2500 रूपये प्रति क्विंटल धान खरीदने का वायदा किया। हमने भी वह वायदा किया था और लगभग आप लोगों ने भी किया था। हमने किया था। जनादेश आपको मिला और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि जब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो आपने 2500 रूपये क्विंटल में धान खरीदने के अपने वायदे को पूरा किया, उसके लिए आपको बधाई। (मेजों की थपथपाहट) लेकिन दूसरे साल के आते-आते मुझे लगने लगा कि आपकी सरकार हांफने लगी है आप भयभीत है। आप मुझे बोल लेने दीजिए मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये जो एक महीने का समय बढ़ा। सारी समस्या का जड़ वही से पैदा हुआ। उसके बाद दूसरी समस्या आयी एम.एस.पी. में जो खरीदने का सेन्ट्रल गर्वनमेंट का ऑर्डर था, वह खरीदी केन्द्र तक पहुंच गया तो लोगों को लगा कि पता नहीं, आप 2500 रूपये प्रति क्विंटल में धान खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे ? यह कन्फ्यूजन बना। पर जब आपने विरोधी दल की बैठक बुलायी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विपक्षी दल की बैठक बुलायी, उन्होंने वहां पर अपना पक्ष रखा, सरकार की तरफ से उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी 4 चिट्ठीयां और खाद्य मंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी। हम लोगों ने वह चिट्ठी पढ़ी। मेरे पास वह चिट्ठी सुरक्षित भी है, उसमें कहीं पर भी मुख्यमंत्री जी ने इस बात का दबाव बिल्कुल नहीं डाला कि वह 2500 रूपये समर्थन मूल्य में धान खरीदने या 2500 रूपये जो रेट छत्तीसगढ़ की सरकार ने की है उसको दिल्ली की सरकार दे ही, यह उनकी चिट्ठी में कहीं जिक्र नहीं है। उन्होंने वहां जिक्र किया है कि जो सेन्ट्रल पुल में चावल सेन्ट्रल गवर्नमेंट को लेना है वह सेन्ट्रल पुल में चावल खरीदने की अनुमति दे। इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ की सरकार और दिल्ली की सरकार के बीच में सिर्फ मतभेद इस बात पर अड़ा हुआ है कि आप सेन्ट्रल पुल में चावल सेन्ट्रल गवर्नमेंट को देना चाहते हैं, आपका जो सरप्लस चावल बचेगा और वह सेन्ट्रल गनर्वमेंट यह बोल रहा है कि अगर आप 2500 रूपये क्विंटल में खरीदेंगे तो मैं नहीं लूंगा। इसमें छत्तीसगढ़ के किसानों का क्या रोल है? 2500 रूपये क्विंटल में धान खरीदने का एक आदेश, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जब अपना जवाब देंगे तो प्रदेश की जनता और किसान को स्पष्ट रूप से संदेश दे दीजिए कि आप 2500 रूपये क्विंटल में धान खरीदेंगे। रहा सवाल दिल्ली का तो दिल्ली की

सरकार के सामने भी हम आपसे वायदे किये थे कि हम उसमें आपका समर्थन करेंगे और जिस तारीख को आपने बताया था, उस तारीख को 10 गाड़ी और रास्ते में रूकने का हमारा सब एडवांस डूब गया, आपके वायदे के मुताबिक। हमने गाड़िया बुक की थी, हमारे लोग जाएंगे। जहां-जहां रास्ते में रूकने का है वहां पूछपाछ के इंतजाम किये थे, हम तो जाना चाहते थे, दिल्ली में हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे ? हमारे प्रदेश की जनता को अगर 3000 रूपये क्विंटल भी मिलेगा तो दिल्ली जाएंगे और आप ज्यादा बोलेंगे तो अमेरिका जाने का होगा तो हम वहां भी जाएंगे। हमको जाना है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की जनता को पैसा मिले।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- भईया, आप पड़ोस वालों को भी बता दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं अपनी बात कह सकता हूं। न वह मेरे अधीन हैं न मैं इतना ज्ञानी हूँ कि सबक सीखा सकूं या कुछ बोल सकूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये पेपर नहीं पढ़ रहा हूं। सरकारी बयान पढ़ रहा हूँ। माननीय मंत्री जी, आपके ही इस जवाब में इस वर्ष खरीफ 2019 में धान का रकबा लगभग 39 लाख हेक्टेयर है, जिससे 125 लाख मे. टन धान उत्पादन होना अनुमानित है। इस प्रकार कुल 85.60 लाख मे.टन धान क्रय किया जाना है। इसका मतलब है कि 40 लाख मे.टन धान किसान के पास रहेगा। वह किसान, चूंकि एक महीने की देरी हुई है इसलिए वह बेच नहीं पा रहा है। पहले 1 नवम्बर को धान बिक्री होती थी, उसको पैसा मिलता था, यह आश्वस्त होता था उसके आधार पर वह कहीं से भी लेन देन करके अपना खर्चा चला लेता था। अब एक बोरी धान, हम लोग खुद बेचे हैं जब वर्षों पूर्व यह नियम कायदा नहीं था कोई खर्चा आ गया कोई मेहमान आ गया, किसी की शादी ब्याह में पैसा भेजना है, कोई कपड़ा लत्ता लेना है, कोई दवाई लेना है या किसी के यहां कुछ सामान भेजना है तो छोटा-मोटा एक क्विंटल धान, आधा क्विंटल धान ले जाकर सेठ जी के दुकान में बेच देते थे और वह पैसा लाकर अपना खर्चा चलाते थे, अब वह सेठ जी मेरे जैसे एक-एक क्विंटल धान बेचने वालों का 50 क्विंटल धान खरीद लिया तो वह बिचौलिया हो गया, वह तस्कर हो गया, वह सरकार को डैमेज करने के लिए हो गया । बृहस्पत सिंह जी आप बहुत बोल रहे थे कि आपके वहां कोई भाजपा का नेता है, उसके यहां राईस मिल में छापा मारो।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय मैंने छापा मारो नहीं कहा, मैंने कहा कि जो पकड़ा गया है, उसका सबूत बता रहा हूं कि वहां आज भी है।

श्री धर्मजीत सिंह :- चलिये मैं वही बात बोलता हूं। मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूं कि बीजापुर में, राजनांदगांव के बार्डर में, गरियाबंद में, महासमुन्द के बार्डर में आपने अपने जवाब में बताया है कि कलेक्टर, एस.डी.एम., तहसीलदार, आर.आई., डी.एफ.ओ., एस.डी.ओ. फारेस्ट, खनिज अधिकारी, इवन कोटवार तक मुस्तैदी से लगे हुए हैं। बाहर से धान नहीं आना चाहिए। जब आप इतनी मुस्तैदी से

लगे हैं तो बाहर से धान कैसे आ रहा है ? उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? आपका प्रशासन तंत्र इतना पंगु है कि आपके कलेक्टर, एस.डी.एम, डी.एफ.ओ. सब अधिकारी लगे हुए हैं उसके बाद भी रामानुजगंज में धान नहीं पकड़ पा रहे हैं ?

श्री बृहस्पत सिंह :- जब कश्मीर के बार्डर में बारूद घुस सकता है तो हमारे इलाके में धान क्यों नहीं घुस सकता जहां सब कुछ होता है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, अब ये बेतुकी बात हुई न। ये बलरामपुर के बार्डर को कश्मीर के सोपोर से तुलना कर रहे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय बेतुकी बात नहीं है। आप वहां देखें हैं, वहां खाली 150 किलोमीटर बार्डर है।

श्री धर्मजीत सिंह :- प्रशासन तो इसी को कहते हैं, वहां तो वह लोग कई हजार किलोमीटर में रक्षा कर रहे हैं, 150 किलोमीटर में आपका प्रशासन रक्षा नहीं कर सकता है ? बिहार और झारखंड के धान को छत्तीसगढ़ आने से रोको। हमारे छोटे-छोटे गरीब किसान जो गांव में धान बेचने वाले लोग हैं, अपना खर्च चला रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- धर्मजीत भैया, अगर ये नहीं रोक पा रहे हैं तो इनकी सरकार की असफलता है, अगर घूस रहे हैं तो आपकी असफलता है, आप रोक नही पा रहे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- वह तो बहुत सारे लोग केन्द्र में बैठे हैं, वह लोग आ कर घुसपैठ कर रहे थे और उनके गांव में पकड़ा गया।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपसे कोई व्यक्तिगत बहस नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, समय कम है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का ध्यान इसलिए आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो तस्कर, बिचौलिये, कोचिये हैं, उनमें और गांव के किसान में जरूर फर्क करने की आप कृपा करें। ऐसा निर्देश जारी करें। क्योंकि गांव का आदमी अपना 2 क्विंटल धान भी बेचे और फुड ऑफिस में चक्कर लगाये, ये ठीक नहीं होगा। अब 5 दिन तो और बचे हैं, 5 दिन में बार्डर की रक्षा कर लीजिए, 5 दिन के बाद आप क्या करने वाले हैं, वह अभी आप जवाब में बतायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, देवभोग, धमतरी में धान को सड़क पर फेंक रहे हैं। अब वह नेता फेंक रहे हैं या किसान फेंक रहे हैं, लेकिन ये संकेत अच्छा नहीं है। रजिस्ट्रेशन के बाद भी फिर से जांच हो रही है, किसानों का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन हुआ। अभी मुझे पता चला है प्रशासनिक अधिकारी उसका भी फिर से वेरीफाई करके उसको कम कर रहे हैं। जंगल में रहने वाले जो आदिवासी हैं, उनका ऑफलाईन रजिस्ट्रेशन हुआ है, वह लोग वहां पर कम्पयूटर में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाये हैं। कम से कम लोरमी के

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

जंगल में मुझे जो शिकायत मिली है, वह मैं बता रहा हूं। तो सही हक तो उनका है। ऑनलाईन वालों से भी उनका हक ज्यादा है जिनके पास सुविधा नहीं है, फोन नहीं है, मोबाईल नहीं चलता है, किसी तरीके का कोई कम्यूनिकेशन उनके पास उपलब्ध नहीं है, कम से कम उसको कम न किया जाये। मंदिर, मस्जिद, ट्रस्ट सबके धान पर आपने प्रतिबंध लगा दिया है। ये भी गलत है। उससे विकास के कार्य होते हैं, समाज के सेवा के काम होते हैं, गरीबों को खाना खिलाया जाता है और भी कई पुण्य के काम होते हैं। यह ठीक नहीं है। इस पर भी जरा आप विचार करिये कि ये सार्वजनिक हित में काम करने वाली संस्थाओं को सरकार की नीतियों, रीतियों का फायदा मिलना चाहिए।

माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग धान, धान कई साल से सुनते आ रहे हैं, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार ये भी सुनते आ रहे हैं। आप और हम यहीं पर बैठते थे। इनके बारे में बोलते थे कि ये धान के रखरखाव की व्यवस्था ठीक से नहीं कर रहे हैं। आप तो सरकार में आ गये, आप तो पहल करिये कि धान की सुरक्षा के लिए जो पक्के प्लेटफार्म बनना चाहिए, धान का हिसाब-किताब कम्पयूटराईज्ड रहना चाहिए। दो-तीन साल पहले सड़े हुए धान का जो भूसा जमाते हैं, वह लेयर दूसरा सत्र आ जाता है, लेकिन वह लेयर भी साफ-सुथरी नहीं बदलते हैं। वही लेयर रहती है ताकि कभी भी कुछ गड़बड़ हो, वह सड़ गया करके दिखाने के काम आये। नया धान का भूसा बिछाओगे, उसको सड़ने में भी साल भर लगेगा। लेकिन दो साल पुराना भूसा बिछा रहेगा, उसके ऊपर नया धान आयेगा। कैसे होता है, कौन ट्रांसपोर्टर आता है, कौन बिना बिल्टी के, बिना रायल्टी के कैसे ले जाता है ? हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार होता है । इसको आप रोकने की कृपा करें । क्योंकि यह हमारे प्रदेश के पैसे का है । आपका यदि एक पैसा भी खराब हो रहा है तो यहां की जनता का पैसा खराब हो रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम बात यह कह रहा हूं कि चाहे आप दिल्ली से लड़ें, चाहे नफ़रत से बात करें या प्रेम से बात करें, दिल्ली से जैसी बात करना है, हम इस मामले में समर्थन कर रहे हैं लेकिन आपने 2500 रूपए में धान खरीदने की बात कही है तो आज कृपा करके इस सदन के माध्यम से घोषणा कर दीजिए कि आप धान खरीदेंगे । इससे ज्यादा इस मामले में न आगे बोलना है न पीछे । मैं विषय के अंतर्गत हूं और विषय के अंतर्गत ही आपसे आग्रह कर रहा हूं ।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर (महासमुंद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज स्थगन पर चर्चा हो रही है और विपक्ष के साथी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, इसके पहले भी जब इनकी सरकार थी तो 270 रूपए बोनस देने की बात करते थे । चुनाव निपटता था उसके बाद बोनस देने के नाम से पीछे हट जाते थे । 2013 के चुनाव में इन्होंने 300 रूपए बोनस देने और 2100 रूपए में धान खरीदने की बात कही । अंतिम-अंतिम में माननीय बृजमोहन जी की विज्ञप्ति आती है कि हम लोग लगभग 2100 रूपए में धान खरीद रहे हैं, 300 रूपए बोनस दे रहे हैं लेकिन आज हमारी सरकार के

मुख्यमंत्री जी ने पिछले सीजन में 2500 रूपए में धान खरीदी की है । जिससे किसानों में खुशहाली आई है । इससे पूरे किसान खुश हैं। केन्द्र की सरकार इस चावल को नहीं खरीदने की बात कहती है । मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि 14 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे अमले के साथ जा रहे हैं, आप भी आएं, संयुक्त चर्चा करते हैं क्योंकि किसान उनके भी किसान और हमारे छत्तीसगढ़ के किसान हैं, सभी सदन के साथी एक साथ जाएं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करें कि हमारा धान खरीदें । बहुत बहुत धन्यवाद् ।

अध्यक्ष महोदय :- विषय विशेषज्ञ के रूप में चन्द्राकर जी आपको 5 मिनट का समय दिया जाता है (हंसी)।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- मोहम्मद अकबर जी मेरे बड़े आदरणीय हैं साहब ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इनको विषय विशेषज्ञ का एक प्रमाण पत्र जारी कर दीजिए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- बोलना, एक प्रकार से प्रमाण पत्र ही है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अजय जी आपको विषय विशेषज्ञ कहा गया है, आप उत्तेजित मत होइएगा, इनको देखकर भी आपको उत्तेजना नहीं आनी चाहिए । यहां की बात होगी तो हमें सुझाव दीजिएगा और वहां की बात होगी तो भी बोलिएगा । अभी जैसा कि कौशिक जी ने शुरूआत में कहा कि मोदी जी भी किसानों की कोई बात नहीं सुन रहे हैं । आपको भी सच्चाई बोलना है आज ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप अपने नम्बर एक और नम्बर दो को कंट्रोल में रखिएगा तो वे ठीक से बोलेंगे (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरी उर्दू गलत होगी तो आप उसको ठीक कर दीजिएगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- और कोई बात होगी तो मुझको भी बता सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, 17.24 लिख रहा हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- धूल चेहरे पर थी ग़ालिब, और उम्र भर आईना साफ़ करते रहे । ये धान खरीदी का पूरा प्रकरण एक इपिक की तरह है, महाकाव्य । रामायण और महाभारत जैसे बना, वैसे ही इसकी पटकथा लेखन टी.एस.सिंहदेव साहब ने किया और उसमें मेन किरदार प्ले माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं । हमारे वांग्मय में 12 साल और 14 साल का वनवास मिलता है । वनवास हो गया 15 साल का । अब 15 साल का वनवास हो गया तो किसी तरह सत्ता में आना है तो आप कुछ भी लिखना है और किसी भी हद तक जाना है । जब कुर्सी में बैठे और जब कांटा निकल आया तो फिर अभी मुख्यमंत्री जी को अपने को छत्तीसगढिया साबित करने में बड़ा प्रयत्न लग रहा है। तो फिर मुख्यमंत्री जी का गम्मत शुरू हो गया।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वे छत्तीसगढिया आदमी हैं।

असंशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- अब छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शेर की सवारी है। आपने 25 रूपये क्विंटल कहा। शेर की सवारी की। आपने मोदी जी को नहीं बताया था कि साहब, मैं 2400-2500 रूपये में शेर की सवारी कर रहा हूं। आप मुझे उतार दीजिए मैं चढ़ तो गया हूं। इसलिए शेर की सवारी करने से पहले सोचना था। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है। पटकथा की जो शुरूआत हुई। ये पटकथा के लेखक राहुल गांधी जी के सामने एकदम सावधान की मुद्रा में खड़े हैं। क्या आपके पास धान खरीदने के लिए पैसा है। जी हुजूर। (हंसी) आपके पास 2500 रूपये प्रति क्विंटन धान के लिए है? जी हुजूर आला। (हंसी) आपके पास 2 साल का बोनस देने के लिए पैसा है ? हुजूर-ए-आला। आपके पास और क्या-क्या है? सब है? कितना पैसा लगेगा? 30 हजार करोड़ हमारे पास है हुजूर-ए-आला। (हंसी) वीडियो पूरे छत्तीसगढ़ ने देखा है सरकार। (हंसी) अब रोना क्यों? टी.एस. सिंहदेव साहब, 6 फुट 3 इंच के आदमी हो। (हंसी) और..।

श्री बृहस्पत सिंह :- 7 फुट-7 फुट। आप गलत नाप बता रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- रोना क्यों? किस बात पर रोना? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद कहानी शुरू होती है। जब केन्द्र सरकार ने अक्टूबर माह में बता दिया, मैं उस पत्र को ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। पत्र पढ़ने के पहले बता देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे प्रकरण में पद और गोपनीयता के शपथ का उल्लंघन किया है, जान-बूझकर राजनीति का इस्तेमाल करने के लिए। महामहिम का पत्र वायरल हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने जो दो बार, तीन बार पत्र लिखा, वह सोशल मीडिया में वायरल हुआ। धान खरीदने की गंभीरता नहीं है। गंभीरता यह है कि इसे राजनीतिक स्वरूप कैसे दिया जाए, क्योंकि शेर की सवारी तो हम कर चुके हैं। किसान राजनीति का शिकार हुआ। आप 2500 रूपये क्विंटल में खरीदे। ठीक है हम दो उपचुनाव हारे। आप 2500 रूपये में खरीदने के बाद और क्या-क्या कर्जा माफी बोलते हैं। 9 लोकसभा सीटें आप कैसे हार गये? आप कारण ढूंढेंगे। कल विनियोग में बात करेंगे क्योंकि आज आपने कम समय दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने इन्हें सूचित कर दिया। मैं एक लाइन बर पढ़ूंगा। यह यहां के चीफ सेक्रेटरी के नाम से केन्द्रीय सचिव का पत्र है। You may be aware that Central Pool Stock of Rice is already much above the buffer stock norms. इससे आगे और भी है। मुख्य सचिव साहब बैठे हैं। उसका पहला स्थगन है और विधान सभा का पहला दिन है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हिन्दी ट्रान्सलेशन भी करके बता। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं और मेरे दल के साथी उसके बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे। हम आपसे क्षमा चाहते हैं साहब। उनको बोलने दीजिए। हमारी तरफ से उनका दूध भात है। (हंसी) माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे साबित करवाना है। धान खरीदी एक तारीख को शुरू होगी। जो बार-बार बातें आ गई हैं, मैं उन्हें रिपिट नहीं करूंगा। आज की तारीख में मैं जब बोल रहा हूं। खाता संख्या 54 लाख। किसान संख्या

37 लाख। पंजीकृत संख्या पिछले वर्ष 20 लाख। पिछले साल धान की खेती हुई 40 लाख हेक्टेयर। पंजीकृत रकबा 27 लाख हेक्टेयर। पंजीकृत रकबा में सत्यापन का काम। अब सत्यापन के काम में जो चिट्ठी लिखी है पूरे 27 जिलें की कुल पंजीकृत किसानों की संख्या 19 लाख है। यह चिट्ठी है, मैं आपको दे देता हूं। यह सरकार का पत्र है। सोसाइटियों में जो पंजीकृत है वह और राजस्व विभाग में जो पंजीकरण है, अभी केवल 32 प्रतिशत खाते का मिलान हुआ है और शत प्रतिशत किसान तीन दिन बाकी है। कहां किसान धान बेचेंगे? कौन सा खाता मान्य होगा? राजस्व विभाग का होगा या सोसाइटियों में जो पंजीकृत है, वह मान्य होगा। मैं आज भाषा में विरोध दर्ज किया। एक पत्र और है। मैं रख देता हूं। एक चिट्ठी गई कि मेढ़ में राहेर बोये। उसके रकबे को घटाकर भेजिए। यह तो अत्याचार की इम्तिहान हो गई। किसानों का आप मजाक क्यों बना रहे हैं?

श्री बृहस्पत सिंह :- उस चिट्ठी की कॉपी सिर्फ आपके पास है।

श्री अजय चन्द्राकर :- यहां से जाकर उसको भी वायरल कर दूंगा। जैसे उनका वीडियो देखा है वैसे उसे भी आप पढ़ लेना। घोषणा पत्र में आपने बात कही है, क्योंकि आपको सत्ता में आना था। अब दिल्ली इस नक्शे में कहां पर आ गई? अब इसके साइड इफेक्ट देखिये। आप जो बार-बार कहते हैं, बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि रकबा बढ़ा, प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे। माननीय कृषि मंत्री जी एक दूसरा साइड इफेक्ट बता देता हूँ। पिछले साल मक्का खरीदी का पंजीयन कितने किसानों का था और इस साल मक्का खरीदी का पंजीयन कितने किसानों का है। यदि एम0एस0पी में 1750 रूपया, जो भी मक्का मूल्य है और यदि मक्का किसान 2500 रूपये में उनके धान को खरीदते हैं तो वह मक्का क्यों बोयेगा ?

अध्यक्ष महोदय :- स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये। मैं समझता हूँ कि सदन सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्थाई हल, जो व्यवस्थाएं , छत्तीसगढ़ के ऐसे अर्थशास्त्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भी सलाहकार हैं, आप महान विद्वान हैं, मैं तो सिर पकड़ लेता हूँ कि 24 हजार करोड़ रूपये गये। दीवाली मनी, शादी हुई, फटाका फूटा, गाड़ी लिया गया, राजस्व व्यय से आर्थिक मंदी नहीं आती, यह अस्थाई प्रभाव है। दुनिया के किसी भी अर्थशास्त्री से पूछ लीजिये। छत्तीसगढ़ के किसान की समस्या का स्थाई हल के लिए, इसकी डायवर्सिटी के लिए, 44 इंच बारिश के लिए, इसके रबी के लिए हम क्या स्थाई हल करना चाहते हैं ? यह सरकार को जो गम्मत करने वाली सरकार है, किसानों के साथ प्रहसन्न करने वाली सरकार है, वह स्थाई हल की ओर नहीं बढ़ रही है। वह सिर्फ और सिर्फ वही नाटक, जो मुझसे माननीय जोगी जी ने कहा कि मकान का घेराव नहीं करना

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

चाहिए। उनके राज में मकान के घेराव में तो हम लोग हाथ-पैर तुड़वाये हैं। दिल्ली नहीं जाना चाहिए। दिल्ली जा रहे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- लेकिन जोगी जी का घर, जब वे मुख्यमंत्री थे तो आप ही लोग घेरने गये थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- दिल्ली गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। जब 6 हजार करोड़, 7 हजार करोड़ रूपया कैम्पा का मिलता है, तो संघीय व्यवस्था जोरदार लगने लगती है, केन्द्र की दिल्ली सरकार जोरदार लगने लगती है। लेकिन जब धान के बारे में चिट्ठी लिखती है, तो लगता है कि पुलिस का पत्र लीक हो जाता है, कौन-कौन से औद्योगिक संस्थानों में कितने बल तैनात हैं। मोहन मरकाम जी आर्थिक नाकेबंदी की बात करते हैं, तब इनको संघीय व्यवस्था नाम का जो शब्द, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जिस बात को बोले तो उसको माननीय मंत्री जी हैं, अकबर जी के बाजू में बैठते हैं, उसको तुरन्त दोहरायेंगे। एक बार संघीय व्यवस्था बोले तो संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था बोलते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब प्रशासन के पास कोई काम नहीं है। नथिंग। एक भी जनहित के काम नहीं हैं। मेरा आज का शून्यकाल था कि धमतरी जिले के वन क्षेत्र के किसानों को नक्शा-खसरा नहीं मिल रहा है। एक टॉक, ओनली वन टॉक, पकड़ो, मारो, छीनो, साबित करो, रोको, धान नहीं आना चाहिए। अभी तो आपकी खरीदी ही शुरू नहीं हुई है तो कहां का अवैध, कैसे अवैध ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब दूसरी बात। हरूना धान की लुआई हो गई है। जांजगीर सबसे सिंचित जिला है। अब उस धान में मिट्टी आ चुकी है। मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ में वह हरूना धान नहीं खरीदा जायेगा। वह क्वालिटी के नाम पर निरस्त होगा। वह दो जगह खरीदा जायेगा- दुर्ग जिले में और बेमेतरा जिले में खरीदा जायेगा। यह विशेषाधिकार प्राप्त सिर्फ दुर्ग और बेमेतरा जिले के हैं। हरूना धान, मैंने मुख्यमंत्री जी को एक ट्वीट किया था कि आप छत्तीसगढ़िया वाद के, आपका अभिनंदन करता हूँ। जिस दिन से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हुई, उस दिन से कोई ब्यारा बनाता नहीं है। खरही कोई रखता नहीं है। हार्वेस्टर से निंजाई होगी, सीधे सोसायटी में जाता है। एक महीने की सूखद। अब आज 01 दिसम्बर 15 फरवरी, डेढ़ महीने की अवधि कम की है, यहां सारी सरकार उपस्थित है, उसमें 20 दिन की छुट्टी है। आप अभी कैलेण्डर निकाल लीजिये। उसके बाद बोरे की सप्लाई हेतु हर साल खरीदी बंद, परिवहन में हर साल खरीदी बंद। मैं आज सदन में पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि यदि 10 से 15 दिन किसानों की धान की खरीदी हो गई तो बहुत है। एक नाटक। अब दूसरी बात, पैसा। आप छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कर्ज लीजिये न। धान खरीदी के लिए 21 हजार करोड़ रूपये का इंतजाम आज की तारीख तक पूरा नहीं हुआ है, जो इनका अनुमान है। आज छत्तीसगढ़ की हालत क्या है ? आज आप उस गौरवशाली परम्परा को निर्वहन करते हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए

जीया है, छत्तीसगढ़ के लिए सोचते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए किया है। छत्तीसगढ़ के अधिकारी, छत्तीसगढ़ के मंत्री अब दिल्ली, मुम्बई जाते हैं तो उसकी इमेज यह है कि किसी समय में अनाथालय में बैण्डपार्टी आती थी, हम लोग पैसा देते थे, यह बैण्ड पार्टी आई है और पैसा देंगे, इन लोगों की इमेज, सरकार की इमेज, छत्तीसगढ़ की इमेज यह बना दी गई कि दिल्ली जाते हैं, कहीं भवन में जाते हैं, किसी बिल्डिंग में जाते हैं तो सिर्फ पैसा मांगने जाते हैं।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो जो अवधि हमने 15 दिन कम की है, वह पूरी अवधि को कम नहीं किया है । उतनी अवधि 15 फरवरी तक बढ़ायी है । बीच में छुट्टी की बात अलग है । आप छुट्टी को भी जोड़ेंगे और जो आपने कहा कि सिर्फ 15 से 20 दिन किसानों का धान खरीदा जाएगा, वह आप गलत बोल रहे हैं । आप छुट्टी काटकर देख लीजिए, उसके बाद भी अवधि कम नहीं होगी । एक बात और कहना चाहता हूं । आप यह देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में आखरी बार पानी किस दिन तक गिरा है और आप खुद किसान हैं, आप जानते हैं । जब जमीन गीली होती है तो हार्वेस्टर नहीं चलता है और आज के दिन में बिना हार्वेस्टर की कटाई करना बहुत मुश्किल है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- वे किसान हैं नहीं, किसान थे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अभी तो किसान हाथ से कटाई कर रहा है ।

श्री उमेश पटेल :- आप मेरे साथ चलिए, मेरे क्षेत्र में मैं आपको घूमाता हूं या आपके क्षेत्र में चलते हैं ।

श्री मनोज सिंह मण्डावी :- अध्यक्ष महोदय, पूरा धान बाहर से लाये हैं और ये लोग उसको बेचने की तैयारी में हैं । अभी किसान धान लू रहे हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, इधर भी सारे लोग किसान हैं, उधर भी सारे लोग किसान हैं। राजनीतिक भाषा में किस तरीके से बातें हो सकती हैं, आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, लेकिन खेती की क्या हालत है, माननीय उमेश जी ने जो कहा । मुझे घोर आपत्ति दूसरे शब्दों में है कि हम दिल्ली जाते हैं । अभी हम केन्द्रीय खाद्य मंत्री जी से मिलने गए थे, हम अभी केन्द्रीय कृषि मंत्री जी से मिलने गए थे । अजय जी, आप क्या कह रहे हैं ? माननीय अध्यक्ष जी ने आपको विशेषज्ञ कहा । हम अपना हक मांगने जाते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप मांगिए न, मैं उसमें कहां कुछ बोल रहा हूं?

श्री रविन्द्र चौबे :- हम छत्तीसगढ़ का हक मांगने जाते हैं । आप किस तरीके से कह रहे हैं । हम किसानों के लिए जाते हैं तो हम क्या भीख मांगने जाते हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं ? अभी तो मुख्यमंत्री जी बोलेंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- मुख्यमंत्री जी भी बोलेंगे, लेकिन इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है । सबेरे जब आप बोल रहे थे तो एक नये माननीय सदस्य ने एक लाईन कह दिया तो आपने कहा कि क्षमा मांगिए और आज आप किन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने आपके लिए कहां अपमानजनक कहा ?

श्री रविन्द्र चौबे :- ये सारी सरकार जाती है तो किसके लिए जाती है ? हम वहां भीख मांगने जाते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने ऐसा नहीं कहा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप बिल्कुल गलत शब्द का उपयोग कर रहे हैं । हम अपने अधिकार के लिए जाते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको गलत लगेगा तो मैं माफी मांग लूंगा । मैंने यह कहा...।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चौबे जी को इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है और यह भी बताने की जरूरत नहीं है कि किसके लिए जाते हो । आप किसान के लिए कम जा रहे हो, अपने घोषणा-पत्र को पूरा करने के लिए जा रहे हो और इसलिए आपको हमने कभी नहीं कहा कि आप मत जाईए । आपको जाने का अधिकार है, संघीय व्यवस्था है । आप संघीय व्यवस्था में जाकर जिनसे बात करना है, आप करिए । हमको उसमें कहीं पर दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जाते हैं । माननीय अजय चन्द्राकर जी और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि संघीय व्यवस्था है, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन दिल्ली में बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री को समझाईए कि छत्तीसगढ़ के किसान भी हिन्दुस्तान के किसान है, यहां के किसान भी इस देश के किसान हैं, यह देश के प्रधानमंत्री को समझाईए ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता जी, अभी आपने कहा कि आप लोग घोषणा-पत्र को पूरा करने के लिए जाते हैं । आपको याद होगा, आपके पुराने मुखिया डॉ. रमन सिंह जी ने जब 21 सौ रूपये की घोषणा की थी, तब भी उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेश बघेल जी थे । उन्होंने कहा कि हम लोग आपके साथ दिल्ली चलेंगे, आप चलिए तो और जाकर मिलिए और मिलकर वहां धरना-प्रदर्शन करेंगे तो हम लोग करेंगे, तब भी हमने कहा और आज भी कह कहते हैं । हम अपनी बात पर अडिग हैं । (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो हमेशा रविन्द्र चौबे जी और भूपेश बघेल जी का हमेशा सम्मान करने वाला हूं । मैं जल्दी समाप्त करूंगा ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- मैं यह नहीं बोल रहा हूं, आपकी सांसे फूल रही है, आप दो मिनट में समाप्त कर दीजिए । (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- जी । अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रधानमंत्री के पास जाने में या विभागीय मंत्री के पास जाने में कहीं आपत्ति नहीं की । मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ के अधिकारी बैंक में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो यह समझ लेते हैं कि ये सिर्फ कर्ज लेने आये हैं । मैंने यह कहा और दूसरी बात मैंने नहीं कही। अब इसका दूसरा साईड इफेक्ट । छत्तीसगढ़ में पिछले साल का धान मतलब चांवल अभी तक रखा है । 32 लाख टन के बाद इस साल का चावल आयेगा । उसके बाद जो थ्रस सेक्टर का उद्योग यहां पर है, क्या नीति हो रही है, किसी राईस मिलर ने पंजीयन नहीं करवाया है? एक आर्डर निकल गया कि साहब सबको पंजीकृत माना जायेगा । कितनी यूनिट बिजली में, कितने दिन तक खपेगा? कोई मतलब नहीं । 350 करोड़ रूपया से ज्यादा राईस मिलर मंडी टैक्स देते हैं, माननीय कृषि मंत्री जी को मालूम है, उससे किसी को मतलब नहीं है । कितने रेजा, हमाल, कुली, यह जो 24 हजार करोड़ रूपये की बात करते हैं, महीने-डेढ़ महीने बेरोजगार हो गये, कितने पैसे की क्षति हुई, कोई मतलब नहीं? छत्तीसगढ़ का चावल रेट के कारण एक्सपोर्ट जो है, उड़ीसा और आन्ध्र के मुकाबले कम हो गया, इसकी चिन्ता सरकार को बिल्कुल नहीं है । सवाल इस बात का नहीं है कि आप क्या नीति अपना रहे हैं? किसानी को आपने राजनीतिक हथियार बनाया, यदि आप छत्तीसगढ़ के हितैषी होते, उस दिशा में बढ़ते। फसल क्राप की जो डायवर्सिटी है या और भी जो दूसरा विकल्प है, जो कृषि में पूंजीगत निवेश है, राजस्व निवेश की जगह में, उस दिशा में बढ़ते । लेकिन आपने उसको यदि औजार बनाया है, शेर की सवारी आपने की है, दोष किसी का नहीं है, आपको देना होगा, दो साल का बोनस भी देना होगा, कर्जा माफ नहीं है, उसको भी करना होगा, जितने घोषणा पत्र है, गंगा जल पिये हैं, क्या पिये हैं, मैं नहीं जानता ? मैं हमेंशा बोलता हूॅं कि सब पूरा करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, संघीय व्यवस्था बार-बार आती है, कर राजस्व का जो सिस्टम बना है, वित्त आयोग का जो गठन होता है, उसमें छत्तीसग़ढ़ को जितना कर राजस्व मिलना चाहिये, उतना कर राजस्व देते हैं, मिल रहा है, प्रति प्रान्त को मिलता है, विशेष परिस्थितियों में जिन लोगों को छत्तीसगढ़ में 14 आकांक्षी जिले हैं, अलग योजनायें हैं, जिसमें अलग से मिलना चाहिये, वह मिलता है । आपने अपने दम पर यदि घोषणा की है, आपने यदि राहुल गांधी के सामने यदि कमिटमेंट किया है तो किसी को दोषारोपण नहीं किया जायेगा और सांसद बने हैं, जनता के जनादेश से, वह मुख्यमंत्री जी कांग्रेस पार्टी से पूछकर प्रश्न नहीं करेंगे, वह प्रश्न करने के लिए नहीं चुने गये हैं, यह कहने का अधिकार किसी को नहीं है । वह निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, आपसे पूछकर प्रश्न नहीं करेंगे, आपने पूछकर घोषणा पत्र नहीं किया था, इसलिए दांया-बांया मत करिये, आजू-बाजू मत करिये, इससे बढ़कर यदि इंदिराजी का सम्मान करते हैं, यदि राहुल गांधी का सम्मान करते हैं, यदि

सोनिया गांधी जी का सम्मान करते हैं, प्रियंका गांधी जी का सम्मान करते हैं, वाड्रा जी का सम्मान करते हैं तो न्याय स्कीम को भी लागू कीजिए । जो न्यूनतम आय स्कीम कहा है, उसको भी आपको लागू करना चाहिये, उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिये, उन्होंने जो कहा है, उसका सम्मान करना चाहिये, आपको जनादेश मिला है, उस जनादेश में यह भी शामिल है,

इसी बात के साथ आपको प्रणाम करते हुये, धन्यवाद देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद । माननीय मुख्यमंत्री जी ।

श्री केशव चन्द्रा :- माननीय, आज आप इतना अच्छा भाषण दिये, आपको कोई नहीं टोके ।

श्री रविन्द्र चौबे :- कैसे टोक देते, भावी नेताओं का नाम ले रहे थे । हंसी

श्री भूपेश बघेल :- लेकिन आप उसको भूल गये ना ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं सभी विपक्षी दल के सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने स्थगन लाया है । प्रदेश के किसानों के हित में बात करने के लिए यह स्थगन लाया गया है और इसका मैं स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ । धन्यवाद उन सभी राजनीतिक दलों के लोगों को भी देता हूँ, जिन्होंने इस बात का समर्थन किया कि 25 सौ रूपये प्रति क्विंटल में धान खरीदी करने के लिए जो भारत सरकार के तरफ से पत्र आया कि आप धान के लिए 25 सौ रूपये देंगे तो आपका चावल नहीं खरीदा जायेगा । उस मामले में भी जिन राजनीतिक दल के लोगों ने समर्थन दिया, उनको भी धन्यवाद । सभी किसान संगठनों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस परिस्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार के समर्थन में खड़े हुये । उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ जो आज स्थगन की चर्चा में जो भाग लिये । माननीय धरमलाल कौशिक जी, नेता प्रतिपक्ष, माननीय मोहन मरकाम जी, अजीत जोगी जी, धनेन्द्र साहू जी, बृजमोहन अग्रवाल जी, केशव चन्द्रा जी, शिवरतन शर्मा जी, संतराम नेताम जी, डॉ.रमन सिंह जी, धर्मजीत सिंह जी, विनोद सेवनलाल चन्द्राकर जी, श्री अजय चन्द्राकर जी, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ । बहुत सारे साथी बोलना चाहते थे, समय की अपनी मर्यादा है, उसके कारण से बोल नहीं पाये । मैं उन सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूँ, जिनकी भावनायें इस सदन में समाहित है ।

अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में धान के मामले में आज से नहीं, जब मध्यप्रदेश में थे, या उसके पहले सी.पी.बरार में थे, तब भी धान के बारे में चर्चा होती रही । धान की चर्चा चाहे मध्यप्रदेश का सदन हो या छत्तीसगढ़ का सदन हो इस मामले में यहां के जनप्रतिनिधि बड़ी मुखरता से बात उठाते रहे हैं। हम लोगों को याद है जब पूरे देश में अनाज की कमी होती थी तब सरकारें चावल उपार्जन के लिए लेव्ही तक लगायी थीं, बांध बंदी किए थे उस समय भी किसान आंदोलनरत थे कि हम क्यों लेव्ही पटायें। यहां के किसानों ने इंदिरा जी की जो हरित क्रांति हुई उसका आंदोलन किया उसके बाद देश के किसानों ने जो

अनाज उत्पादन किया आज देश में जो आवश्यकता है उससे कहीं तीन गुना अनाज देश के भंडारों में भंडारित है। आज अनाज रखने की जगह नहीं है ये समस्या भारत सरकार की भी है। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ में हम ही लोगों ने सबसे पहले धान खरीदी की शुरूआत की। अध्यक्ष महोदय, आप उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और आपकी अध्यक्षता में एक बैठक महाबैठका हुई थी जो कि वासुदेव चंद्राकर जी के गांव में उनकी जयंती के अवसर पर हुई थी और उसमें सबसे पहले प्रस्ताव हुआ था कि धान में 200 रूपये क्विंटल मिलना चाहिए। फिर आपने जो घोषणा पत्र तैयार किया उसमें 250 रूपये कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 270 रूपये किया। किसी साल मिलता था और किसी साल नहीं मिलता था। वह दौर निकल गया। फिर जो समय आया, केंद्र में सरकारें आती रहीं, जाती रहीं, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने न केवल धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि की बल्कि केन्द्र सरकार से भी दो साल का बोनस एक साल 50 रूपये और एक साल 100 रूपये दिया था। परिस्थितियां बदलीं और केन्द्र में एन.डी.ए. की सरकार बनी। उस समय आपको याद होगा, आपके घोषणा पत्र की कॉपी मेरे पास भी है आपने कहा था कि हम 2100 रूपये समर्थन मूल्य की पहल करेंगे और 300 रूपये बोनस देंगे। 2013 के चुनाव के बाद आपने दिया भी लेकिन जून 2014 में भारत सरकार ने एक पत्र जारी किया कि यदि आप बोनस देंगे तो फिर आपके यहां से चावल नहीं खरीदा जायेगा। स्थिति क्या बनी? स्थिति यह बनी कि आप दूसरे साल से बोनस देना बंद कर दिये। धान पहले अलग-अलग सोसायटियों में 18, 20, 22 क्विंटल खरीदी होती थी, उसे कम करके आपने 10 क्विंटल किया फिर 12 क्विंटल किया फिर 15 क्विंटल कर दिया। लेकिन सदन में हम लोग लगातार कहते रहे जिसके बारे में उमेश पटेल जी ने उल्लेख किया, हमने कहा कि डॉ. रमन सिंह जी आप प्रधानमंत्री जी से समय ले लीजिए, हम आपके साथ दिल्ली जाने को तैयार हैं। ये राजनीति का विषय नहीं है, किसानों का विषय है। हम दिल्ली जाने को तैयार हैं, आप समय तो ले लीजिए, आप भले ही चुपचाप बैठे रहिए, हम लोग बोलेंगे। छत्तीसगढ़ में वैसे भी जो परिस्थितियां हैं, जिसके बारे में अजीत जोगी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि यहां पर विपरीत परिस्थिति में अनाज का उत्पादन करते हैं। यहां बस्तर और सरगुजा में सिंचित रकबा बहुत न्यूय है। कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां शून्य प्रतिशत है। किसी में एक प्रतिशत, दो प्रतिशत या चार प्रतिशत है और वहां सिंचाई होती नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उसके बाद भी किसान अनाज उत्पादन कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो फसल चक्र परिवर्तन की बात हो रही है, हम लोग भी चाहते हैं कि फसल चक्र परिवर्तन हो लेकिन छत्तीसगढ़ के मौसम की जो स्थिति है, दूसरी तरफ तो एक ही मानसून आता है किंतु हमारे छत्तीसगढ़ में दो मानसून आते हैं। मुंबई से आने वाला मानसून भी हमारे छत्तीसगढ़ में आता है जिसमें हम बोआई और रोपाई करते हैं और धान पकाने का जो काम होता है वह बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से हम लोग फसल पकाते हैं और दोनों मानसून

हमारे छत्तीसगढ़ के सरगुजा में महाराज साहब के गांव सेनम गांव में मिलती है। सेनम गांव में दोनों मानसून टकराते हैं। बरसात में आप दूसरी फसल लेने की कल्पना नहीं कर सकते। मैं किसान हूं, मैं जानता हूं कि दूसरी फसल ले लें तो इतनी घास वहां निकलती है कि किसान निंदाई करते-करते परेशान हो जाता है। इसलिए बरसात में दूसरा फसल नहीं पुराता। इसलिए यहां बरसात में केवल धान का ही फसल हो सकता है। बरसात के बाद दूसरी फसल ली जा सकती है। लेकिन जो सिंचाई का रकबा है, जिसमें आप मैदान के विषय में कुछ जिलों में सिंचाई है लेकिन हमारे बस्तर, सरगुजा या रायगढ़ जिले में वनांचल है। आप मैदान की बात मत करिये, वनांचल में कौन सी सिंचाई योजना है ? केवल एक फसल के भरोसे पूरे परिवार पालता है और उसी कारण से छत्तीसगढ़ में हमने का है कि बोनस मिलना चाहिए। एक तृतीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बराबर कम से कम उसके पास पैसा आये। यह सोच रही है। जब छत्तीसगढ़ बना, जोगी जी ने अधूरी जानकारी दी। पहले केबिनेट में फैसला हुआ कि सरकार धान नहीं खरीदेगी। चूंकि मैं उसका गवाह हूं इसलिए इस बात को बोल रहा हूं। वासुदेव चंद्राकर जी मुझे फोन किया। बोले, जोगी जी से मिलने का समय निर्धारित करवाईये। हम लोग, रविन्द्र चौबे जी सब लोग गये थे। बोले, आप यदि छत्तीसगढ़ में किसानों का धान नहीं खरीदेंगे तो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाईये फिर से मध्यप्रदेश में मिला दीजिए। यदि छत्तीसगढ़ में किसानों की धान खरीदी नहीं होगी तो कहां होगी ? यह छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद फिर से धान खरीदी का फैसला लिया गया। यह बात सच है कि जब भारत सरकार ने रोक लगाई तो हम लोग दिल्ली गये, 24 अकबर रोड से हम लोग प्रधानमंत्री निवास की तरफ बढ़ रहे थे तो हम सब लोगों को तुगलक थाना रोड के पास गिरफ्तार किया गया। एक वैधानिक संकट उत्पन्न हुई फिर उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हम लोगों को बुलाये बात किये और यह बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने आर.बी.आई. से लोन लेकर फिर धान खरीदी की शुरूआत की और वह व्यवस्था चली आ रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप जब 2014 में आप ही की सरकार के द्वारा यह प्रतिबंध लगाया गया उसके पहले प्रतिबंध नहीं लगाया था। भारत सरकार खुद बोनस देती रही है जिसका मैं उल्लेख कर चुका हूं। लेकिन आपकी पार्टी की सरकार आने के बाद बोनस देना तो दूर, समर्थन मूल्य वृद्धि तो दूर जो सरकार बोनस देती थी उस पर रोक लगाने का काम किया, यह दुर्भाग्यजनक है। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, कोई लोकसभा में पारित नहीं हुआ है, यह एक आदेश खाद्य विभाग की तरफ से निकला है। आप बोनस देंगे तो आपका चावल नहीं खरीदेंगे। हम पासवान जी के पास गये। हमने कहा पिछले दो साल से आप उसमें छूट दिये थे, 2014 में आपने रोक लगा दी, 2015 में नहीं दिया, 2016 में नहीं दिया, 2017 में आपने फिर छूट दी, फिर 2018 में छूट दे दी। दो साल आप छूट दे दिये तो फिर तीसरे साल क्यों छूट नहीं दे रहे हैं? सवाल तो इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। जब दो साल आप

विशेष परिस्थिति में, चाहे आप चुनाव को देख करके करवाया या आपने किसानों के प्रति अचानक आपका मोह, प्रेम जाग गया उस कारण से किया हो। लेकिन दो साल तो छूट मिला है, क्या इस बात से भारतीय जनता पार्टी के लोग इंकार कर सकते हैं, उस दल के लोग इंकार कर सकते हैं । जो सत्ता में बैठे हुए मंत्रिमंडल के सारे लोग यहां अभी बैठे हुए हैं, कुछ लोग तो हैं, क्या इस बात से इंकार कर सकते हैं कि आप ही के प्रयासों से छूट नहीं मिली थी ? जब आपके भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिये विशेष छूट 2017-18, 2018-19 में दिया था तो 2020-21 में क्यों नहीं मिलना चाहिए ? क्या इसलिए कि हमारी सरकारें बदल गयी ? इसकी सजा किसानों को क्यों मिलना चाहिए? अध्यक्ष महोदय, इसीलिए हम पासवान जी से दो बार मिले। उसके बाद प्रधानमंत्री से लगातार पत्राचार करते रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय से खबर आई कि चूंकि विदेश यात्रा में है इसलिए कृषि मंत्री से मिल लीजिए। राष्ट्रपति से भी हमने मिलने का समय मांगा। लेकिन अंतिम समय में वह मीटिंग टल गयी। लेकिन कृषि मंत्री जी ने समय दिया। कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री को हम लोग लेकर गये। वहां खाद्य मंत्री से भी चर्चा हुई और कृषि मंत्री जी से भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हम आपकी बात से सहमत हैं। पासवान जी ने तो बढ़कर कहा कि भूपेश भाई मैं तो 200 प्रतिशत आपकी बात से सहमत हूं। भूपेश भाई, मैं आपकी बात से 200 प्रतिशत सहमत हूँ। मैं 100 प्रतिशत नहीं, 200 प्रतिशत सहमत हूँ। लेकिन आजकल सब काम पी.एम.ओ. से हो रहा है। नहीं तो इसकी छूट देने का अधिकार खाद्य विभाग का है। आपने केन्द्रीयकरण कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम कृषि मंत्री से मिले, हमने कृषि मंत्री से कहा कि आप तो हमारे साथ रहे हैं अविभाजित मध्यप्रदेश के हैं, वहां की परिस्थिति के बारे में जानते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। वहां विशेष परिस्थिति में लोग कृषि कार्य कर रहे हैं और उनको खड़ा करना जरूरी है। जिस प्रदेश में जहां 37 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हो जाएं, 41 प्रतिशत महिलाएं एनिमिया से पीड़ित हैं उस प्रदेश में विशेष परिस्थिति है। हम लोगों को जहां 10 प्रतिशत, आपने स्पेशल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया हुआ है जहां इन प्रदेशों में अनाज का उत्पादन कम होता है ये वही क्षेत्र है। जहां नक्सल प्रभावित है । अब सवाल इस बात का है कि आप उन नवजवानों को हल पकड़ाना चाहते हैं या बंदूक पकड़ाना चाहते हैं। सवाल आज भी वही है। आज बस्तर में बहुत सारे लोग, कृषि का रकबा बढ़ा है मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार से आपके 3 लाख किसानों ने ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाया है। 2 लाख से अधिक एकड़ जमीन का रकबा बढ़ा है। जो लोग कृषि नहीं कर रहे थे, वे लोग खेती की तरफ लौटे हैं। हमने इसीलिए सारे दलों को बुलाया, सब ने राजनीति, इन लोगों ने नहीं की। उन लोगों ने राजनीति नहीं की, वे लोग तो किसान के मामले में आये, माननीय धर्मजीत सिंह जी भी आये थे और माननीय चन्द्रा जी भी आये थे। उन्होंने कहा कि हमारे दल का समर्थन है। राजनीति तो आप कर रहे थे। हमें सूचना नहीं मिली। सांसदों को बुलाये तो चपरासी के द्वारा सूचना मिली। शासकीय सूचना है, आपके पास

पहुंची, पेपर में छप गया, आपके पास सूचना पहुंच गयी, टेलीफोन किया गया और बार-बार असत्य कथन। यदि छत्तीसगढ़ का मामला है दल में नहीं बंटना चाहिए, छत्तीसगढ़ का मामला है छत्तीसगढ़ के किसानों का मामला है सारे जनप्रतिनिधियों को एक होकर आवाज उठाना चाहिए, दिल्ली भी जाना है तो दिल्ली में सबको साथ में काम करना चाहिए। (मेजों की थपथपाहट) आप इसमें राजनीति कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य है हम सांसदों का घेराव नहीं करना चाहते थे। एक प्रतीक है कि आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं। यहां की समस्याओं के बारे में आप आवाज नहीं उठायेंगे तो कौन उठायेगा ? हम क्या उतना भी गुहार नहीं कर सकते हैं? हमने चिट्ठी लिखी, बुलाया। दुनिया भर की बहानेबाजी। हमको सूचना ही नहीं मिली, ये नहीं हुआ। सूचना नहीं मिली फिर आप कैसे आ गये? दूसरे दल के लोग कैसे आये ? आप राजनीति कर रहे हैं। यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी साथियों ने कहा कि आपने घोषणा पत्र में कहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने वर्ष 2013 में किससे पूछकर, घोषणापत्र में शामिल किया था? 2100 रूपये समर्थन मूल्य और 300 रूपये बोनस देंगे। आपने सरकारों से पूछकर किया था? आज हमने कर दिया तो गुनाह कर दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ। हमारी सरकार बन गई है। आपने बोनस नहीं दिया था। हम भी चुप बैठ सकते थे। लेकिन हम आप जैसे हरकत नहीं कर सकते। हम सब लोगों को यह आगाह किये, किसानों को बुलाया, राजनीतिक दल के लोगों को बुलाया (मेजों की थपथपाहट) हम दिल्ली गये, आप कितनी बार गये ? जब वर्ष 2014 में रोक लगाये तब आपने किसको विश्वास ? आप तो चिट्ठी तक दिखाने को तैयार नहीं थे। आप तो उस समय बात करने को तैयार नहीं थे। हमने तो कहा कि यदि आपको रोक लगाया तो आप समय ले लीजिए। हम लोग चलेंगे, पूरे 90 विधायक चलेंगे छत्तीसगढ़ के किसानों का मामला है। तब आप चुप बैठे रहे। आज हम चुप नहीं है। हम बार-बार दिल्ली जा रहे हैं। हम दिल्ली इसलिए जा रहे हैं ये हमारा अधिकार है। ये संघीय व्यवस्था है। ये जो चावल खरीद रहे हैं वह छत्तीसगढ़ सरकार के लिए नहीं है। आपको जो बोलना था आप बोल लिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार एम.एस.पी. घोषित करती है। चावल एफ.सी.आई. चावल एकत्रित करती है। राज्य सरकारें मार्कफेड के माध्यम से उपार्जन करती है भारत सरकार का एक माध्यम है आप घोषित करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कितने राज्यों में समर्थन मूल्य में धान खरीदी कर रहे हैं ? उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र में कर रहे हैं, आप कहां कर रहे हैं? और फिर पंजाब और हरियाणा की तुलना यहां नहीं हो सकती, वहां आप 100 प्रतिशत खरीदी कर रहे हैं, यहां भी एफ.सी.आई. से खरीद लीजिए। हम तो आपसे 2500 रुपये मांग नहीं रहे हैं। हम तो इतना कह रहे हैं कि हम राज्य सरकार के खजाने से 2500 रुपये देंगे, आप तो 1835 रुपये में खरीदिये। उसके हिसाब से आज यह जो

चावल है, आप सत्ता में 15 साल रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम अपने पी.डी.एस. में भी चावल देते हैं तो भारत सरकार एलाट करती है तब हम पी.डी.एस. में चावल आवंटित कर पाते हैं। यह भारत सरकार की योजना है। आप बार-बार क्यों कहते हैं कि आपने घोषणा किया था। किसानों के साथ राजनीति क्यों कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, रमन सिंह जी ने चावल से पेट्रोल बनाने की बात कही। आपके जेट्रोफा का क्या हुआ? डीजल नहीं अब खाड़ी से, डीजल मिलेगा बाड़ी से। अकबर जी ने कहा कि अब डीजल तो नहीं हो रहा है, क्या खाड़ी में वापस जायें?

श्री बृहस्पत सिंह :- वह बायोडीजल से बैलगाड़ी भी नहीं चली।

श्री भूपेश बघेल :- पैरा से पेट्रोल बनाये, उसमें गड़करी जी कल स्कूटी चला रहे थे, कल हमने फोटो देखा। पैरा से इथेनॉल बनाया है, उसमें स्कूटी चला रहे थे। आप तो वह भी नहीं चलाये, सैकड़ों, करोड़ रुपया खर्च कर दिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पासवान जी ने से कहा, कृषि मंत्री जी को प्रस्ताव दिया। हमने परीक्षण कराया है। स्टार्च से बनता ही है। मोलासिस से, गन्ने के रस से, धान से, गेहूं से, मक्का से इथेनॉल बनता है। आपको विश्वास नहीं है, यहां हमने फरवरी में वर्कशॉप किया था। इंडियन ऑयल के लोग आये थे, सारे बैंकर्स आये थे, भारत सरकार की उपसचिव महिला अधिकारी यहां आई थीं। सबके सामने वर्कशॉप किया गया। हमने कृषि मंत्री जी, खाद्य मंत्री जी से यही कहा कि यदि आपके पास सरप्लस अनाज है कि इथेनॉल क्यों नहीं बना देते? दो किलो धान में 1 लीटर इथेनॉल बनता है। स्टार्च से 80 प्रतिशत इथेनॉल बन सकता है, 1 किलो में 80 प्रतिशत आ रहा है। यदि आप औद्योगिक रूप से, व्यावसायिक रूप से करेंगे तो हो सकता है कि 50 प्रतिशत आये, लेकिन उससे कम नहीं नहीं आयेगा। हमने प्राइवेट लैब से परीक्षण करवा लिया, 1 किलो चावल से 80 प्रतिशत तक इथेनॉल निकलता है। बहुत कम होगा तो 50 प्रतिशत होगा, 2 किलो धान से 1 लीटर इथेनॉल बनेगा। हमारे कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री जी से भी कहा। मैं तो पेट्रोलियम मंत्री जी के पास भी गया था। आप पैरा से रेट डिक्लेयर कर दिये, मोलासिस से भी रेट डिक्लेयर कर दिये, अनाज से भी रेट डिक्लेयर कर दीजिए। हमने कृषि मंत्री जी से निवेदन किया। प्लाण्ट डालने के लिए तैयार हैं, यहां लोग प्लाण्ट डालने के लिए आ रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने फिर एक अडंगा लगा दिया। कोई सौ, सवा सौ, डेढ़ सौ करोड़ रुपये का प्लाण्ट डालेगा, उसको केवल एक साल की अनुमति रहेगी। अध्यक्ष महोदय, कोई कैसे प्लाण्ट लगायेगा? हमने इतना आग्रह किया कि 10 साल के लिए अनुमति दीजिए। कितना भी सूखा पड़े, आज अनाज उत्पादन होता ही है, ट्यूबवेल भी है, बांध भी है। फिर भी हम सूखा भी घोषित करते हैं, धान भी खरीदते हैं। आपने भी खरीदा है और हम लोगों ने भी खरीदा है। भविष्य में धान की कमी नहीं होने वाली है। लेकिन इथेनॉल आप बना देंगे तो किसानों को रेट मिल जायेगा, उद्योग भी चलेगा, रोजगार भी मिलेगा और विदेशी धन भी बचेगा। इस बात को आपके मंत्रियों ने स्वीकार किया बिल्कुल आप ठीक कह

रहे हैं। जब ठीक कह रहे हैं तो हमको अनुमति तो दे दीजिए। हम आपके पास गिड़गिडाने नहीं आयेंगे। हम अपने चावल की, धान की व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन अनुमति देने के लिए तैयार नहीं हैं। आपके क्या पत्र लिखा? आप ये कहते हैं कि चावल भंडारण के परिसमापन में गंभीर समस्या उत्पन्न होने की संभावना है । बिल्कुल सही बात है । जितनी जरूरत है यदि उससे ज्यादा उत्पादन हो रहा है तो भंडारण की समस्या तो होगी । लेकिन यदि उसका रास्ता बता रहे हैं तो आपको हंसी छूट रही है । करेंगे क्या, इस चावल को सड़ा देंगे ? और सड़ाने के बाद किसको देते हैं ? शराब फैक्ट्री वाले को । शराब फैक्ट्री वाला एथेनॉल नहीं तो और क्या बनाता है ? वही तो एथेनॉल है । जब शराब फैक्ट्री वाले से बन सकता है तो इससे क्यों नहीं बन सकता ? तो सड़ाने से पहले ही दे दो ना ताकि ऑडिट ऑब्जेक्शन न आए और उससे किसानों को लाभ भी मिल सके । अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा ओ.एम.एस.एस.डी. के माध्यम से चावल के अतिरिक्त स्टॉक का परिसमापन में बहुत कम होता रहा है साथ ही विश्व व्यापार संगठन से कृषि समझौते के मुताबिक सार्वजनिक भंडार से निर्यात भी नहीं किया जा सकता । माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि ऐसा है तो यू.पी.ए. सरकार में दो बार बोनस दिया गया था । आप जब सरकार में थे तब भी आपने बोनस दिया है । इस साल भारत सरकार क्यों नहीं दे रही ? वही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं और इसीलिए आपका समर्थन चाह रहा हूं कि केवल एक लाईन लिखकर दे दें । चावल कौन लेगा? चावल तो भारत सरकार ही लेती है । क्या राज्य सरकारें अपने लिए करती हैं ? पंजाब सरकार क्या चावल अपने लिए उपार्जन करती है, क्या हरियाणा सरकार अपने लिए उपार्जित करती है ? सब भारत सरकार के लिए उपार्जित करते हैं, हम भी कर रहे हैं और आप भी करते थे । यही बात तो मैं कह रहा हूं कि हम भारत सरकार के लिए उपार्जित करते हैं, हम अपने किसानों को यदि अतिरिक्त दे रहे हैं तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए । यदि आप हमको एथेनॉल बनाने की अनुमति दे देते हैं तो 6 महीने में प्लांट लग जाएगा, अगले साल से कोई समस्या नहीं होगी । मैंने रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की, उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया प्रस्ताव है, भेजिए । अध्यक्ष महोदय, सारे लोग बंद कमरे में स्वीकार कर रहे हैं और सारे लोग प्रस्ताव मंगा रहे हैं, मैंने प्रस्ताव भेजा भी है, सबको मेल कर दिया । लेकिन आप क्यों राजनीति कर रहे हैं ? यदि चावल से एथेनॉल बनाने का प्रस्ताव दे रहा हूं तो मैं एक भारतीय हूं और इस देश की चिंता मुझे भी है । आपकी समस्या मेरी समस्या है, इसमें मैं कोई राजनीति से नहीं सोचता । यदि यह सोच रहा होता तो मैं यह प्रस्ताव नहीं देता, क्या चावल का उत्पादन केवल छत्तीसगढ़ में हो रहा है ? यह देश की समस्या है । अनाज के भंडारण की समस्या राष्ट्रीय समस्या है । आज स्थिति क्या है ? यदि इसको ठीक से डिस्पोज़ल किया जाए, यदि गन्ने के रस से बना दिया जाए, हम तो इस दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं । यदि गन्ने के रस से एथेनॉल बनाएंगे तो हम गन्ना उत्पादक किसानों को ज्यादा कीमत दे पाएंगे । अध्यक्ष महोदय, हमारा कहीं यह उद्देश्य नहीं है कि हम

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

इसमें राजनीति करें । मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि हमारे सदस्यों ने बड़ी चिंता जाहिर की कि आपने 1 दिसम्बर से घोषित कर दिया, इसके कारण किसानों को नुकसान हो रहा है । आप तो बोनस भी नहीं देते थे, आपने ऋण माफी भी नहीं किया था । किसान के सिर से कभी बोझा नहीं उतरा था । उसके बाद भी आपने भी 1 दिसम्बर से धान खरीदा, आपने भी 15 नवम्बर से धान खरीदा। आप कैसे भूल जाते हैं कि आपकी सरकार ने 2017-18 में 58 हजार 415 क्विंटल धान जप्त किया था । किससे जप्त किया था ? आपने 2018-19 में 62 हजार 971 क्विंटल धान जप्त किया था, यह किससे जप्त किया था ? आप कर रहे थे तो अच्छा था और हमने किया तो बुरे हो गए । आपकी सरकार ने भी जप्त किया है । लेकिन हमने कहा है कि जो धान बाहर से आ रहा है केवल उसको ही रोकें । जो कोचिये बेच रहे हैं उनको रोकें । यदि किसान आपको ऋण पुस्तिका दिखा दे तो कोई किसान को रोकने वाला नहीं है । हमारे अधिकारियों से हमने कहा है कि यदि ऋण पुस्तिका दिखा दें तो उन्हें जाने दीजिए । लेकिन हमारा प्रदेश 7-8 प्रदेशों से घिरा हुआ है । हमारे चन्द्रा जी कह रहे कि जांजगीर-चांपा में कहां से धान आएगा ? मैं आपको बता रहा हूं मेरे पाटन क्षेत्र की जामगांव सोसायटी में झारखंड का धान पकड़ा गया था । जांजगीर-चांपा से 200 किलोमीटर दूर जाकर मेरे क्षेत्र में पकड़ा गया है, आप ही की सरकार में । वह तो जिसकी जहां सीटिंग होती है तो ट्रक वहां चला जाता है। रातों-रात वहां पहुंच जायेगा। उसमें क्या है? और यह काम आपकी सरकार ने किया हुआ है। 2016 में भी किया, 2017 में भी किया, 2018 में भी किया। मैं तो 2 साल का आंकड़ा भी दे दिया। यह सब लड़ाई इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि यह पैसा छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए है। दूसरे प्रदेश के किसानों की चिंता वहां की सरकारें करें। हमारे पैसे का लाभ दूसरे प्रदेश के बिचौलिये, कोचिये, व्यापारी न उठा पाये। बृजमोहन जी कह रहे थे। दुकानदारों के यहां जब्ती बना रहे हैं। गोदाम बना रहे हैं। चन्द्रा जी कर रहे हैं कि किसानों के यहां कोठी भी नहीं है। दोनों बातों में बिल्कुल विरोधाभास है। तो व्यापारी के यहां ही तो हो रहा है। अब सवाल इस बात का है कि चार क्विंटल की आपकी सीमा है। यह कानून बना था। आप 15 साल तक थे। आप क्यों नहीं बदले? मैं इस सदन के माध्यम से कह रहा हूं कि 4 क्विंटल से बढ़ाकर 10 क्विंटल किया जाना चाहिए। (मेजों की थपथपाहट) व्यापारी के पास धान रखने की क्षमता 10 क्विंटल होना चाहिए। उनको भी परेशानी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। व्यापारी 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो धान बेचने आता है, व्यापारी के पास रहता है। मंडी शुल्क पटा दें। कोई दिक्कत कहां है? लेकिन आप किसी नियम का पालन ही नहीं करेंगे। नियम तो सभी ने बनाया है। आपके समय बना। उसके पहले भी बना। अभी हम कोई नया नियम तो नहीं बनाये हैं। उसी नियम के हिसाब से चल रहे हैं। अब उसमें कार्रवाई हो रही है। हो सकता है। जैसे अभी नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे थे कि 8 ट्रेक्टर खड़ी हुई है। वह अपना ऋण पुस्तिका दिखा दे और ले जाये।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- मुख्यमंत्री जी, नहीं छोड़ रहे हैं। ऋण पुस्तिका लेकर किसान गया। मंडी सेक्रेटरी के पास गया। कलेक्टर के पास गया।

श्री भूपेश बघेल :- आपके जिले के कलेक्टर से मैंने खुद बात की है। मैंने कहा 24 घण्टा हो गया है..।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं स्वयं कलेक्टर के पास गया था। कलेक्टर ने मना कर दिया।

श्री भूपेश बघेल :- चलिए, मैं भी बात कर लिया हूं। अब ऋण पुस्तिका दिखा दीजिए। ले जाइए। ऋण पुस्तिका नहीं दिखाएगा तो किसान कैसे माना जायेगा? मेरे पास पूरे जिलेवार आंकड़े हैं। यदि आप कहें तो मैं उसका वाचन कर देता हूं। सबसे ज्यादा सीमावर्ती क्षेत्र में और कवर्धा में तो और भी बहुत ज्यादा है। खूब पकड़ में आ रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- कवर्धा में यदि है तो इधर वाला है या पीछे वाला है। कौन करवा रहा है?

श्री भूपेश बघेल :- ये यहां के जनप्रतिनिधि हैं। वो उनका निवास है। उनका गृह जिला है।

श्री अजय चन्द्राकर :- तो करवा कौन रहा है?

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- दोनों के सहयोग से ही होता है। (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- अब सवाल इस बात का है कि आज किसानों को नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि पूरा सदन इससे सहमत होगा, लेकिन अध्यक्ष महोदय, यदि हमने 2500 रूपये सीधे दे दिया तो भारत सरकार हमारा चावल नहीं खरीदेगा। तो क्या यह चावल हम मैदान में रखकर सड़ायें। अनाज का इतना अपमान क्या यह सदन बर्दाश्त कर पायेगा। हमारी जितनी क्षमता है, हम जितना पी.डी.एस. में लगाते हैं, उतना तो हमको चाहिए। उतना हम खपा लेंगे। बचे हुये चावल का क्या होगा? अगर भारत सरकार नहीं खरीदी, तब क्या होगा? चावल तो हम लोग उसी के लिए खरीदते हैं। आपसे इतना ही निवेदन है कि जब आप 2 साल छूट दे दिये तो इस साल भी छूट दीजिए और इसके लिए आपसे समर्थन मांग रहे हैं तो कौन सा अपराध कर रहे हैं। आपके सांसदों से कह रहे हैं कि आप अपने प्रधानमंत्री से कहिए। इस प्रदेश की समस्या है। एक लाइन की बात है। जब 2017, 2018, 2019 में आपने छूट दिया तो इस समय भी छूट दे दीजिए। यह बात कहने में आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? लेकिन इसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि किसान के जेब में 2500 रूपये जाएगा। (मेजों की थपथपाहट) न्याय होगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, आपका भी धान 2500 रूपये में खरीदेंगेग।

श्री भूपेश बघेल :- हम आग्रह कर रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं। केन्द्र सरकार से क्यों लड़ेंगे ? लेकिन हम बात भी नहीं कर सकते। आप जैसे चुप नहीं रह सकते। आप तो 2014 में चिट्ठी आयी, उसके बाद मौन साध लिये। न जनता पर, न किसानों पर विश्वास किया, न जनप्रतिनिधि पर विश्वास किया और न

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ही राजनीतिक दलों पर विश्वास किया। आप लेकर चलते तो उसी समय किसानों को 300 रूपये मिलना शुरू हो गया होता। आज हम वह काम कर रहे हैं। राजनीतिक दलों और किसानों को साथ में ले रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) चलिए, हम तो 15 तारीख को जाने वाले थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसके कारण निर्णय बदलना पड़ा । 15 लाख से अधिक किसानों के हस्ताक्षरयुक्त पत्र आ गए हैं। इनको तो फर्जी लगता है। किसान ही नहीं, व्यापारी तक हस्ताक्षर किए हैं। क्यों ? क्योंकि किसानों को 2500 रूपया क्विंटल धान का दाम मिलने से लोगों को व्यापार में भी लाभ हुआ है। (मेजों की थपथपाहट) यह एक मात्र प्रदेश है, आपकी नीति से देश में आटोमोबाइल सेक्टर भरस्ट हो गया है, बैठ गया है, उसमें 19 प्रतिशत की गिरावट आई है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने ऋण माफी और 2500 रूपये क्विंटल में धान खरीदा तो असर यह हुआ कि मार्च महीने में आटोमोबाइल सेक्टर में 36.5 प्रतिशत का ग्रोथ हुआ है। 84 प्रतिशत सराफा के व्यापार में वृद्धि हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं कपड़ा वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। रियल स्टेट के व्यापार के आकड़ें निकालकर देख लीजिये कि जून 2018 से सितम्बर, 2019 तक के आकड़ें देखे। आपके समय में केवल 92 करोड़ रूपया आया था, लेकिन हमारे समय में 152 करोड़ रूपये की रजिस्ट्री हुई है, असर यह है। तो आप इसको रोकना क्यों चाहते हैं ? आपकी किसानों की दुश्मनी क्यों है ? राज्यपाल महोदया ने पत्र लिख दिया, हम उनको धन्यवाद देते हैं। आप भी प्रधानमंत्री जी से एक बार आग्रह कर लीजिये। मैं अभी भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि आप एक बार प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख दीजिये, आप हमारे साथ चलिये और छत्तीसगढ़ के किसानों के हक में बात करिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात कि धान खरीदी में विलंब क्यो हुआ ? अध्यक्ष महोदय, आप सब जानते हैं, सबके पास रिकार्ड है। जून महीने में पानी ही नहीं गिरा, बुआई लेट हुआ है, अगस्त तक तो रोपाई हुआ है। आखिरी सितम्बर तक रोपाई होता रहा। 25 अक्टूबर तक तो पानी गिरता रहा है, दीपावली के पहले तक पानी गिरता रहा है तो 01 नवम्बर से कहां से धान की खरीदी शुरू कर दें ? मैं भी तो किसान हूँ, मेरे खेत में भी हार्वेस्टर नहीं जा पा रहा है। मैं भी तो किसानी कर रहा हूँ, मजदूर लगाकर लुआई कर रहे हैं। हार्वेस्टर नहीं जा पा रहा है, खेत में ट्रेक्टर घुस नहीं पा रहा है। आप जो कह रहे हैं , मुझे छत्तीसगढ़ की जनता का आर्शीवाद मिला है मैं आजकल हेलीकाप्टर में जा रहा हूँ, मैं आपके यहां देख रहा हूँ कि वहां खरही गंजाया हुआ है। खेत से धान नहीं ला पा रहे हैं, ट्रेक्टर जा ही नहीं पा रहा है तो खेत में ही खरही गांज दिए हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है कि आपके खेत में ट्रेक्टर नहीं जा रहा है, ठीक है। आजकल कीचड़ में, गीले खेत में भी चलने वाला हार्वेस्टर आ गया है। आजकल बाजार में नहीं मिल रहा है, आप उसमें

सब्सिडी की घोषणा कर दीजिये। 2500 रूपये के साथ-साथ किसानों की घोषणा हो जायेगी कि हार्वेस्टर के लागत के 50 प्रतिशत की घोषणा करते हैं।

श्री भूपेश बघेल :- चलिये, आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। कृषि मंत्री जी ने कहा कि बिलकुल विचार किया जायेगा। अजय जी, आप छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में बात करेंगे तो हम क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। अच्छा सुझाव दीजिये, हम क्यों नहीं करेंगे ? (मेजों की थपथपाहट) लेकिन हम वही कह रहे हैं कियदि छत्तीसगढ़ सरकार कोई अच्छा सुझाव दे रही है तो भारत सरकार क्यों चुप है ? उनको भी स्वीकार करना चाहिए।

आज इस बात का कि चावल का सेटल कैसे करें ? 32 लाख मीट्रिक टन से अधिक चावल हमारे यहां बचेगा। हमने पिछले साल 75 लाख मीट्रिक टन धान का लक्ष्य रखा था और 80 लाख मीट्रिक टन खरीदे थे। हमने इस साल लक्ष्य बढ़ाया है इस साल 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। तो यह तो बढ़ने ही वाला है, कम होने वाला नहीं है, बढ़ेगा ही। तो हमारा चावल बचेगा ही, धान बचेगा ही। हम इसको सड़ा नहीं सकते। हमने किसान से वादा किया है, हम किसान को देकर रहेंगे। किसान के जेब में पैसा जाना चाहिए। आपका केवल इतना ही न, आप अहंकार की बात कर रहे थे। मैं आपके अहंकार को प्रणाम करता हूँ। आपके केन्द्र सरकार के अहंकार को भी प्रणाम करता हूँ। हम वहां केवल 1835 और 1815 रूपया ही लिखेंगे, लेकिन किसानों के साथ न्याय होगा। हम और दूसरी योजना लायेंगे और उसके माध्यम से किसानों की जेब में, किसानों के खाते में पैसा डालने का काम करेंगे। उसके लिए समिति बनेगी, जिसमें कृषि मंत्री जी रहेंगे, खाद्य मंत्री जी भी रहेंगे, सहकारिता मंत्री भी रहेंगे और अकबर जी भी रहेंगे, उमेश पटेल जी भी रहेंगे। यह मैं सदन में घोषणा कर रहा हूँ। किसानों के साथ न्याय होगा, हम न्याय करके रहेंगे । हम सोसायटियों में 1815 लिख देंगे । भारत सरकार ने समर्थन मूल्य किया है तो आपके अहंकार की संतुष्टि हो जाएगी। आपके अहंकार की तुष्टि हम कर देंगे कि केवल 1835 रूपये में खरीद रहे हैं, लेकिन किसान को तो पैसा चाहिए न, हम देंगे । (मेजों की थपथपाहट) उसके लिए समिति बना देंगे, वे दूसरे राज्य जाएंगे, अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से दिए हैं और वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी देंगे, लेकिन किसी किसान को 25 सौ रूपये से कम नहीं मिलने देंगे । (मेजों की थपथपाहट) उनको मिलेगा । यह पैसा छत्तीसगढ़ के किसानों का है । कमीशनखोरी के लिए नहीं है, दलाली के लिए नहीं है, कोचिया लोगों के लिए नहीं है । हम 1 तारीख को बैनर टांग देंगे । अब आप खुश हो गए, आपके नेता खुश हो जाएंगे ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा निचोड़ ये था कि 1 दिसम्बर और 15 नवम्बर और इसके बाद 25 सौ रूपये है तो 25 सौ रूपये में देंगे, उसमें किसानों के लिए अहसान नहीं है, हमारे लिए अहसान नहीं है । आपकी घोषणा है तो आपको देना पड़ेगा । रही

सवाल तो पूरी चर्चा के बाद में आज भी मुख्यमंत्री जी अडिग हैं और अड़े हुए हैं कि 1 दिसम्बर से खरीदी करेंगे तो पूरे स्थगन में चर्चा करने का क्या फायदा ? आपके कथन से हम असंतुष्ट हैं और हम बहिर्गमन करते हैं । (हंसी)

समय :
6:21 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में</u>

(श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

श्री बृहस्पत सिंह :- किसान विरोधी पार्टी है। छत्तीसगढ़ के धोखेबाज हैं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑन लाईन के आधार पर पंजीयन में कटौती कर रहे हैं । जो किसान पंजीयन करा चुके हैं, पिछले साल भी पंजीयन करा चुके हैं, ऑन लाईन राजस्व विभाग की कमी है, उसके कारण दो दिनों से मुझे सूचना मिल रही है कि पंजीयन में किसानों के रकबे की कटौती की जा रही है । इस ओर भी ध्यान देंगे ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, आप भी किसान हैं, हम लोग सब पूरे किसान परिवार के हैं । हम लोगों की ऋण पुस्तिका में देखेंगे तो मान लो कि रकबा 18 एकड़ है, लेकिन यदि हम वास्तव में धान की खेती कर रहे हैं तो 15 एकड़ हो सकता है, कुछ भांठा, ब्यारा हो सकता है, कुछ पड़त हो सकती है, कुछ बगीचा हो सकती है । कोई तालाब भी हो सकता है तो उसका धान हम नहीं खरीदेंगे । वास्तविक रूप से जिन्होंने जितना रकबा वे बोये हैं, उसी का धान हम खरीदेंगे । नहीं तो कोचिये लोग फिर शुरू हो जाएंगे । यदि आपके पास कोई शिकायत है..

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अध्यक्ष महोदय, जो रकबा है, आप वही खरीदिए, लेकिन ऑन लाईन नहीं हुआ है, उसके कारण रकबा की कमी कर रहे हैं । जो धान की फसल लगाये हैं, उसी को आप खरीदिए । हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अधिक को खरीदिए ।

श्री भूपेश बघेल :- आप उसको दे दीजिए, हम उसको सुधरवा लेंगे, उसकी जांच करा लेंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आदिवासी अंचल में जहां पर कम्प्यूटर वगैरह की व्यवस्था नहीं है, वहां पर भी थोड़ा गैर कानूनी तरीके से उनको दबाने की कोशिश हो रही है और मंदिर और ट्रस्ट की जमीन का भी बता दीजिए ।

असंशोधित/मुद्रण हेतु नहीं

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, धर्मजीत जी ने बहुत सही सवाल उठाया है और चंद्रा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों की चिन्ता व्यक्त करते हुए जो व्यवहारिक कठिनाई है, हम उसको दूर कर लेंगे, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो मंदिर और ट्रस्ट का मामला है, उस मामले में हम लोगों ने मंत्रिमण्डल में अनेक बार चर्चा की और भारत सरकार के द्वारा इस पर रोक लगाया गया है क्योंकि मंदिर ट्रस्ट है, मठ है, वह इंडीव्यूजवल नहीं है । हम किसानों का धान खरीदते हैं, वह इंडीव्यूजवल का है और इसलिए उसका धान सोसायटियों के माध्यम से नहीं खरीदा जाएगा, भारत सरकार के निर्देश के कारण से यह हुआ है । छत्तीसगढ़ सरकार तो खरीदना चाहती है, मेरे पास बहुत सारे मठ-मंदिर के लोग आये थे, मैंने उनको आश्वस्त किया था कि इसमें कोई न कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन भारत सरकार ने यह अडंगा लगा हुआ है, इस कारण ये यह संभव नहीं हो पाया है। यदि वे अधिया-रेगहा दिए हुए हैं और किसानों के नाम से पंजीयन कराते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन वह मठ के नाम से है, वे खेती कर रहे हैं तो उसका लाभ नहीं मिल पाएगा । हम भारत सरकार से एक बार आग्रह करेंगे, जो आपने कहा है । एक पत्र भारत सरकार के मामले में लिख देंगे । सभी साथियों ने जो समय दिया और आपने मुझे समय दिया, उसके लए मैं धन्यवाद देते हुए पुन: इस बात को रेखांकित करता हूं कि किसानों के साथ न्याय होगा, किसानों के जेब में 25 सौ रूपये जाएगा । किस प्रकार से जाएगा, उसके लिए मैंने कृषि मंत्री जी, खाद्य मंत्री जी, सहकारिता मंत्री जी, वन मंत्री जी और उच्च शिक्षा मंत्री जी की मंत्रिमण्डल की उप समिति की मैं घोषणा करता हूं । यह विभिन्न राज्यों में किस प्रकार से दिया जा रहा है, भारत सरकार भी जो किसान सम्मान निधि दे रही है, उसका भी अध्ययन कर लें, यह सब अध्ययन करके, मंत्रिमण्डल के सामने रखेंगे, किसानों को हर हालत में उसका लाभ मिलेगा, इस बात की घोषणा करते हुये, आपने जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी । सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 26 नवम्बर, 2019 को 11:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित ।

(6 बजकर 26 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 26 मार्च 2017 (अग्रहायण 5, शंक संवत 1941) के पूर्वान्ह 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।)

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक 25 नवम्बर, 2019